•वर्ष-5
•अंक-232
रायपुर, शनिवार 16 मई 2026
•पृष्ठ-8
•मूल्य-3 रु.

।। संगच्छध्वम् संवदध्वम् ।।

समाचार पचीसा

राजनीति का जनपक्षकार

पेज-8> वनांचल क्षेत्र का विकास हमारी...

मोदी ने ब्रदर बोलकर लूट ली यूएई की महफिल, ईरान दंग, ट्रंप परेशान

यूएई भारत में 5 अरब डॉलर रुपये का निवेश करेगा

नईदिल्ली। दुनिया की नजरें इस वक्त ट्रंप के चीन दौरे पर टिकी हुई है। अमेरिका और चीन के बीच चल रही टकराहट पूरी दुनिया की सुर्खियां बनी हुई है इस वक्त। लेकिन इसी बीच बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अचानक एक ऐसा बड़ा दांव चल दिया है जिसने चीन में बैठे ट्रंप तक को हिला कर रख दिया है। हैरान कर दिया है और पूरी दुनिया में बेचैनी बढ़ा दी है। हालात ये हैं कि इस वक्त ट्रंप के चीन दौरे से ज्यादा चर्चा हो रही है पीएम मोदी की पांच देशों की यात्रा की। ऐसे में अब सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या होने जा रहा है? क्यों दुनिया के बड़े देश अचानक भारत की तरफ देखने लगे हैं और कैसे पीएम मोदी दुनिया में फैले सबसे बड़े संकट को भारत के लिए सबसे बड़े मौके में बदलने की तैयारी कर रहे हैं। दुनिया में फैलते संकट के बीच भारत की सबसे बड़ी रणनीतिक तैयारी मानी जा रही है।

क्योंकि बता दें कि इस वक्त पूरी दुनिया जिस चीज से सबसे ज्यादा डर रही है और वो ऊर्जा संकट है और पीएम मोदी संयुक्त अरब अमीरात के दौरे पर पहुंचे हैं।

यूएई में पीएम मोदी ने कहा कि ब्रदर इस आत्मीय स्वागत के लिए मैं आपका हृदय से बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं और जैसा आपने कहा मैं अपने दूसरे कराया ये शब्द ये भाव मेरे जीवन की बहुत बड़ी पूंजी है आज भी जिस प्रकार से आपकी वायु सेना के जहाजों ने किया। ये भारत के लोगों का सम्मान है। आपने पिछले दिनों प्राकृतिक आपदा के कारण कुछ इलाकों में जो परेशानियां आई उन पीड़ित परिवारों के लिए संवेदना व्यक्त की। इसके लिए भी मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूं। वेदर पिछले कुछ समय से आपसे फोन पर तो बात होती रहती थी परंतु मैं स्वयं आपसे मिलने के लिए बहुत ही बेता आता पता नहीं क्यों लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे जितना हो सके उतना जल्दी आपके पास आना चाहिए आपको मिलना चाहिए आज आपसे मिलकर के मुझे सचमुच बहुत खुशी हुई है ब्रदर जैसा मैंने आपको पहले भी कहा है यूएई पर हुए हमलों की हम कठोर निंदा करते हैं यूएई को जिस तरह निशाना बनाया गया है ये किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है ब्रदर इन कठिन परिस्थितियों में आपने जिस संयम करेज और विल का परिचय दिखाया है। यह बहुत ही सराहनीय है। राष्ट्रीय एकता सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखने आपके नेतृत्व में उठाए गए कदमों का हम अभिनंदन करते हैं।

पीएम मोदी ने कहा कि कठिन समय यूएई में रहने वाले भारतीय समुदाय की चिंता करने और उनकी देखभाल की जिस प्रकार से आपने उनको अपने परिवार के सदस्यों को संभाला है। मैं भी सरकार का आपका रॉयल फैमिली का हृदय से बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं। ब्रदर पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव आज पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी पर प्राथमिकता दी है। और उसको फ्री ओपन और सेफ बनाए रखना ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इस विषय में अंतरराष्ट्रीय कानूनों का पालन आवश्यक है।

अगले साल से ऑनलाइन होगी नीट: शिक्षामंत्री

दिल्ली। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) ने मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट-यूजी को लेकर बड़ा फैसला लिया है। पेपर लीक के आरोपों और देशभर में छात्रों के विरोध के बाद अब नीट-यूजी की परीक्षा 21 जून को आयोजित की जाएगी।

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दिल्ली में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी आधिकारिक घोषणा की। उन्होंने कहा कि अगले साल से हृश्वश्वञ्ज एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड होगा। छात्रों के भविष्य और परीक्षा की

पारदर्शिता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। इस फैसले के बाद लाखों छात्रों को दोबारा परीक्षा की तैयारी करनी होगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शिक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार छात्रों की मेहनत और उनके सपनों के प्रति पूरी तरह संवेदनशील है। किसी भी योग्य छात्र के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। सरकार का उद्देश्य निष्पक्ष और पारदर्शी परीक्षा प्रणाली सुनिश्चित करना है। शिक्षा मंत्री ने बताया कि नीट परीक्षा 3 मई को आयोजित की गई थी। इसके बाद 7 मई तक एनटीए की शिकायत निवारण प्रणाली के माध्यम से कई शिकायतें सामने आईं। छात्रों और अभिभावकों ने आरोप लगाया कि कथित 'गेस पेपर' में दिए गए कुछ प्रश्न मुख्य प्रश्नपत्र से मेल खाते थे।

पुणे से मास्टरमाइंड कुलकर्णी गिरफ्तार

सीबीआई ने नीट-यूजी 2026 परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक के सरगना की पहचान कर ली है। सीबीआई ने बताया कि जांच में पता चला है कि एनटीए की ओर से परीक्षा प्रक्रिया में शामिल रसायन विज्ञान के लेक्चरर पी.वी. कुलकर्णी के पास प्रश्नपत्रों की पहुंच थी। अप्रैल 2026 के अंतिम सप्ताह में, उन्होंने एक अन्य आरोपी मनीषा वाघमारे की मदद से छात्रों को संगठित किया और पुणे स्थित अपने आवास पर इन छात्रों के लिए विशेष कोचिंग कक्षाएं आयोजित कीं। सीबीआई के मुताबिक इन विशेष कोचिंग कक्षाओं के दौरान उन्होंने प्रश्न, विकल्प और सही उत्तर लिखवाए। छात्रों ने इन प्रश्नों को अपनी नोटबुक में हाथ से लिखा और ये प्रश्न 3 मई 2026 को आयोजित नीट-यूजी 2026 परीक्षा के वास्तविक प्रश्नपत्र से हूबहू मेल खाते हैं।

नीट-यूजी की परीक्षा अब 21 जून को

दिल्ली। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) ने मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट-यूजी को लेकर बड़ा फैसला लिया है। पेपर लीक के आरोपों और देशभर में छात्रों के विरोध के बाद अब नीट-यूजी की परीक्षा 21 जून को आयोजित की जाएगी।

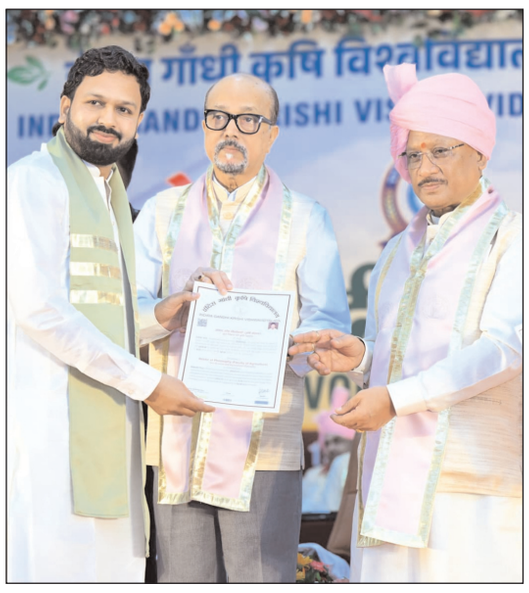

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दिल्ली में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी आधिकारिक घोषणा की। उन्होंने कहा कि अगले साल से नीट एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड होगा। छात्रों के भविष्य और परीक्षा की पारदर्शिता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। इस फैसले के बाद लाखों छात्रों को दोबारा परीक्षा की तैयारी करनी होगी।छात्रों के भविष्य को बताया सर्वोच्च प्राथमिकता

रायपुर। राज्यपाल रमेन डेका एवं कुलाधिपति इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर ने विश्वविद्यालय के 11वें दीक्षांत समारोह में यह बात कही। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय और विशिष्ट अतिथि के रूप में कृषि मंत्री राम विचार नेताम और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली के पूर्व निदेशक और प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉ. अशोक कुमार सिंह उपस्थित थे । इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर के सभागार में आयोजित भव्य एवं गरिमामय दीक्षांत समारोह में शैक्षणिक वर्ष 2024-25 में उत्तीर्ण छात्र-छात्राओं को पदक एवं उपाधियां वितरित की गई। विभिन्न संकायों में प्रावीण्य सूची में स्थान प्राप्त करने वाले मेधावी विद्यार्थियों को 13 स्वर्ण, 7 रजत एवं 2 कांस्य पदक सहित 128 शोधार्थियों को पी.एच.डी, 518 विधार्थियों को स्नातकोत्तर और 1234 विधार्थियों को स्नातक उपाधि प्रदान की गई। ›› विस्तृत समाचार पेज-3 पर

अमित शाह की अध्यक्षता में 19 मई को बस्तर में होगी बैठक

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने

■ **सीएम विष्णुदेव ने हाई लेवल मीटिंग लेकर तैयारियों की समीक्षा की**

आज मंत्रालय महानदी भवन में बस्तर में आयोजित होने वाली मध्य क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक की तैयारियों को लेकर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। यह महत्वपूर्ण बैठक केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आयोजित होगी, जिसमें मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री शामिल होंगे।

बैठक के दौरान अधिकारियों ने प्रस्तुतीकरण (पीपीटी) के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा परिषद की बैठक में उठाए जाने

वाले विभिन्न विषयों की जानकारी मुख्यमंत्री को दी। मुख्यमंत्री ने सभी बिंदुओं की विस्तार से समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए।

मुख्यमंत्री साय ने वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों को विभिन्न जिम्मेदारियां सौंपते हुए निर्देश दिए कि आयोजन की तैयारियों में किसी प्रकार की कमी न रहे और सभी व्यवस्थाएं गंभीरता एवं समन्वय के साथ सुनिश्चित की जाएं।मुख्यमंत्री साय ने कहा कि विकसित भारत के निर्माण में मध्य क्षेत्रीय परिषद के राज्यों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि यह परिषद देश की ऐसी क्षेत्रीय परिषद है जहां सदस्य राज्यों के बीच किसी प्रकार का विवाद नहीं है, जो आपसी सहयोग और समन्वय का उत्कृष्ट उदाहरण है। उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय परिषदें राज्यों तथा केंद्र और राज्यों के बीच विभिन्न विषयों पर संवाद, सहयोग और समन्वय को मजबूत करने का प्रभावी मंच बन चुकी हैं।मुख्यमंत्री ने कहा कि मजबूत राज्य ही मजबूत राष्ट्र का निर्माण करते हैं और इसी भावना के साथ क्षेत्रीय परिषदें विकास, प्रशासनिक समन्वय और राष्ट्रीय एकता को नई दिशा प्रदान कर रही हैं। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में इन परिषदों ने राज्यों के बीच स्वस्थ सहयोग और विकासोन्मुखी सोच को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।मुख्यमंत्री साय ने कहा कि बस्तर में इस महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन प्रदेश के लिए गौरव का विषय है। उन्होंने कहा कि बस्तर में शांति स्थापना के बाद इस स्तर की राष्ट्रीय बैठक का आयोजन यह दर्शाता है कि राज्य सरकार क्षेत्र के विकास और नई संभावनाओं को लेकर पूरी तरह संकल्पित है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के नेतृत्व में नक्सल उन्मूलन से क्षेत्र में शांति स्थापित हुई है।

प्रमुख समाचार

जिसे जाना है जाए, मैं नए सिरे से पार्टी का गठन करूंगी: ममता

कोलकाता । तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी ने पार्टी के हारे हुए प्रत्याशियों को साफ कहा है कि उनमें से जो भी जाना चाहता है, वह जा सकता है। वे नए सिरे से पार्टी का गठन करेंगी। ममता ने शनिवार को कालीघाट स्थित अपने घर पर हारे प्रत्याशियों के साथ बैठक की। ममता पार्टी नेताओं व कार्यकर्ताओं से हिम्मत न हारते हुए नए सिरे से लड़ाई का पहले ही आह्वान कर चुकी हैं। उन्होंने आगे कहा-जो लोग साथ हैं, वे टूटे हुए पार्टी कार्यालय को ठीक करें। रंग-रोगन करके फिर से खोलें। जरूरत पड़ी तो मैं खुद भी रंग करूंगी। तृणमूल कभी सिर नहीं झुकाएगी। जनता का फैसला लूटा गया है। बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी भी मौजूद थे। इससे पहले गत पांच मई को भी संवाददाता सम्मेलन कर ममता ने कहा था-मैं जानती हूं, कई लोग दूसरी पार्टी में चले जाएंगे। शायद उनकी मजबूरी हो। मुझे इसमें कुछ कहने को नहीं है। जो जाना चाहता है, जाए। मैं जबरदस्ती रोकने के पक्ष में नहीं हूं।

कोई सैन्य समाधान नहीं, गंभीरता से बातचीत करें: अराघची

नई दिल्ली। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होने आए ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने अमेरिका पर सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने कहा कि ईरान के पास अमेरिका पर भरोसा न करने के कई कारण हैं, जबकि अमेरिकियों को ईरान पर पूरा भरोसा करना चाहिए।उन्होंने दोनों देशों के बीच चल रही बातचीत में मुख्य बाधा को भरोसे की कमी बताया। अराघची के अनुसार, ईरान के खिलाफ युद्ध में कोई लक्ष्य हासिल न हो पाने के बाद अमेरिका ने बातचीत का प्रस्ताव रखा है। उन्होंने जोर देकर कहा, हमें अमेरिकियों पर कोई भरोसा नहीं है। यही कूटनीतिक प्रयासों की राह में सबसे बड़ी बाधा है। विदेश मंत्री ने कहा कि दुश्मनी के बावजूद फिलहाल एक कमजोर सीजफायर लागू है क्योंकि ईरान कूटनीति को मौका देना चाहता है। ईरान सिर्फ सम्मान की भाषा का जवाब देता है। हम किसी दबाव, धमकी या प्रतिबंध के आगे नहीं झुकते है। अमेरिका ने बार-बार हमारी परीक्षा ली है।

अमेरिका सच में गिरता हुआ देश बन गया था: ट्रंप

नई दिल्ली। वाशिंगटन से लेकर बीजिंग तक उस वक्त हलचल मच गई, जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुले मंच से मान लिया कि कुछ समय पहले तक अमेरिका सच में गिरता हुआ देश बन चुका था। हैरानी की बात यह रही कि ट्रंप ने यह बात चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग की टिप्पणी पर सहमति जताते हुए कही। ट्रंप ने साफ शब्दों में कहा कि अगर शी चिनफिंग ने अमेरिका को पतनशील राष्ट्र कहा, तो वह बाइडन सरकार के चार सालों की तबाही की तरफ इशारा था और उस बात से वह 100 प्रतिशत सहमत हैं।

ट्रंप ने इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म पर कहा कि जो बाइडन की नीतियों ने अमेरिका को भीतर तक कमजोर कर दिया था। उन्होंने आरोप लगाया कि खुली सीमाओं ने अवैध घुसपैठ बढ़ाई, ऊंचे टैक्स ने अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचाई, अपराध तेजी से बढ़ा और डीईआइ जैसी नीतियों ने देश की व्यवस्था बिगाड़ दी।

मरणोपरांत गोवा कांग्रेस नेता की याचिका का सुको में निपटारा

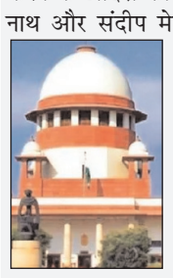

नई दिल्ली। गोवा कांग्रेस नेता केतन भाटीकर की सांप के काटने से मृत्यु के एक दिन बाद सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उनकी याचिका का निपटारा कर दिया है। याचिका में भाटीकर ने बांबे हाई कोर्ट के पोंडा विधानसभा उपचुनाव को रद करने के आदेश को चुनौती दी थी।जस्टिस विक्रम नाथ और संदीप मेहता की पीठ ने भाटीकर की मृत्यु की जानकारी मिलने के बाद उनकी याचिका पर कार्यवाही को समाप्त कर दिया। भाटीकर (38) कर्नाटक के डंडेली गांव की ओर जा रहे थे, जब उनकी मृत्यु हुई।मृतक नेता के लिए उपस्थित अधिवक्ता अभिषेक जेबराज ने पीठ से अनुरोध किया कि वह कार्यवाही को बंद कर दें। पीठ ने दोनों पक्षों की प्रस्तुतियों को दर्ज किया और याचिका पर कार्यवाही को समाप्त कर दिया। पोंडा विधानसभा सीट के लिए विपक्षी पार्टी कांग्रेस के उम्मीदवार रहे भाटीकर ने 8 अप्रैल को बांबे हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसने उपचुनाव को रद कर दिया था।

एमएसपी में मामूली बढ़ोतरी किसानों को लूटा: केजरीवाल

नईदिल्ली। आम आदमी पार्टी ने शुक्रवार को पेट्रोल, डीजल और सीएनजी की कीमतों में हालिया बढ़ोतरी को लेकर भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। पार्टी का आरोप है कि धान के न्यूनतम समर्थन मूल्यमें मामूली वृद्धि के बावजूद इस बढ़ोतरी से किसानों और आम जनता पर और बोझ पड़ेगा। पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने केंद्र पर धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य में मामूली वृद्धि की घोषणा के एक दिन बाद ईंधन की कीमतें बढ़ाकर किसानों को लूटने का आरोप लगाया। एक्स पर एक पोस्ट में चीमा ने कहा कि केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपये प्रति लीटर की वृद्धि की, जबकि धान के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में केवल 72 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ने किसानों को नाममात्र का एमएसपी बढ़ाकर और फिर अगले ही दिन डीजल की कीमतें बढ़ाकर उन्हें उनके हक के मुआवजे से वंचित कर दिया है।

बंगाल में वैचारिक विष से मुक्ति का युद्ध

तरुण विजय

शुभेंदु अधिकारी उन गिने-चुने राजनेताओं में से हैं, जिन्होंने विनम्रता, वैचारिक प्रतिबद्धता, हिंदू गौरव के प्रति निडर रुख और विकास की एक स्पष्ट दृष्टि दिखाई है। हालांकि मैं उनसे कभी मिला नहीं हूं, लेकिन मुझे लगता है कि वह डा. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की विरासत के सच्चे उत्तराधिकारी हैं। शायद बहुत से लोगों को याद न हो कि बंगाल में 1941 में पहली बार 'केसरिया गठबंधन' वाली सरकार बनी थी, जिसे 'श्यामा-हक सरकार' कहा जाता था।

डा. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 'हिंदू महासभा' ने ए.के. फजलुल हक की 'कृषक प्रजा पार्टी' (के.पी.पी.) के साथ गठबंधन किया था। उस सरकार में हिंदू महासभा के चार और के पी पी के पांच मंत्री थे, जिसमें मुखर्जी वित्त मंत्री और हक मुख्यमंत्री थे। उस गठबंधन के 85 साल बाद, आज पहली बार किसी हिंदुत्ववादी राष्ट्रवादी पार्टी ने बंगाल में बिना किसी सहयोगी के, अपने दम पर सरकार बनाई है। अब शासन की कमान पूरी तरह से श्यामा प्रसाद मुखर्जी के अनुयायियों के हाथ में है। इन आठ दशकों में बंगाल ने कई भारी उतार-चढ़ाव देखे हैं कलकत्ता का 'डायरैक्ट एक्शन डे' का मुस्लिम लीगी जिन्ना वाला हिन्दू नरसंहार, बंगाल का विभाजन, पूर्वी पाकिस्तान का बनना (जो बाद में बांग्लादेश बना), नक्सली हिंसा, मरीचझापी नरसंहार और अवैध घुसपैठियों का भारी जनसांख्यिकीय आक्रमण।

इस पूरे दौर में, कांग्रेस से लेकर वामपंथ (माकपा) और फिर तृणमूल के शासन तक, राजनीतिक नेतृत्व, शासन व्यवस्था , सत्ता का रूप हमेशा हिंदुत्व की विचारधारा का कड़ा विरोधी रहा। इस पृष्ठभूमि में बंगाल में ड्ढ्रद्बहदुत्ववादी विचारधारा वाली पार्टी को मिले पूर्ण बहुमत के महत्व को आंका जाना चाहिए। आजादी के बाद 79 वर्षों तक वहां के प्रशासन, सत्ताधारी वर्ग, 'भद्रलोक' और पुलिस-कानून एजैंसियों को केवल एक ही बात सिखाई

गई हिंदुत्व को खुद से दूर रखो। उन्हें सिखाया गया कि यह 'जहर' है और इसे बढ़ावा नहीं देना चाहिए। आग्रही हिन्दुओं पर हमले, उनको वैचारिक अस्पृश्यता का शिकार बनाना, यहां तक कि विश्व के महान हिन्दू संन्यासी संगठन श्री रामकृष्ण मिशन को न्यायालय में यह शपथ पत्र तक देना पड़ा कि वे हिन्दू नहीं हैं ताकि उनको मिलने वाली बंगाल सरकार के शैक्षिक वित्तीय सहायता मिलती रहे-यह सब बंगाल में आम बात थी। हिन्दुओं को लगता था वे अरब इस्लामिक शासन में हैं।

बंगलादेशीयों की घुसपैठ रोकने के लिए सीमा सुरक्षा बल को बंगाल की सैक्युलर सरकार ने जमीन तक नहीं उपलब्ध कराई जिसका आदेश शुभेंदु सरकार ने पहले दिन ही दिया। जब अंग्रेजों ने बंगाल पर राज किया और कलकत्ता को अपनी पहली राजधानी बनाया, तो उन्होंने हिंदू समाज के भद्रलोक वर्ग को चापलूस 'बाबू' बनाने की कोशिश की। उन्होंने समाज को हिंदू-मुस्लिम के चरम विभाजन में बांट दिया, हिंदू भद्रलोक की आजादी की जद्दोजहद से नफरत की, और 'श्री राम पुर' का नाम बिगाड़कर उसे 'सेरामपुर' कर उसे ईसाई धर्म परिवर्तन का बड़ा केंद्र बनाया। बंगाल ने वह दौर भी देखा जब ब्रिटिश मिशनरियों ने हिंदुओं के खिलाफ झूठ फैलाया, उन्हें 'जंगली' और 'सपेरा' कहा। इससे स्वामी विवेकानंद इतने क्रोधित हुए कि उन्होंने मिशनरियों को फटकारते हुए कहा था 'तुम ईसाई नहीं हो; ईसा मसीह के पास वापस जाओ।'

लेकिन बंगाल कभी नहीं झुका = इसी धरती से सबसे विद्रोही आवाजें उठीं क्रांतिकारी, आध्यात्मिक गुरु और सनातन धर्म के अडिग विचारक। बंकिम चंद्र के आनंदमठ और वंदे मातरम से लेकर विवेकानंद की 'तूफानी हिंदू' पुकार तक; सिस्टर निवेदिता, टैगोर और सुभाष चंद्र बोस से लेकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और काजी नजरुल इस्लाम तक हजारों क्रांतिकारियों ने वंदे मातरम गाते हुए फांसी के फंदे को चूम लिया। बंगाल ने विदेशी विचारधाराओं से कभी समझौता नहीं किया। हिंदू महासभा के कमजोर होने से बहुत पहले ही, 1940 के दशक में स्व संघ के प्रचारकों ने बंगाल में हिन्दू संगठन का अपना काम शुरू कर दिया था।

ओबीसीएल को राष्ट्रीय राजमार्ग अतिक्रमण मामले में मिली हाईकोर्ट से राहत

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़े कथित अतिक्रमण मामले में ओबीसीएल (पूर्व में उड़ीसा बंगाल करियर प्राइवेट लिमिटेड) को अंतरिम राहत प्रदान की है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि संबंधित भूमि का विधिवत सीमांकन किए बिना किसी भी प्रकार की दमनात्मक कारवाई नहीं की जाएगी। ओबीसीएल की ओर से दायर याचिका में कहा गया था कि सिलतरा औद्योगिक क्षेत्र रायपुर स्थित लगभग 18,725 वर्गफुट भूमि कंपनी को वर्ष 2009 में वैधानिक रूप से आवंटित की गई थी, तथा 2020 में 99 वर्ष की लीज डीड निष्पादित की गई। इसके बावजूद राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की ओर से 2 मई 2016 को कथित अतिक्रमण हटाने का नोटिस जारी किया था। कंपनी की ओर से दायर याचिक में कहा गया था कि बिना किसी अधिकृत सीमांकन के अतिक्रमण का आरोप लगाया गया है, जो विधिसम्मत नहीं है। वहीं राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की ओर से न्यायालय को अवगत कराया गया कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राष्ट्रीय राजमार्गों पर अतिक्रमण हटाने को लेकर दिए गए निर्देशों के अनुपालन में कार्रवाई की जा रही है। जस्टिस अमितेंदु किशोर प्रसाद की सिंगल बैंच ने मामले की सुनवाई के बाद निर्देश दिया कि संबंधित भूमि का सीमांकन विधि अनुसार तथा संबंधित पक्षों की उपस्थिति में किया जाए।

चार साल का तेंदूपत्ता बोनस दिलाने को संग्राहकों ने विधायक को सौंपा ज्ञापन

बीजापुर। बीजापुर जिले के पामेड़ क्षेत्र के तेंदूपत्ता संग्राहकों ने पिछ्ले चार वर्षों से लंबित तेंदूपत्ता बोनस राशि दिलाने की मांग को लेकर बीजापुर विधायक विक्रम मंडावी को विधायक निवास पहुंचकर एक ज्ञापन सौंपा है। ग्रामीणों ने प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति पामेड़ के प्रबंधक रामाराव व्ही. पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने विगत चार वर्षों से तेंदूपत्ता संग्राहकों को बोनस राशि का भुगतान नहीं किया है। ज्ञापन में बताया गया कि समिति के अंतर्गत 23 फड़ संचालित हैं, जहां संग्राहक मेहनत से तेंदूपत्ता एकत्र करते हैं, लेकिन बोनस की राशि नहीं मिलने से उन्हें आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। संग्राहकों ने आरोप लगाया कि जब वे बोनस राशि के बारे में पूछते हैं, तो पामेड़ के प्रबंधक रामाराव व्ही. उन्हें डरा-धमकाकर चुप करा देते हैं। ज्ञापन प्राप्त करने के बाद विधायक ने कहा तेंदूपत्ता संग्राहकों का बोनस पाने का अधिकार है। गरीब आदिवासियों की मेहनत पर डाका डालने वालों को चिह्नित कर उन पर कार्रवाई हो। विधायक मंडावी ने शासन-प्रशासन से मांग की है कि इस पूरे मामले की उच्चस्तरीय जांच हो और दोषी पाए जाने पर प्रबंधक रामाराव व्ही. के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए तथा संग्राहकों के चार वर्षों के लंबित बोनस का भुगतान तत्काल किया जाए। विधायक ने यह भी कहा है कि यदि मामले की जांच और दोषियों पर कार्रवाई नहीं हुई, तो तेंदूपत्ता संग्राहकों के साथ मिलकर आंदोलन किया जाएगा।

फर्जी दस्तावेज से नौकरी हासिल की, हुआ बर्खास्त

■ **आरक्षक को बलरामपुर पुलिस ने किया गिरफ्तार, बलरामपुर पुलिस इस मामले में अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है**

बलरामपुर। फर्जी दस्तावेज के आधार पर निवास प्रणाम पत्र बनवाकर सीआरपीएफ में नौकरी पाने के आरोपी आरक्षक को बलरामपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तहसीलदार की रिपोर्ट पर पुलिस ने सीआरपीएफ से बर्खास्त जवान के खिलाफ केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया है। मामले में शामिल अन्य लोगों की तलाश भी पुलिस कर रही है। जानकारी के मुताबिक 204 कोबरा बटालियन, सीआरपीएफ, करनपुर जगदलपुर में पदस्थ कॉन्स्टेबल सुमित ने तहसील कार्यालय बलरामपुर से ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से अपना फर्जी निवास प्रमाण पत्र बनाया था। आरोपी ने विशाल सोनी के शैक्षणिक दस्तावेजों और अन्य आवश्यक दस्तावेजों में कूटरचना कर सुमित सिंह के नाम का उल्लेख कर निवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन दिया। जिसके बाद उसका निवास प्रमाण पत्र बन गया। इसी प्रमाण पत्र के आधार पर सीआरपीएफ में उसकी नौकरी लगी। लेकिन बाद में मामले का खुलासा होने पर उसे सीआरपीएफ से बर्खास्त कर दिया गया। अ्ररोपी आरक्षक पर मामला भी दर्ज किया गया। बलरामपुर जिले के एडिशनल एसपी विश्व दीपक त्रिपाठी ने जानकारी देते हुए बताया कि बीते 28 अप्रैल को बलरामपुर तहसीलदार ने आवेदन दिया और बताया कि आरोपी ने कूटरचित दस्तावेज के आधार पर अपना निवास प्रमाण पत्र ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से बनाया और उसके आधार पर सीआरपीएफ कोबरा में नौकरी कर रहा है। तहसीलदार के आवेदन के आधार पर थाना बलरामपुर में धारा 318, 336, 319, 340, 61, 338 बीएनएस और आईटी एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया। आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया, जहां से न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि इस मामले में संलिप्त अन्य लोगों की तलाश की जा रही है।

वृंदावन कॉलोनी विवाद मामले अब जगदलपुर विशेष लोक अदालत में होगा निपटारा

जगदलपुर। शहर के वृंदावन कॉलोनी का बहुचर्चित भूमि विवाद एक बार फिर सुर्खियों में है। लगभग 60 एकड़ में फैली इस कॉलोनी पर मालिकाना हक को लेकर बस्तर राज परिवार और यहां निवासरत सैकड़ों परिवारों के बीच बीते कई दशकों से कानूनी संघर्ष जारी है। अब इस मामले में देश की सर्वोच्च अदालत के हस्तक्षेप के बाद समाधान की नई आस जगी है। मिली जानकारी के अनुसार, वृंदावन कॉलोनी में 1980 के दशक से व्यवस्थित रूप से बसावट और पक्के मकानों का निर्माण शुरू हुआ था। रहवासियों का दावा है कि उन्होंने करीब 50 वर्ष पूर्व बस्तर राज परिवार से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) लेकर विधिवत जमीन खरीदी थी। इसी आधार पर लोगों ने यहां अपने आशियाने बनाए और धीरे-धीरे पूरी कॉलोनी विकसित होती चली गई। हालांकि, समय बीतने के साथ इस जमीन के वास्तविक मालिकाना हक को लेकर विवाद खड़ा हो गया। मामला निचली अदालत तक पहुंचा, जहां शुरुआती सुनवाई में फैसला कॉलोनी वासियों के पक्ष में आया था। इससे रहवासियों को राहत मिली और वे लंबे समय तक अपने अधिकार को लेकर आश्वस्त रहे।बाद में इस निर्णय को चुनौती देते हुए मामला छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट पहुंचा। हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान कथित रूप से रहवासियों या उनके पक्षकारों की अनुपस्थिति के कारण अदालत ने एकपक्षीय (एक्स-पार्टी) निर्णय बस्तर राज परिवार के पक्ष में सुना दिया। इस फैसले के बाद विवाद ने और गंभीर रूप ले लिया, क्योंकि हाई कोर्ट की डिक्री के बाद राज परिवार का दावा कानूनी रूप से मजबूत माना जाने लगा। हाई कोर्ट के आदेश से चिंतित रहवासियों ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। सर्वोच्च अदालत ने मामले की संवेदनशीलता, जटिलता और सैकड़ों परिवारों के आवासीय हितों को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इतने बड़े सामाजिक और आवासीय विवाद का समाधान केवल कानूनी लड़ाई से नहीं, बल्कि आपसी सहमति और संवाद से बेहतर तरीके से किया जा सकता है। इसी के तहत सुप्रीम कोर्ट ने मामले को विशेष लोक अदालत के माध्यम से निपटाने के लिए पुन- जगदलपुर जिला एवं सत्र न्यायालय भेज दिया है। कोर्ट के निर्देशानुसार अब इस विवाद के समाधान के लिए 21, 22 और 23 अगस्त 2026 की तारीखें तय की गई हैं। इन तीन दिनों के दौरान दोनों पक्षों के बीच समझौते और अंतिम समाधान की प्रक्रिया चलेगी। प्रक्रिया के तहत जिला न्यायालय द्वारा वृंदावन कॉलोनी के लगभग 500 रहवासियों को नोटिस जारी कर अदालत में उपस्थित होने के निर्देश दिए गए हैं। इससे कॉलोनी में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। बड़ी संख्या में रहवासी इस प्रक्रिया को अपने भविष्य और संपत्ति अधिकार से जुड़ा अहम मोड़ मान रहे हैं। राज परिवार का पक्ष लगातार यह रहा है कि संबंधित 60 एकड़ भूमि उनकी निजी संपत्ति है और इस पर उनका वैधानिक मालिकाना हक है। हाईकोर्ट से पक्ष में फैसला आने के बाद राज परिवार की स्थिति और मजबूत हुई थी।

डीजल पेट्रोल बचाने कार पूलिंग कर तिलोखन गांव पहुंचा एमसीबी जिला प्रशासन

मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर। कलेक्टर संतन देवी जांगड़े के निर्देशानुसार जिला स्तरीय अधिकारियों ने सुशासन तिहार के जिला स्तरीय शिविर में शामिल होने के लिए अलग-अलग वाहनों के बजाय सामुदायिक बस का उपयोग किया। कलेक्ट्रेट परिसर से अधिकारियों की यह बस ग्राम तिलोखन के लिए रवाना हुई। इस पहल का मुख्य उद्देश्य ईंधन की बचत, पर्यावरण संरक्षण और सामूहिक परिवहन व्यवस्था को बढ़ावा देना है।

प्रशासन का मानना है कि यदि अधिकारी खुद सामुदायिक रूप से यात्रा करेंगे तो आम लोगों में भी इसके प्रति जागरूकता बढ़ेगी और संसाधनों का बेहतर उपयोग हो सकेगा। जिला प्रशासन की इस पहल को शासन की जनहितकारी योजनाओं को व्यवहारिक रूप से अपनाने की दिशा में एक सकारात्मक कदम माना जा रहा है। अधिकारियों ने सामूहिक यात्रा के माध्यम से यह संदेश देने का प्रयास किया कि छोटी-छोटी आदतों में बदलाव कर ईंधन संरक्षण और पर्यावरण सुरक्षा में महत्वपूर्ण योगदान दिया जा सकता है।

इस सामुदायिक यात्रा में विभिन्न विभागों के अधिकारी शामिल रहे। इनमें सीएसपीडीसीएल, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग , खनिज विभाग, क्रेडा, पीएमजीएसवाई, आयुष, पशुपालन, शिक्षा, मत्स्य, अंत्यावसायी एवं कौशल विकास, कृषि, भूमि विकास, सीजीएमएससी, डीपीएसओ, नान उपस्थित रहे।

दोपहर में पशुओं के व्यावसायिक एवं श्रम संबंधी उपयोग पर प्रतिबंध

कांकेर। जिले में वर्तमान में पड़ रही भीषण गर्मी एवं लू के बढ़ते प्रकोप के कारण पशुओं के स्वास्थ पर प्रतिकूल प्रभाव पडऩे तथा उनके जीवन की रक्षा को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी निलेशकुमार महादेव क्षीरसागर ने पशुओं से व्यावसायिक एवं श्रम संबंधी उपयोग पर प्रतिबंध लगाया है। जारी आदेश में उल्लेख किया गया है कि पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम 1996 के नियम 6(3) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आगामी 30 जून तक जिले के सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र में पशुओं के व्यावसायिक एवं श्रम संबंधी उपयोग पर प्रतिदिन दोपहर 12 से 03 बजे तक पूर्णत- प्रतिबंध रहेगा। इस अवधि के दौरान बैलगाड़ी, भैंसागाड़ी, ऊंट, खच्चर अथवा गधों के माध्यम से माल ढुलाई, सवारी कराना या किसी भी प्रकार का शारीरिक श्रम लिया जाना प्रतिबंधित होगा। तेज धूप और उच्च तापमान के दौरान पशुओं से कार्य लेना पशु क्रूरता की श्रेणी में माना जाएगा तथा उक्त आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों व पशु स्वामियों के विरूद्ध पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम 1996 के तहत वैधानिक एवं दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।

तेज आंधी-तूफान से मालगाड़ी की तिरपाल ओएचई तार में फंसी

कोरबा। जिले में शुक्रवार की सुबह मौसम का मिजाज बदल गया। सुबह से काली घटाएं छाई रहीं और तेज आंधी-तूफान के साथ आकाशीय बिजली की चमक और बारिश ने लोगों को गर्मी से बड़ी राहत दी। मौसम में आए इस बदलाव से तापमान में गिरावट दर्ज की गई और लोगों को गर्मी से राहत भी मिली। तेज आंधी-तूफान का असर कोयला परिवहन पर भी पड़ा। खदान से कोयला लोड कर प्लांट के लिए जा रही मालगाड़ी को बीच रास्ते में रोकना पड़ा। पवन टाकीज से दुरपा रोड के पास यह घटना सामने आई है। दरअसल, चलती मालगाड़ी में कोयले को ढंकने के लिए तिरपाल लगाया गया था। तेज आंधी के चलते तिरपाल उड़कर फट गया और ओएचई तार व खंभे में फंसने लगा। तिरपाल के ओएचई तार में फंसने से शॉर्ट सर्किट की संभावना बन गई थी।

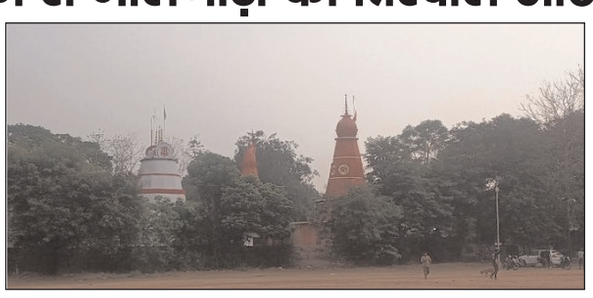

अगर तार में करंट आता तो बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। मालगाड़ी के चालक ने सूझबूझ दिखाते हुए तत्काल ट्रेन रोक दी और उच्च अधिकारियों को इसकी सूचना दी। इसके बाद मौके पर पहुंची टीम ने फटे हुए तिरपाल को हटाकर ठीक किया। तब जाकर मालगाड़ी को आगे के लिए रवाना किया गया। स्थानीय लोगों के मुताबिक, सुबह से ही आसमान में काले बादल छाए रहे। करीब 6 बजे अचानक तेज आंधी चली और बिजली कड़कने लगी। इसके बाद हल्की से मध्यम बारिश शुरू हो गई। मौसम विभाग ने पहले ही जिले में आंधी-बारिश का अलर्ट जारी किया था। बेमौसम बारिश और आंधी से किसानों की चिंता बढ़ गई है। खेतों में तैयार सब्जी फसल को नुकसान की आशंका है। तेज आंधी से तापमान में 4 से 5 डिग्री की गिरावट आई है। लोगों को गर्मी से राहत मिली है, लेकिन कई जगह पेड़-पौधे और बिजली के खंभे में शॉर्ट सर्किट की घटना सामने आया। कुछ इलाकों में बिजली आपूर्ति भी बाधित हुई। समय रहते चालक की सतर्कता से बड़ा हादसा टल गया। ओएचई लाइन में फंसा तिरपाल हटाने के बाद परिचालन सामान्य कर दिया गया है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे तक इसी तरह का मौसम बने रहने की संभावना जताई है।

छत्तीसगढ़ प्रमुख समाचार

जिला प्रशासन का सख्त निर्देश अवैध खरीद-बिक्री पर कार्रवाई

एमसीबी। जिले में ईंधन की जमाखोरी को रोकने और सुचारू आपूर्ति बनाए रखने के लिए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी कार्यालय द्वारा एक महत्वपूर्ण प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है अपर कलेक्टर अनिल सिदार द्वारा जारी इस आदेश के तहत जिले के सभी पेट्रोल पंप संचालकों को सख्त निर्देश दिए गए हैं।प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि पेट्रोल पंप संचालक केवल वाहनों में ही डीजल और पेट्रोल की आपूर्ति करेंगे । किसी भी स्थिति में खुले बर्तनों, जरिकेन या अवैध रूप से ईंधन देने पर पाबंदी रहेगी । एम्बुलेंस, शासकीय वाहनों और सुरक्षा बलों के वाहनों के लिए ईंधन की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। इन आवश्यक सेवाओं के सुचारू संचालन के लिए सभी पंपों को पर्याप्त रिजर्व स्टॉक रखना अनिवार्य होगा।सभी पेट्रोल पंप संचालकों को अपने दैनिक स्टॉक की जानकारी अनिवार्य रूप से जिला कार्यालय की खाद्य शाखा को भेजनी होगी। यदि किसी पंप पर प्रतिदिन की औसत बिक्री के अनुसार दो दिन से कम का स्टॉक बचता है, तो इसकी सूचना तुरंत जिला प्रशासन को देनी होगी।

खैरागढ़ शराब दुकान पर ओव्हररेटिंग का आरोप

खैरागढ़। खैरागढ़ की सरकारी शराब दुकान फिर से विवाद के घेरे में है। कभी मिलावटी शराब और फर्जी होलोग्राम को लेकर सुर्खियों में रही शराब दुकान अब ओव्हररेटिंग और अव्यवस्था के आरोपों से घिरी है।यही नहीं ओव्हर रेटिंग का विरोध करने वालों पर शराब दुकान के कर्मी दबंगई करते हैं। अब तो हालात ऐसे हैं कि शराब प्रेमियों के बीच चर्चा आम हो चुकी है कि यहां से शराब लेनी है तो रेट तो ज्यादा लगेगा ही। स्थानीय लोगों का आरोप है कि दुकान के बाहर कुछ कथित असामाजिक तत्वों ने अपना अनौपचारिक नेटवर्क बना रखा है। आरोपों के मुताबिक निर्धारित कीमत से 10 रुपए ज्यादा लेकर शराब उपलब्ध कराई जा रही है।जो ग्राहक इसका विरोध करते हैं, उन्हें गाली-गलौज, धमकी और अभद्र व्यवहार का सामना करना पड़ता है। हैरानी की बात यह है कि यह पूरा खेल कथित तौर पर सरकारी दुकान के आसपास ही चल रहा है, लेकिन जिम्मेदार विभाग की सख्ती कहीं नजर नहीं आती।शाम ढलते ही दुकान के बाहर हालात और बिगड़ने लगते हैं।

पेट्रोल-डीजल व एलपीजी की पर्याप्त उपलब्धता: कलेक्टर

धमतरी। जिले में पेट्रोल पंपों पर इन दिनों बढ़ती भीड़ एवं कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा ईंधन एवं घरेलू गैस की कमी संबंधी अफवाह फैलाए जाने की स्थिति को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी अबिनाश मिश्रा ने जिले के सभी अनुविभागीय दण्डाधिकारियों (एसडीएम) को अपने-अपने क्षेत्र के पेट्रोल पंपों पर आवश्यकतानुसार कार्यपालिक दण्डाधिकारी एवं फूड इंस्पेक्टर की ड्यूटी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर श्री मिश्रा ने स्पष्ट किया है कि जिले में पेट्रोल एवं डीजल का पर्याप्त भंडारण उपलब्ध है तथा आपूर्ति व्यवस्था पूरी तरह सुचारू रूप से संचालित हो रही है। इसी प्रकार एलपीजी (घरेलू गैस) की भी जिले में किसी प्रकार की कमी अथवा शॉर्टेज नहीं है। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों द्वारा फैलायी जा रही भ्रामक सूचनाओं के कारण अनावश्यक रूप से पेट्रोल पंपों पर भीड़ एकत्र हो रही है, जिससे आम नागरिकों को असुविधा हो रही है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि पेट्रोल पंपों की नियमित मॉनिटरिंग की जाए।

12 केजी गांजे के साथ पुलिस के हत्थे चढ़ा ओडिशा तस्कर

जगदलपुर। ओडिशा से गांजा लेकर उसे एक सफेद बोरी में रख वाहन का इंतजार कर रहे आरोपी को नगरनार पुलिस ने पकड़ने में सफलता हासिल की। पुलिस ने आरोपी के पास से 12 किलो से अधिक का गांजा जब्त किया है। आरोपी ने बताया कि वह गांजा को राजस्थान में खपाने के फिराक में था। लेकिन मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने आरोपी को धर दबोचा और उसे न्यायालय में पेश कर दिया। मामले की जानकारी देते हुए नगरनार थाना प्रभारी संतोष सिंह ने बताया कि सुरेश मेघवाल 20 वर्ष निवासी ग्राम खारीगुर्द थाना कडवड तहसील बावरी जिला जोधपुर राजस्थान के द्वारा 14 मई को सफेद बोरी में अवैध रूप से मादक पदार्थ गांजा रखकर वाहन की तलाश में धनपूंजी आरटीओ नाका के पास खड़ा था। आरोपी को देख मुखबिर ने पुलिस को सूचना दी। जिसके बाद टीम ने ग्राम धनपुंजी आरटीओ नाका एनएच 63 पहुंचकर मुखबीर के बताये युवक की तलाश करते हुए सफेद बोरी रखकर वाहन का इंतजार कर रहे युवक को घेराबंदी कर पकड़ा गया।

ग्राहक सेवा केंद्र संचालक की कार का कांच तोड़कर चोरी

एमसीबी। जनकपुर थाना क्षेत्र में दिनदहाड़े लाखों रुपये की चोरी हुई है। ग्राहक सेवा केंद्र संचालक की कार का शीशा तोड़कर लाखों रुपये से भरा बैग पार कर दिया गया। एमसीबी पुलिस ने आरोपियों पर 5 हजार रुपये का इनाम घोषित किया है। कोटाडोल क्षेत्र निवासी ध्रुव कुमार यादव बरौता में ग्राहक सेवा केंद्र का संचालन करता है। वह अपने केंद्र के लेनदेन कार्य के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा जनकपुर से ?4 लाख 25 हजार नकद निकालकर लौट रहा था। रकम को उसने काले रंग के बैग में रखा था, जिसमें पहले से ?22 हजार नकद मौजूद थे। इस तरह बैग में कुल ?4 लाख 47 हजार रुपये रखे हुए थे। बैंक से निकलने के बाद ध्रुव कुमार यादव कुछ दूरी पर स्टेबलाइजर खरीदने के लिए एक दुकान के सामने रुका। उसने अपनी कार सड़क किनारे लॉक की और दुकान की ओर चला गया इसी दौरान पहले से घात लगाए बैठे अज्ञात चोरों ने कार के सामने बाईं ओर का कांच तोड़ दिया और सीट पर रखा नकदी से भरा बैग लेकर फरार हो गए।

कवर्धा में शराब भट्टी के खिलाफ एबीवीपी का बड़ा प्रदर्शन

■ **कवर्धा में एबीवीपी ने शराब भट्टी हटाने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया है. रायपुर-जबलपुर नेशनल हाईवे जाम हो गया.**

कवर्धा। जिले के पोंडी में शराब दुकान के खिलाफ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में उग्र विरोध प्रदर्शन किया है। एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने शराब दुकान को पोंडी से हटाने की मांग की है। इस मांग को लेकर एबीवीपी ने रायपुर-जबलपुर नेशनल हाईवे को जाम कर दिया। एबीवीपी के प्रदर्शनकारियों का कहना है कि लंबे समय से शराब भट्टी को अन्य स्थान पर शिफ्ट करने की मांग की जा रही थी। प्रशासन की तरफ से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। जिसके बाद इस मुद्दे पर मजबूरी में विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में स्कूली छात्र-छात्राएं भी शामिल रहे। प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर बैठकर प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और शराब भट्टी को तत्काल हटाने की मांग की। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि स्कूल और आबादी क्षेत्र के पास शराब दुकान संचालित होने से आसपास का माहौल लगातार खराब हो रहा है।

इससे विद्यार्थियों और स्थानीय लोगों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। चक्का जाम के कारण नेशनल हाईवे-30 के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई। यात्री बसें, ट्रक और अन्य छोटे-बड़े वाहन घंटों तक जाम में फंसे रहे, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। सड़क पर यातायात पूरी तरह प्रभावित हो गया और कई लोग वैकल्पिक मार्ग तलाशते नजर आए। धरना-प्रदर्शन के कारण हुए चक्काजाम में डिप्टी सीएम विजय शर्मा का काफी भी फंस गया। जाम इतना तगड़ा था कि लोग अपने वाहनों से कहीं भी नहीं जा पा रहे थे। जाम बढ़ता देख मौके पर कवर्धा पुलिस के आला अधिकारी पहुंचे। उन्होंने उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया जिसके बाद हालात सामान्य हो सकी। प्रदर्शन स्थल पर पुलिस बल को तैनात किया गया है जिससे किसी भी मुश्किल स्थिति से निपटा जा सके।

ट्रेन डिरेल के बाद राहत और बचाव कार्य का लाइव प्रदर्शन

ट्रेन डिरेल के बाद राहत और बचाव कार्य का लाइव प्रदर्शन, हादसे से निपटने की तैयारी

मनेंद्रगढ़। रेल दुर्घटनाओं को रोकने और हादसे के समय तुरंत मदद पहुंचाने के लिए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे (बिलासपुर मंडल) ने एक बड़ा सुरक्षा अभ्यास किया। यह मॉक ड्रिल मनेन्द्रगढ़ रेलवे स्टेशन पर आयोजित की गई, ताकि किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए टीम को तैयार रखा जा सके। अभ्यास को असली रूप देने के लिए एक काल्पनिक (नकली) स्थिति बनाई गई। इसमें दिखाया गया कि यात्रियों से भरी एक ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। जैसे ही हादसे की खबर मिली, रेलवे की आपदा प्रबंधन टीम, एनडीआरएफ (ह्ष्ठक्रस्न), स्वास्थ्य विभाग और स्थानीय प्रशासन तुरंत एक्शन में आ गए। सभी एजेंसियों ने मिलकर संयुक्त रूप से रेस्क्यू ऑपरेशन (बचाव कार्य) शुरू किया। इस अभ्यास के दौरान मुख्य रूप से घायलों का रेस्क्यू किया गया। इसमें बोगियों में फंसे घायल यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। इसके बाद घायलों को मौके पर ही प्राथमिक उपचार (फर्स्ट एड) देने का प्रदर्शन किया गया। मॉकड्रिल के दौरान मलबे को काटने और लोगों को निकालने वाले राहत उपकरणों का व्यावहारिक इस्तेमाल करके देखा गया। रेलवे अधिकारियों के अनुसार, इस मॉक ड्रिल का उद्देश्य फ्रंट लाइन स्टाफ और आपदा प्रबंधन टीम को इस तरह तैयार करना कि वे बिना समय गंवाए तुरंत काम शुरू कर सकें। इस मॉकड्रिल में अलग-अलग विभागों जैसे रेलवे, एनडीआरएफ और अस्पताल के बीच आपसी समन्वय को मजबूत किया गया। इससे वास्तविक हादसे के समय कम से कम समय में प्रभावी राहत पहुंचाकर लोगों की जान बचाई जा सके। इस दौरान वहां मौजूद आम जनता को भी सुरक्षा के प्रति जागरूक किया गया। लोगों को बताया गया कि अगर कभी ऐसा रेल हादसा हो, तो उन्हें घबराने के बजाय क्या सुरक्षा उपाय अपनाने चाहिए और कैसे मदद करनी चाहिए। इसके साथ ही रेलवे ने अपनी टीम की तैयारियों और दुर्घटना राहत उपकरणों की जांच भी पूरी की

संक्षिप्त समाचार

पेट्रोल पंप संचालकों व कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए पुलिस ने चस्पा किए इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर

रायपुर। पेट्रोल पंप संचालकों एवं कर्मचारियों की सुरक्षा तथा आपातकालीन स्थिति में त्वरित पुलिस सहायता उपलब्ध कराने हेतु प्रमुख एवं दृष्टिगोचर स्थानों पर इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर चस्पा किए जा रहे हैं। उक्त पोस्टरों में पुलिस कंट्रोल रूम, संबंधित स्थानीय थाना प्रभारी, डायल-112 सहित अन्य महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबर अंकित किए गए हैं, ताकि किसी भी संदिग्ध गतिविधि अथवा आपराधिक घटना की स्थिति में तत्काल पुलिस को सूचना दी जा सके। साथ ही पेट्रोल पंप संचालकों एवं कर्मचारियों को रात्रिकालीन सतर्कता, संदिग्ध व्यक्तियों पर निगरानी रखने, सीसीटीवी कैमरे सक्रिय रखने तथा नगदी के सुरक्षित प्रबंधन संबंधी आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए जा रहे हैं।

जगदलपुर में 105.22 और रायपुर में 103.58 रुपए लीटर हुआ पेट्रोल

रायपुर। देशभर में पेट्रोल और डीजल 3-3 रुपए प्रति लीटर महंगा हो गया है और इसका असर छत्तीसगढ़ पर पड़ा है। जगदलपुर में सबसे अधिक 105.22 रुपये व सबसे कम राजधानी रायपुर में 103.58 रुपये लीटर में पेट्रोल मिल रहा। वहीं डीजल जगदलपुर में डीजल - 98.22 रुपए और राजधानी रायपुर में इसकी कीमत 96.57 रुपए हैं। पेट्रोल पंप खुलने से पहले ही लोगों की लंबी-लंबी कतारे सुबह 5 बजे से लगी शुरु हो जा रही है क्योंकि उन्हें यह लग रहा है कहीं पेट्रोल खत्म हो गया तो दूसरे पेट्रोल पंप में मिलेगा या नहीं। प्रशासन का दावा है कि अफवाहों के चलते लोग सामान्य से ज्यादा पेट्रोल-डीजल भरवा रहे हैं, जिससे शहर में अचानक भीड़ बढ़ गई है। जहां पहले लोग जरूरत के हिसाब से ईंधन लेते थे, वहीं अब बड़ी संख्या में वाहन चालक फुल टैंक करवा रहे हैं। रायपुर कलेक्टर ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। शहर में यदि पेट्रोल की ब्लैक मार्केटिंग हो रही हो तो कलेक्टर कॉल सेंटर के नंबर 9977222564, 9977222574, 9977222584 और 9977222594 पर जानकारी दे सकतें हैं।

छत्तीसगढ़ के लाल दिव्यांशु ने जूनियर वर्ल्ड कप में बनाया विश्व रिकॉर्ड

रायपुर। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के होनहार अंतरराष्ट्रीय निशानेबाज दिव्यांशु देवांगन ने वैश्विक पटल पर भारत का परचम लहराया है। मिस्र की राजधानी काहिरा में आयोजित जूनियर वर्ल्ड कप की 10 मीटर एयर राइफल मिक्स्ड डबल्स स्पर्धा में दिव्यांशु ने न केवल स्वर्ण पदक जीता, बल्कि एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड भी स्थापित किया है। वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी ने कहा कि खेल केवल जीत-हार का माध्यम नहीं, बल्कि अनुशासन और राष्ट्र के प्रति समर्पण का सबसे सशक्त मार्ग है। दिव्यांशु की इस अभूतपूर्व सफलता पर छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी ने उन्हें फोन कर व्यक्तिगत रूप से बधाई दी। बातचीत के दौरान उन्होंने इस जीत के महत्व को साझा किया। श्री चौधरी ने कहा कि यह सफलता छत्तीसगढ़ के लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। यह साबित करता है कि अटूट संकल्प से इतिहास रचा जा सकता है। उन्होंने कहा कि उन्होंने खेल को अनुशासन, धैर्य और आत्मविश्वास का सर्वश्रेष्ठ शिक्षक बताया। उन्होंने जोर दिया कि खेलों के माध्यम से ही युवा शक्ति अंतरराष्ट्रीय मंच पर देश का मान बढ़ा सकती है। वित्त मंत्री ने दिव्यांशु को आश्वासन दिया कि राज्य सरकार प्रदेश की खेल प्रतिभाओं को निखारने और उन्हें हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने विश्वास जताया कि दिव्यांशु भविष्य में भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश और प्रदेश का नाम रोशन करते रहेंगे। स्वर्ण पदक विजेता दिव्यांशु देवांगन ने वित्त मंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि प्रदेशवासियों के स्नेह और निरंतर प्रोत्साहन ने ही उन्हें इस मुकाम तक पहुँचाने की ऊर्जा दी है।

अमर शहीद सुखदेव की जयंती पर वित्त मंत्री ने अर्पित की भावभीनी श्रद्धांजलि

रायपुर। छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रखर नायक और महान क्रांतिकारी अमर शहीद सुखदेव थापर जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धापूर्वक नमन किया है। शहीद सुखदेव जी के बलिदान को याद करते हुए चौधरी ने कहा कि माँ भारती की स्वतंत्रता के लिए सुखदेव जी ने हँसते-हँसते अपने प्राणों की आहुति दे दी। उनका जीवन देशभक्ति, अदम्य साहस और त्याग का एक कालजयी उदाहरण है। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान उन्होंने भगत सिंह और राजगुरु जैसे साथियों के साथ जिस निडरता और अटूट समर्पण का परिचय दिया, वह आज भी भारत के हर युवा के हृदय में राष्ट्रप्रेम की अलख जगाता है। ओ.पी. चौधरी ने कहा कि शहीद सुखदेव जी का बलिदान केवल इतिहास का हिस्सा नहीं, बल्कि हमारे राष्ट्र के गौरवशाली अस्तित्व की नींव है। उनकी वीरता हमें राष्ट्र निर्माण के प्रति सदैव समर्पित रहने की प्रेरणा देती है।

इकोनॉमी के विकास के लिए वैल्यू एडिशन आधारित उत्पादन करना होगा : डेका

इंदिरा गांधी कृषि विविके 11 वें दीक्षांत समारोह मे शामिल हुए राज्यपाल और मुख्यमंत्री, 1880 विद्यार्थियों को मिली उपाधि, 13 विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक मिले

रायपुर। छत्तीसगढ़ की लगभग 80 प्रतिशत अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है। आज भूमि लगातार संकुचित होती जा रही है। अतएव हमें कम जमीन में ज्यादा से ज्यादा उत्पादन के लिए कार्य करना होगा। अर्थव्यवस्था के तेजी से विकास के लिए वैल्यू एडिशन उत्पादन आज की महती आवश्यकता है। यह उद्गार राज्यपाल श्री रमेन डेका एवं कुलाधिपति इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर ने विश्वविद्यालय के 11वें दीक्षांत समारोह में व्यक्त किये। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय और विशिष्ट अतिथि के रूप में कृषि मंत्री श्री राम विचार नेताम और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली के पूर्व निदेशक और प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉ. अशोक कुमार सिंह उपस्थित थे ।

इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर के सभागार में आयोजित भव्य एवं गरिमामय दीक्षांत समारोह में शैक्षणिक वर्ष 2024-25 में उत्तीर्ण छात्र-छात्राओं को पदक एवं उपाधियां वितरित की गई। विभिन्न संकायों में प्रावीण्य सूची में स्थान प्राप्त करने वाले मेधावी विद्यार्थियों को 13 स्वर्ण, 7 रजत एवं 2 कांस्य पदक सहित 128 शोधार्थियों को पी.एच.डी, 518 विधार्थियों को स्नातकोत्तर और 1234 विधार्थियों को स्नातक उपाधि प्रदान की गई।

कार्यक्रम के अध्यक्षीय उद्बोधन में राज्यपाल श्री रमेन डेका ने इन उपाधि और पदक प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि दीक्षांत समारोह छात्र जीवन का एक बहुत बड़ा अवसर होता है। यह केवल डिग्री प्राप्त करने का दिन नही बल्कि भविष्य की शुरूआत का प्रतीक है। जब यह विश्वविद्यालय स्थापित हुआ था तब यहां केवल दो या तीन स्ट्रीम ही उपलब्ध थी। लेकिन समय के साथ शिक्षा और अवसरों का विस्तार हुआ है। डेका ने कहा कि आज कृषि परिवर्तन के दौर से गुजर रही है। अब यह विज्ञान तकनीकी, नवाचार और उद्यमिता से संचालित हो रही है। विश्वभर में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ड्रोन, उपग्रह मानचित्र, सटीक कृषि जलवायु अनुकूल तकनीक, जैव प्रौद्योगिकी और डेटा विश्लेषण का उपयोग बढ़ रहा है। भारत भी तेजी से इस दिशा में आगे बढ़ रहा है। ड्रोन द्वारा उर्वरक एवं कीटनाशक छिड़काव, डिजिटल उपकरणों से मृदा स्वास्थ्य निगरानी, मोबाइल ऐप द्वारा किसान परामर्श और ई-नाम बाजार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बदल रहे हैं। किसानों और युवाओं को भी आधुनिक और उन्नत खेती की ओर बढना चाहिए।

छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। लेकिन अब हमें बासमती जैसे उच्च गुणवत्ता वाले धान के उत्पादन पर भी ध्यान देना चाहिए। इससे कार्पोरेट कंपनियों द्वारा खरीद आसान होगी और किसानों को बेहतर लाभ मिल सकेगा। हाइड्रोपोनिक्स और प्राकृतिक खेती के लिए भी भविष्य में बड़ी संभावनाएं है। विद्यार्थियों को भी कृषि के क्षेत्र में आगे बढना चाहिए। श्री डेका ने कहा कि छत्तीसगढ़ की भूमि और जल संरचना कृषि के लिए अनुकूल है। यहां पानी आसानी से नीचे नहीं जाता जिससे उत्पादन बढ़ाने में सहायता मिलती है। सही तकनीक और सोच के साथ कृषि को और अधिक लाभकारी बनाया जा सकता है।

दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि कृषि विश्वविद्यालय ने कृषि शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया है तथा वैज्ञानिकों द्वारा विकसित नई फसल किस्मों और आधुनिक तकनीकों से किसानों को बड़ा लाभ मिल रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए खेती को आधुनिक, लाभकारी और टिकाऊ बनाने की दिशा में लगातार कार्य कर रही है। धान के साथ-साथ दलहन, तिलहन,फल-सब्जी और मोटे अनाजों के उत्पादन को बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि किसानों से 3100 रूपए प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी, सिंचाई परियोजनाओं के विस्तार, कृषि उपकरणों की उपलब्धता तथा मुफ्त बिजली जैसी योजनाओं से किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है। उन्होंने विद्यार्थियों से ड्रोन, एआई और डिजिटल तकनीकों को खेती से जोड़कर किसानों और वैज्ञानिकों के बीच सेतु बनने का आव्हान किया।

कृषि मंत्री श्री रामविचार नेताम ने कहा कि प्रदेश में कृषि को बढ़ावा देने के लिए अनेक नवाचार किए जा रहे है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में धान की सबसे ज्यादा प्रजातियां है। सुगन्धित धान के लिए हमारा राज्य जाना जाता है। फल, फूल और मसाले की भी अपार संभावनाएं यहां है। उन्होंने विद्यार्थियों से शोध और नवाचार के क्षेत्र में आगे आने का आग्रह करते हुए कहा कि विद्यार्थियों के ज्ञान का लाभ छत्तीसगढ़ को मिलेगा। समारोह में दीक्षांत भाषण डॉ. अशोक कुमार सिंह ने दिया। विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. गिरीश चंदेल ने दीक्षांत प्रतिवेदन प्रस्तुत किया उन्होंने विश्वविद्यालय की गतिविधियों एवं उपलब्धियों पर विस्तृत प्रकाश डाला। साथ ही उपाधि प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को दीक्षा उपदेश दिया। आभार प्रदर्शन कुलसचिव द्वारा किया गया। दीक्षांत समारोह में क्षेत्र के विधायक पद्मश्री अनुज शर्मा, विभिन्न विश्वविद्यालय के कुलपति, विश्वविद्यालय के प्रबंध मण्डल, विद्या परिषद तथा प्रशासनिक परिषद के सदस्यगण, प्राध्यापक, वैज्ञानिक, विश्वविद्यालय के अधिकारी, उपाधि तथा पदक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी तथा उनके पालकगण उपस्थित थे।

भूपेश पहले कांग्रेस के अपने जर्जर घर को सम्हालें : शताब्दी

- **कांग्रेस को अंतर्कलह और अनुशासनहीनता का अड्डा बता किया पलटवार**

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश प्रवक्ता शताब्दी पाण्डेय ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के भाजपा से जुड़े हालिया बयान पर तीखा प्रहार करते हुए कहा है कि जिनकी अपनी जमीन खिसक चुकी है, वे अब भाजपा के आंतरिक और सुदृढ़ संगठनात्मक ढाँचे पर टिप्पणी कर रहे हैं! श्रीमती पाण्डेय ने कहा कि बघेल का बयान उनके मानसिक हताशा और खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली स्थिति को दर्शाता है।

भाजपा प्रदेश प्रवक्ता श्रीमती पाण्डेय ने कांग्रेस को अंतर्कलह और अनुशासनहीनता का अड्डा बताते हुए कहा कि आज छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी का संगठनात्मक ढाँचा पूरी तरह जर्जर हो चुका है। पार्टी में जिस स्तर की आंतरिक कलह और गुटबाजी है, वह किसी से छिपी नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री को दूसरों के घर में झाँकने के बजाय यह बताना चाहिए कि उनकी पार्टी में कार्यकर्ताओं को मंचों पर

अपमानित क्यों किया जा रहा है? जिस पार्टी में सरेआम नेताओं की खींचतान और अनुशासनहीनता चरम पर हो, उसके नेता को भाजपा के संगठनात्मक विषयों पर बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। श्रीमती पाण्डेय ने कहा कि कांग्रेस आज आपराधिक चरित्र के लोगों के प्रभुत्व वाली पार्टी बन गई है। सत्ता में रहते हुए भी और विपक्ष में आने के बाद भी, कांग्रेस ने केवल उन तत्वों को संरक्षण दिया है जो समाज में अशांति फैलाते हैं। आज कांग्रेस के निष्ठावान कार्यकर्ता खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं क्योंकि पार्टी में केवल खास सिपहसालारों और विवादित चेहरों की ही चलती है।

श्रीमती पाण्डेय ने भाजपा में वरिष्ठ नेताओं व कार्यकर्ताओं के सम्मान की अटूट परम्परा का उल्लेख करते हुए बघेल द्वारा रामविचार नेताम और बृजमोहन अग्रवाल जैसे वरिष्ठ नेताओं का जिक्र करने पर पलटवार करते हुए कहा कि भाजपा एक परिवार है जहाँ हर कार्यकर्ता की भूमिका और वरिष्ठों का मार्गदर्शन सर्वोपरि है। हमारे नेता कैबिनेट में और संगठन में पूरी सक्रियता के साथ प्रदेश की सेवा कर रहे हैं। बघेल को भाजपा की चिंता करने की जरूरत नहीं है, बल्कि उन्हें इस बात की चिंता करनी चाहिए कि उनकी अपनी पार्टी के भीतर उनके खिलाफ जो अविश्वास का माहौल है, उससे वे कैसे निपटेंगे? श्रीमती पाण्डेय ने कहा कि जनता ने कांग्रेस के कुशासन और उनके भ्रष्टाचार को नकार दिया है। अब अपनी प्रासंगिकता बचाए रखने के लिए बघेल अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। बेहतर होगा कि वे अपनी पार्टी की टूटती कडियों को जोडने पर ध्यान दें, क्योंकि भाजपा का संगठन हमारे प्रदेश अध्यक्ष किरण देव के नेतृत्व में चट्टान की तरह एकजुट है और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ विकास के नए आयाम स्थापित कर रहा है।

भारत सरकार भूमि संसाधन विभाग के सचिव ने मुख्य सचिव से की सौजन्य भेंट

- **छत्तीसगढ़ में जलग्रहण, पीएम सिंचाई योजना, पंजीयन एवं स्टाम्प और राजस्व विभाग के कार्यकलापों की ली जानकारी**

रायपुर। भारत सरकार भूमि संसाधन विभाग के सचिव श्री नरेन्द्र भूषण ने आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में मुख्य सचिव श्री विकासशील से सौजन्य भेंट की। भेंट के दौरान जलग्रहण प्रबंधन पी.एम. कृषि सिंचाई, छत्तीसगढ़ भुईयां, पंजीयन एवं स्टाम्प ई-कोर्ट सहित छत्तीसगढ़ में सुशासन के लिए किये जा रहे नवाचारों के बारे में विस्तार से चर्चा की। इसी प्रकार से श्री भूषण ने छत्तीसगढ़ शासन के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, वाणिज्यिक कर पंजीयन एवं स्टांप और छत्तीसगढ़ राज्य जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन एजेंसी के अधिकारियों का बैठक लेकर विभागीय कार्यकलापों एवं प्रगति की विस्तार से समीक्षा की।

बैठक में राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की सचिव श्रीमती शम्मी आबिदी ने बताया कि छत्तीसगढ़ में भू-अभिलेखों की कम्प्यूटराईजेशन किया गया है। भूमि रिकार्ड के लिए मॉडर्न रिकार्ड रूम बनाये गये हैं। भू-नक्शों की भी डिजिटलाईजेशन किया गया है। रेवेन्यू ई-कोर्ट के जरिये राजस्व प्रकरणों का निराकरण किया जा रहा है। भुईयां पोर्टल पर डिजीटल किसान किताब अपडेट की गई है। कोई भी भूमि स्वामी भुईयां पोर्टल पर अपनी भूमि की जानकारी डाउनलोड कर सकता है। इसी प्रकार से ऑनलाईन भूमि का ऑटो डायवर्सन किया जा रहा है।

छत्तीसगढ़ के पंजीयन एवं स्टाम्प विभाग ने अपनी कार्यप्रणाली में आधुनिक तकनीक अपनाकर दस्तावेजों की रजिस्ट्री ई-पंजीयन द्वारा की जा रही हैं। रजिस्ट्री प्रक्रिया आसान एवं पारदर्शी और पेपरलेस की गई है। अब दस्तावेजों को ऑनलाईन उप पंजीयक को ऑनलाईन प्रस्तुत किया जा रहा है। व्हाट्सएप अलर्टस के माधयम से क्रेता-विक्रेता का अपॉइंटमेंट से लेकर रजिस्ट्री होने तक के सभी अपडेट्स प्राप्त हो जाते हैं। रजिस्ट्री की प्रति भी व्हाट्सएप से डाउनलोड की जा सकती है।

छत्तीसगढ़ राज्य जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन ऐजेंसी के अधिकारियों ने बताया कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-जलग्रहण क्षेत्र विकास घटक के तहत वर्ष 2021-22 में कुल 45 परियोजनाओं की स्वीकृति प्राप्त हुई है जिसमें कुल 27 जिलों के 43 विकासखंड में 387 माइक्रो वाटरशेड शामिल है।

कोर्ट परिसर में पुलिस का चेकिंग अभियान 2 युवक चाकू के साथ गिरफ्तार

रायपुर। राजधानी रायपुर के न्यायालय परिसर में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने और अपराधों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से पुलिस ने शुक्रवार को बड़ा आकस्मिक चेकिंग अभियान चलाया। यह विशेष अभियान न्यायालय की अनुमति से डीसीपी सेंट्रल जोन एवं क्राइम के निर्देश पर संचालित किया गया।

अभियान में मध्य जोन के विभिन्न थानों का स्टाफ, एसीसीयू, पुलिस लाइन के 100 से अधिक जवान और बीडीएस टीम शामिल रही। पुलिस ने न्यायालय परिसर में संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखते हुए व्यापक तलाशी अभियान चलाया। चेकिंग के दौरान परिसर में संदिग्ध रूप से घूमते और उपद्रव की आशंका वाले 6 लोगों के खिलाफ प्रतिबंधात्मक धाराओं के तहत कार्रवाई की गई। सभी आरोपियों के खिलाफ थाना सिविल लाइन में कार्रवाई के बाद एसीपी कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया।

अभियान के दौरान दो युवकों के पास से अवैध चाकू भी बरामद किए गए। पुलिस ने मयंक सोनी और विनोद सारथी को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 1-1 चाकू जब्त किया। दोनों आरोपियों के खिलाफ थाना सिविल लाइन में आर्म्स एक्ट के तहत अपराध दर्ज किया गया है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक न्यायालय परिसर की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आगे भी इस तरह के विशेष चेकिंग अभियान लगातार चलाए जाएंगे, ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके।

मैनपावर सप्लाई घोटाला : अनवर ढेबर की जमानत याचिका खारिज

- **हाई कोर्ट ने कहा- आर्थिक अपराध सामान्य नहीं, देश की अर्थव्यवस्था के लिए खतरा**

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने मैनपावर सप्लाई घोटाले में आरोपी अनवर ढेबर की जमानत याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि आर्थिक अपराध सामान्य अपराध नहीं होते, बल्कि ये समाज और देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने वाली सुनियोजित साजिश होते हैं।

मामला सीएसएमसीएल में कर्मचारियों के ओवरटाइम भुगतान में गड़बड़ी से जुड़ा है। ईडी की जांच में 28.80 लाख रुपए नकद मिले थे। आरोप है कि कर्मचारियों के ओवरटाइम के पैसे में भ्रष्टाचार किया गया। जांच के आधार पर एसीबी ने धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार का केस दर्ज किया है। अनवर ढेबर पर आरोप है कि उन्होंने अपने राजनीतिक

प्रभाव का इस्तेमाल कर सीएसएमसीएल के कामकाज और पैसों के फैसलों में दखल दिया।

जांच रिपोर्ट के मुताबिक, संस्था को मैनपावर सप्लाई करने वाली निजी एजेंसियों के बिल तब तक पास नहीं किए जाते थे, जब तक वे तय रकम कमीशन के रूप में नहीं देती थीं। शुरुआत में कमीशन तय दर पर लिया जाता था, लेकिन बाद में अनवर ढेबर के निर्देश पर इसे बढ़ाकर बिल राशि का एक-तिहाई या उससे ज्यादा कर दिया गया। आरोप है कि चुनाव के नाम पर अवैध वसूली और बढ़ाने के निर्देश भी दिए गए थे। इस मामले में निगम के तत्कालीन अधिकारियों और कुछ निजी लोगों पर पैसे पहुंचाने वाले माध्यम के तौर पर काम करने का आरोप है। वे एजेंसियों से रकम लेकर अनवर ढेबर तक पहुंचाते थे।

ईडी ने 29 नवंबर 2023 को ट्रैप कार्रवाई के दौरान ईगल हंटर सॉल्यूशंस एजेंसी के कर्मचारियों को 28.80 लाख रुपए की रिश्वत देते हुए पकड़ा था। इसी कार्रवाई में मिले सबूतों के आधार पर अनवर ढेबर को 23 फरवरी 2026 को गिरफ्तार किया गया। अनवर ढेबर ने इस मामले में जमानत के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।

हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि ऐसे मामलों में केवल इसलिए राहत नहीं दी जा सकती, क्योंकि आरोपी प्रभावशाली है या सीधे तौर पर धन की वसूली उसके पास से नहीं हुई है। जब मामला जनता के पैसे और सरकारी खजाने की लूट से जुड़ा हो, तो कोर्ट को अलर्ट रहना चाहिए। ऐसे घोटाले न केवल देश के आर्थिक ढांचे को नुकसान पहुंचाते हैं, बल्कि सरकारी व्यवस्था में जनता के विश्वास को भी चोट पहुंचाते हैं। कोर्ट ने ढेबर को इस मामले का मुख्य साजिशकर्ता और फायदा लेने वाला बताया है।

प्रधानमंत्री मोदी की अदूरदर्शिता के कारण देश में अफरा-तफरी : दीपक बैज

रायपुर। प्रधानमंत्री मोदी की अदूरदर्शी अपील के कारण देश में पेट्रोल डीजल को लेकर अफरा तफरी का माहौल बनाया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि प्रधानमंत्री ने अपने अपील के कारण पूरे देश में भय पैदा कर दिया, लोग पेट्रोल डीजल के संकट के भय से ग्रसित होकर पेट्रोल पंपों पर लाइन लगा रहे है। दूसरी तरफ देश भर के आधे पेट्रोल पंपो का ड्राई हो जाना भी लोगो में भय का बड़ा कारण है। सरकार के पास पर्याप्त स्टाक है, तो सरकार सप्लाई को सुचारू क्यों नहीं कर पा रही, यदि सभी पंपो में पर्याप्त मात्रा में पेट्रोल-डीजल मिलेगा तो लोग खुद ही कतार में नहीं लगेंगे।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि सरकार को पेट्रोल-डीजल का रेट बढ़ाना था, इसलिये यह ड्रामा किया गया। प्रधानमंत्री मोदी को

पेट्रोल-डीजल का रेट बढ़ाना था, तो उन्होंने उसके पहले संकट का पूरा माया जाल रचा, रेट तो बढ़ाया ही जनता को परेशान कर दिया।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि बचत करना एक अलग विषय है, लेकिन कमी होना अलग विषय है। प्रधानमंत्री ने बचत करने की अपील के साथ कमी को जोड़ दिया। जिससे हालात इतने भयावह बने है। यह मोदी की अदूरदर्शिता है, जिसका खामियाजा देश को भुगतना पड़ रहा है।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि इसके पहले भी नोटबंदी, जीएसटी और लॉकडाऊन के समय भी मोदी की अदूरदर्शिता देश की जनता पर भारी पड़ी थी। मोदी अपने आत्म प्रचार में तथा स्वंय को सबसे महान बताने के चक्कर में देश के सामने नया-नया संकट खड़ा करते है।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी से देश नहीं संभल रहा, देश ने पहले भी अनेकों ऐसे संकट देखे है, तब भारत की तत्कालीन सरकारों ने सूझबूझ से इन समस्याओं का सामना किया था। मोदी ने तो आज तक इस वैश्विक संकट पर विपक्षी दलों की बैठक तक नहीं बुलाई। जब उनसे स्थितियां नहीं संभल रही तो देश की जनता से कम उपयोग की अपील कर रहे है।

कार्यालय कार्यपालन अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, संभाग- कांकेर

Phone No. :- 07868-241213, Email Id : ee-res.kanker@gov.in

// मैनुअल पद्धति जोनल निविदा सूचना //

क्रमांक / 07 /व.ले.लि./ग्रा.यां.से./2026-27 कांकेर, दिनांक 12/05/2026.

एकीकृत पंजीयन प्रणाली अंतर्गत सक्षम श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों से निम्नलिखित निर्माण कार्य हेतु मैनुअल पद्धति जोनल निविदा दिनांक 27.05.2026 शाम 5.00 बजे तक पंजीकृत डाक स्पीड पोस्ट से (आमंत्रण क्रम प्रथम बार) आमंत्रित की जाती है तथा निविदा दिनांक 29.05.2026 को 11.30 बजे पूर्वान्ह में खोली जावेगी :-

क्र.	कार्य का नाम एवं स्थल	विकासखण्ड	जोन क्रमांक	ठेके की अनुमानित लागत (लाख मे)
1	2	3	4	5
1	विभिन्न मदों में स्वीकृत रू. 30.00 लाख तक लागत के भवन रंगमंच नाली / आहता / पुल / पुलिया एवं अन्य प्रकार के निर्माण कार्य (विद्युतीकरण कार्य छोड़कर) जिला-उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.) कांकेर	कांकेर	1	40.00 लाख
			2	40.00 लाख
			3	40.00 लाख
		भानुप्रतापपुर	1	40.00 लाख
			2	40.00 लाख
		कोयलीबेड़ा	1	40.00 लाख
			2	40.00 लाख
			3	40.00 लाख
		अंतागढ़	1	40.00 लाख
			2	40.00 लाख
		चारामा	1	40.00 लाख
		नरहरपुर	1	40.00 लाख
		दुर्गूकोंदल	1	40.00 लाख

2. उपरोक्त निर्माण कार्यों की निविदा की सामान्य शर्तें, धरोहर राशि, विस्तृत निविदा विज्ञप्ति, निविदा दस्तावेज (परिशिष्ट 2.10 एवं 2.13) व अन्य जानकारी विभागीय वेबसाईट http://res.cg.gov.in से डाउनलोड किये जा सकते है।

जी-262700718/6

कार्यपालन अभियंता,
ग्रामीण यांत्रिकी सेवा
संभाग - कांकेर

केरल के मुख्यमंत्री का चयन 10 दिन में

सनत जैन

पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव परिणाम आने के बाद सबसे अधिक चर्चा जिस मुद्दे को लेकर हुई, वह केवल जीत-हार तक सीमित नहीं रही, बल्कि कांग्रेस संगठन की कार्यप्रणाली और नेतृत्व क्षमता भी बहस के केंद्र में आ गई। विशेष रूप से केरल में कांग्रेस नीत यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (यूडीएफ) को स्पष्ट बहुमत मिलने के बावजूद मुख्यमंत्री के चयन में दस दिन का समय लगना राजनीतिक हलकों में चर्चा और आलोचना का विषय बन गया। गौरतलब है कि 4 मई को चुनाव परिणाम घोषित किए गए थे और कांग्रेस के पास सरकार बनाने के लिए पर्याप्त संख्या थी। बावजूद इसके पार्टी मुख्यमंत्री के नाम पर जल्दी निर्णय नहीं ले सकी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को विधायक दल के नेता के चयन का अधिकार पहले ही दे दिया गया था। उन्होंने विधायकों और वरिष्ठ नेताओं से चर्चा भी की, लेकिन आम सहमति नहीं बन सकी। अंतत: पार्टी को जयराम रमेश, मुकुल वासनिक, दीपा दासमुंसी और अजय माखन जैसे वरिष्ठ नेताओं को केरल भेजना पड़ा। दो दिन की मशक्कत के बाद वीडी सतीशन के नाम पर सहमति बनी और उनके मुख्यमंत्री बनने का रास्ता साफ हुआ। यह स्थिति उस पार्टी के लिए निश्चित रूप से चिंताजनक मानी जाएगी, जो कभी देश की सबसे मजबूत राजनीतिक शक्ति थी। केरल जैसे राज्य, जहां कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का सीधा राजनीतिक जुड़ाव रहा है, वहां भी नेतृत्व चयन को लेकर इतना लंबा गतिरोध कांग्रेस की आंतरिक स्थिति को उजागर करता है। विडंबना यह रही कि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (आईयूएमएल) और यूडीएफ के कई सहयोगी दल पहले ही वीडी सतीशन के समर्थन में खुलकर सामने आ चुके थे। सतीशन लंबे समय से कांग्रेस संगठन में सक्रिय रहे हैं और उन्हें जमीनी नेता माना जाता है। इसके बावजूद कांग्रेस के भीतर शक्ति संतुलन और गुटबाजी इतनी मजबूत रही कि निर्णय लेने में पार्टी नेतृत्व को अत्यधिक समय लग गया। दरअसल, कांग्रेस की सबसे बड़ी ताकत ही आज उसकी कमजोरी बनती दिखाई दे रही है। पार्टी के भीतर लोकतांत्रिक माहौल होने के कारण हर नेता अपनी बात खुलकर रखने और अपने हित साधने की कोशिश करता है। यदि उसकी बात नहीं मानी जाती तो कई बार वह पार्टी छोड़कर क्षेत्रीय दल बना लेता है या भाजपा में शामिल हो जाता है। कांग्रेस के केंद्र में सत्ता से बाहर होने के बाद यह प्रवृत्ति और तेज हुई है। आज कांग्रेस जिन राज्यों में मजबूत दिखाई देती है, वहां भी आंतरिक खींचतान उसके लिए चुनौती बनी हुई है। कर्नाटक इसका बड़ा उदाहरण है, जहां सरकार बनने के बाद भी मुख्यमंत्री पद को लेकर समय-समय पर विवाद सामने आते रहते हैं। कांग्रेस का बड़ा समय विपक्ष से लड़ने के बजाय अपने ही नेताओं के बीच संतुलन बनाने में निकल जाता है। यह भी सच है कि कांग्रेस आज भी देशभर में एक व्यापक जनाधार रखने वाली पार्टी है। केंद्र में रहते हुए भी भाजपा प्रत्येक राज्य में वैसी सामाजिक स्वीकार्यता नहीं बना सकी है जैसी कांग्रेस के पास दशकों से रही है। लेकिन कांग्रेस के भीतर निजी महत्वाकांक्षाएं और गुटीय संघर्ष उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई है। बहरहाल इन तमाम परिस्थितियों के बावजूद यदि पार्टी आंतरिक एकजुटता नहीं दिखा पाएगी, तो उसकी चुनौतियां और बढ़ेंगी। केरल में आखिरकार वीडी सतीशन के मुख्यमंत्री बनने का रास्ता साफ हो गया है। इसे देर आयद दुरुस्त आयद की स्थिति कहा जा सकता है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने यह जरूर स्पष्ट कर दिया कि कांग्रेस की सबसे बड़ी लड़ाई फिलहाल भाजपा से कम और अपने भीतर की राजनीति से अधिक है।

ट्रंप और जिनपिंग की दोस्ती ने बदल डाले वैश्विक समीकरण

नीरज कुमार दुबे

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चीन यात्रा बदलती विश्व व्यवस्था का ऐसा प्रतीक बनकर सामने आई जिसने वैश्विक राजनीति की दिशा पर नए सवाल खड़े कर दिए हैं। बीजिंग में राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ ट्रंप की लंबी बैठकों, व्यापारिक समझौतों, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और तकनीकी सहयोग पर चर्चा तथा अमेरिकी उद्योगपतियों की भारी मौजूदगी ने यह संकेत दिया कि तमाम टकरावों और आरोपों के बावजूद अमेरिका और चीन एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। इसी के साथ यह सवाल भी तेज हो गया है कि क्या इस यात्रा ने क्वॉड जैसे रणनीतिक समूहों के भविष्य पर भी अनिश्चितता पैदा कर दी है?

दिलचस्प बात यह है कि पिछले वर्ष जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शंघाई सहयोग संगठन सम्मेलन के दौरान शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की थी, तब ट्रंप ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि अमेरिका भारत को चीन और रूस के हाथों खो रहा है। यही नहीं, मोदी की चीन और रूस के नेताओं के साथ तस्वीरों को वाशिंगटन में रणनीतिक असहजता के रूप में देखा गया था। लेकिन अब वही ट्रंप खुद चीन की धरती पर शी जिनपिंग के साथ बैठकों में व्यस्त रहे। उनके साथ अमेरिका के सबसे बड़े उद्योगपति और तकनीकी कंपनियों के प्रमुख भी मौजूद रहे। ऐसे में यह सवाल स्वाभाविक है कि यदि भारत का चीन से संवाद अमेरिका के लिए भारत को खो देना था, तो फिर ट्रंप की अपनी चीन यात्रा को क्या कहा जाए? क्या यह अमेरिकी यथार्थवाद है, आर्थिक मजबूरी है या फिर वैश्विक शक्ति संतुलन की नई स्वीकारोक्ति है?

ट्रंप की इस यात्रा ने यह भी साफ कर दिया कि चीन को अलग थलग करने की अमेरिकी रणनीति अब पहले जैसी प्रभावी नहीं रह गई है। वहीं बीजिंग ने ट्रंप की इस यात्रा को केवल कूटनीतिक कार्यक्रम नहीं रहने दिया, बल्कि इसे अपनी तकनीकी, आर्थिक और सामरिक शक्ति के प्रदर्शन में बदल दिया। शहर की सड़कों पर चालक रहित विद्युत वाहन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित प्रणालियां, मानवरूपी रोबोट और डिजिटल विज्ञापन चीन की नई ताकत का प्रदर्शन कर रहे थे। चीन दुनिया को यह संदेश देना चाहता था कि अब वह केवल सस्ती वस्तुएं बनाने वाला देश नहीं बल्कि भविष्य की तकनीकों का नेतृत्व करने वाली शक्ति बन चुका है।

देखा जाये तो ट्रंप की यात्रा ऐसे समय हुई जब अमेरिका ईरान युद्ध के कारण कई मोर्चों पर दबाव में है। अमेरिकी खुफिया रिपोर्टों के अनुसार चीन ने ईरान संकट का उपयोग अपनी रणनीतिक स्थिति मजबूत करने के लिए किया है। होर्मुज जलडमरूमध्य संकट के बीच चीन ने ऊर्जा आपूर्ति और हथियारों के जरिये अपनी भूमिका बढ़ाई, जबकि अमेरिका युद्ध और आर्थिक दबावों में उलझा रहा। यही कारण है कि ट्रंप को अंतत: बीजिंग पहुंचकर शी जिनपिंग से संवाद करना पड़ा।

बीजिंग में हुई बातचीत के दौरान ताइवान सबसे बड़ा मुद्दा बनकर सामने आया। शी जिनपिंग ने साफ कहा कि यदि ताइवान के मुद्दे को ठीक ढंग से नहीं संभाला गया तो दोनों देशों के बीच टकराव और संघर्ष हो सकता है। यह बयान केवल चेतावनी नहीं था बल्कि बदलते शक्ति संतुलन का संकेत भी था। चीन अब अमेरिका से बराबरी की भाषा में बात कर रहा है।

ट्रंप की प्राथमिकता हालांकि व्यापार और निवेश रही। उनके साथ एलन मस्क, जेन्सन हुआंग और अन्य अमेरिकी उद्योगपति भी पहुंचे। यह इस बात का संकेत था कि अमेरिकी उद्योग जगत चीन से दूरी नहीं चाहता। दुनिया की सबसे बड़ी उपभोक्ता अर्थव्यवस्था और विशाल तकनीकी बाजार से अलग होना अमेरिका के लिए आसान नहीं है।

व्हाइट हाउस की ओर से जारी आधिकारिक बयान ने भी यह स्पष्ट कर दिया कि ट्रंप की चीन यात्रा के दौरान दोनों देशों ने कई संवेदनशील मुद्दों पर व्यावहारिक सहयोग की दिशा में आगे बढ़ने के संकेत दिए। बयान के अनुसार ट्रंप और शी जिनपिंग ने अमेरिकी कंपनियों के लिए चीन में बाजार पहुंच बढ़ाने, चीन के निवेश को अमेरिका में प्रोत्साहित करने और कृषि उत्पादों की खरीद बढ़ाने पर चर्चा की। दोनों देशों ने होर्मुज जलडमरूमध्य को खुला रखने और ऊर्जा आपूर्ति बाधित न होने देने पर भी सहमति जताई। चीन ने जलडमरूमध्य के सैन्यीकरण का विरोध दोहराया, जबकि ईरान को परमाणु हथियार हासिल नहीं करने देने पर भी साझा रुख सामने आया। यह बयान इस बात का संकेत है कि तीखी प्रतिस्पर्धा और रणनीतिक अविश्वास के बावजूद अमेरिका और चीन वैश्विक अर्थव्यवस्था तथा ऊर्जा सुरक्षा जैसे मुद्दों पर टकराव के बजाय नियंत्रित सहयोग की राह भी तलाश रहे हैं।

यही वह बिंदु है जहां क्वॉड का भविष्य भी सवालों में घिरता दिखाई देता है। क्वॉड को लंबे समय से हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के प्रभाव को संतुलित करने वाले समूह के रूप में देखा जाता रहा है। भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की यह साझेदारी चीन को लेकर साझा रणनीतिक चिंता पर आधारित मानी जाती है। लेकिन यदि अमेरिका का राष्ट्रपति खुद चीन के साथ संबंधों को स्थिर करने, व्यापार बढ़ाने और तकनीकी सहयोग तलाशने बीजिंग पहुंचता है, तो फिर क्वॉड की वास्तविक दिशा क्या रह जाएगी?

भारत के लिए यह प्रश्न और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। पिछले कुछ वर्षों में नई दिल्ली ने क्वॉड को अपनी हिंद प्रशांत रणनीति का अहम हिस्सा बनाया है। लेकिन ट्रंप की चीन यात्रा यह संकेत देती है कि अंतत: अमेरिका अपने राष्ट्रीय हितों के आधार पर ही निर्णय लेगा। यदि आर्थिक या सामरिक कारणों से उसे चीन के साथ समझौता करना पड़े, तो वह पीछे नहीं हटेगा। ऐसे में भारत को यह समझना होगा कि वैश्विक राजनीति स्थायी मित्रताओं से अधिक स्थायी हितों पर चलती है।

ट्रंप की यात्रा ने एक और महत्वपूर्ण तथ्य उजागर किया है। अमेरिका और चीन के बीच प्रतिस्पर्धा अब केवल व्यापार युद्ध तक सीमित नहीं है। यह तकनीक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ऊर्जा, दुर्लभ खनिज, चिप निर्माण, समुद्री मार्गों और वैश्विक प्रभाव की व्यापक लड़ाई बन चुकी है। लेकिन इस प्रतिस्पर्धा के बीच दोनों देश एक दूसरे पर निर्भर भी हैं। अमेरिका चीन को रोकना चाहता है, लेकिन उसकी कंपनियां चीन के बाजार और विनिर्माण क्षमता से अलग नहीं हो पा रहीं। दूसरी ओर चीन अमेरिकी तकनीक और वैश्विक वित्तीय संरचना से पूरी तरह अलग नहीं हो सकता।

इसीलिए बीजिंग में ट्रंप और शी जिनपिंग की मुलाकात केवल दो नेताओं की बैठक नहीं थी। यह उस नई विश्व व्यवस्था की झलक थी जिसमें प्रतिद्वंद्विता और सहयोग साथ-साथ चलेंगे। दोनों देश सार्वजनिक रूप से एक दूसरे को चुनौती देंगे, लेकिन आर्थिक और तकनीकी स्तर पर पूरी तरह अलग भी नहीं होंगे।

इस पूरी प्रक्रिया में भारत की स्थिति बेहद जटिल हो जाती है। एक ओर वह अमेरिका के साथ सामरिक साझेदारी मजबूत कर रहा है, दूसरी ओर रूस से ऊर्जा खरीद जारी रखता है और चीन के साथ संवाद भी बनाए हुए है। ट्रंप की चीन यात्रा भारत को यह संदेश भी देती है कि वैश्विक राजनीति में किसी एक धुरी पर पूरी तरह निर्भर रहना जोखिम भरा हो सकता है।

बहरहाल, ट्रंप की बीजिंग यात्रा ने यह स्पष्ट कर दिया है कि 21वीं सदी की विश्व राजनीति का केंद्र अब अमेरिका चीन संबंध ही होंगे। यही संबंध तय करेंगे कि वैश्विक अर्थव्यवस्था किस दिशा में जाएगी, तकनीकी नेतृत्व किसके हाथ में रहेगा और भविष्य की विश्व व्यवस्था कैसी होगी। लेकिन इसके साथ ही यह यात्रा एक बड़ा सवाल भी छोड़ गई है कि यदि अमेरिका खुद चीन के साथ अपने रिश्तों को नए सिरे से गढ़ रहा है, तो फिर दुनिया के बाकी देशों से वह किस प्रकार की रणनीतिक निष्ठा की अपेक्षा कर सकता है?

पुराण दिग्दर्शन ....

सन्देहाभासनिकारणाध्यायः (नौवां अध्याय)

(गतांक से आगे...)

स तस्यां जनयायास पुरूरवसमात्मजम्।।35।।
एवं स्त्रीत्वमनुप्राप्तः सुद्युम्नो मानवो नृपः।
सस्मार स्वकुलाचार्य्य वसिष्ठमिति शुश्रुमः।। 36॥
स तस्य तां दशां दृष्ट्वा कृपया भृशपीडितः।
सुद्युम्नस्याशयन्पुंस्त्वमुपाधावत शङ्करम्।। 37।।
तुष्टस्तस्मै स भगवान्नृषये प्रियमावहन् ।।38।।
मांसं पुमान्स भविता मासं स्त्री तव गोत्रजः।। 39॥
(श्रीमद्भागवत 6 । 1)

अर्थात् पुराने समय में महर्षि वसिष्ठ ने सन्तानरहित मनु राजा को वंश वृद्धि के लिए मित्रावरुण% का यज्ञ रचा॥13॥ मनु की घर्म-पत्नी श्रद्धा ने [एकान्त में] होता यज्ञाचार्य्य से कन्या उत्पन्न होने की प्रार्थना की।।14।। अत: होता की तादृश भावना से उक्त रानी से पुत्र के बजाय इला नाम वाली कन्या उत्पन्न हुई, जिसे देखकर विमनस्क हुये मनु ने वसिष्ठ जी से शिकायत की।।16।॥ [वसिष्ठ जी ने रानी और होता की विपरीत भावना से कन्या की उत्पत्ति बता कर इला के पुरुष बन जाने की इच्छा से आदिपुरुष परमात्मा की स्तुति की ॥21॥

इससे प्रसन्न होकर भगवान् ने इसे इच्छित वर दिया, जिसके प्रताप से इला स्त्रीत्व को छोड़ कर सुद्युम्न नामक राजकुमार बन गई ॥22॥ एक बार राजकुमार सुद्युम्न शिकार खेलते हुये ॥ 23॥ उस स्थान में जा पहुँचे - जहां कि भगवान् शङ्कर पार्वती सहित रमण करते थे।। 25।।

(इस स्थान के ताट्य प्रभाव से सुद्युम्न ने देखा कि वह स्वयं स्त्री बना हुआ है और उसका घोड़ा भी घोड़ी बन गया है ।। 26।। इस तरह अपने साथियों सहित स्त्रीभावापन्न सुद्युम्न को वन में घूमता अथवा घूमती हुई देखकर बुध ने उसको चाहा ॥ 34।॥ इस तरह बुध के संयोग से उक्त इला में पुरूरवा नामक पुत्र उत्पन्न हुआ ।। 35।

क्रमशः ...

अंतरराष्ट्रीय प्रकाश दिवस

सुनील कुमार महला

हर वर्ष 16 मई को अंतरराष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया जाता है। पाठकों को बताता चलूं कि यह दिवस विज्ञान, शिक्षा, संस्कृति, ऊर्जा, चिकित्सा, संचार जैसे क्षेत्रों में और देश व समाज के सतत विकास(सस्टेनेबल डेवलपमेंट) के क्रम में प्रकाश के महत्व को समझाने और प्रकाश के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से हर साल मनाया जाता है। वास्तव में प्रकाश से तात्पर्य केवल और केवल भौतिक रोशनी से नहीं है, बल्कि यह ज्ञान, जागरूकता, आशा, नवाचार और मानव प्रगति का प्रतीक भी है। धर्म, भाषा और सीमाओं से परे प्रकाश सार्वभौमिक(यूनिवर्सल) है तथा कला से लेकर दर्शन तक इसे सदैव ज्ञान और सकारात्मकता के प्रतीक के रूप में देखा गया है। सच तो यह है कि आधुनिक जीवन की रीढ़ ही प्रकाश है और बिना प्रकाश विज्ञान के आज डिजिटल इंडिया, वैश्विक कनेक्टिविटी तथा आधुनिक तकनीक की कल्पना भी संभव नहीं है। वास्तव में, अंतरराष्ट्रीय प्रकाश दिवस केवल एक वैज्ञानिक उपलब्धि यानी लेज़र के सफल संचालन का ही उत्सव नहीं है, बल्कि यह मानवता के अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ने की यात्रा का भी प्रतीक है। कहना ग़लत नहीं होगा कि यह दिवस विज्ञान और मानवता के बीच एक सेतु का कार्य करता है तथा हमें ज्ञान, विज्ञान और सकारात्मक सोच का प्रकाश फैलाने की प्रेरणा देता है।

पाठक जानते होंगे कि भारतीय संस्कृति में भी प्रकाश को अत्यंत पवित्र और ज्ञानदायी माना गया है। उपनिषदों का प्रसिद्ध मंत्र तमसो मा ज्योतिर्गमय अर्थात् हे प्रभु! हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो के बारे में आखिर कौन है जो नहीं जानते ? प्रकाश केवल बाहरी अंधकार से उजाले की ही बात नहीं करता है, बल्कि यह मनुष्य के अज्ञान, भय, भ्रम और नकारात्मकता से ज्ञान, सत्य और सकारात्मकता की ओर लगातार बढ़ने का संदेश देता है और आज के समय में तो यह संदेश और भी प्रासंगिक हो जाता है। हमारे यहां दिवाली प्रकाश का सबसे बड़ा त्योहार है, जबकि लोक संस्कृति में लालटेन उत्सव भी उजाले, आशा और मानवीय संवेदनाओं का प्रतीक माना जाता है। इतना ही नहीं, सामाजिक जीवन में शिक्षा, जागरूकता और नैतिक मूल्यों का प्रकाश समाज को आगे बढ़ाने का कार्य करता है।

बहरहाल, यदि हम यहां पर इस दिवस के मुख्य उद्देश्यों की बात करें तो, अंतरराष्ट्रीय प्रकाश दिवस का मुख्य उद्देश्य प्रकाश विज्ञान और ऑप्टिकल तकनीकों के महत्व के प्रति जागरूकता बढ़ाना, विज्ञान और तकनीक को समाज के विकास से जोड़ना, ऊर्जा, स्वास्थ्य, इंटरनेट और संचार में प्रकाश आधारित तकनीकों के योगदान को रेखांकित करना, युवाओं को विज्ञान एवं अनुसंधान के प्रति प्रेरित करना तथा देशों के बीच वैज्ञानिक सहयोग और शांति को बढ़ावा देना है। यूनेस्को के अनुसार यह दिवस विज्ञान, संस्कृति, कला, शिक्षा और सतत विकास में प्रकाश की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करता है। वास्तव में यह दिवस इस बात की याद दिलाता है कि विज्ञान और तकनीक का सही उपयोग मानव कल्याण, शांति और सतत विकास के लिए कितना आवश्यक है।

ब्रिक्स के विदेश मंत्रियों के दिल्ली-विमर्श के निहितार्थ

कमलेश पांडे

ब्रिक्स के विदेश मंत्रियों की दो दिवसीय दिल्ली बैठक ने दुनिया को कई महत्वपूर्ण राजनीतिक, आर्थिक और सामरिक संदेश दिए हैं, जिनके कूटनीतिक निहितार्थ को समझने की जरूरत है। अन्यथा शेष दुनिया को अमेरिकी-यूरोपीय दादागिरी (नाटो सैन्य गठबंधन) के दुनियावी दांवपेंचों से निजात मिलनी मुश्किल है। लिहाजा, इस बैठक में मुख्य रूप से वैश्विक शक्ति-संतुलन, अमेरिकी प्रतिबंध नीति, पश्चिम एशिया संकट, वैश्विक व्यापार व्यवस्था और ग्लोबल साउथ की भूमिका पर जोर दिखाई दिया।

देखा जाए तो नई दिल्ली में ब्रिक्स के विदेश मंत्रियों का जमावड़ा लगा हुआ है। दो दिनों का यह 18वां शिखर सम्मेलन ऐसे समय हो रहा है, जब दुनिया कई मोर्चे पर अस्थिरता से गुजर रही है। ब्रिक्स के सदस्य देश - ईरान और यूएई सीधे तौर पर इस हलचल में शामिल है। ऐसे में यह जुटान पूरी दुनिया के लिए अहम हो जाती है। इस अहम बैठक में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर, रूस के विदेश मंत्री सर्जेई लावरोव और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची जैसे नेताओं के दूरदर्शिता भरे बयान विशेष चर्चा में रहे। जिसके दुनियावी मायने बेहद अहम हैं।

जिस तरह से कूटनीतिक सम्मेलन के पहले ही दिन जयशंकर ने अंतरराष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र चार्टर के खिलाफ लगाए जाने वाले एकतरफा प्रतिबंधों का जिक्र किया, जो सबसे ज्यादा विकासशील देशों को नुकसान पहुंचाते हैं। स्वाभाविक तौर पर उनका इशारा अमेरिका है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीतियों की वजह से दुनिया को बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा है। वहीं, ईरान मामले में भी गतिरोध की वजह बहुत हद तक वॉशिंगटन की अव्यवहारिक मांगें है। ब्रिक्स के बड़े मंच से उठी आवाज का असर ज्यादा होगा।

विदेश मंत्री एस जयशंकर का उद्घाटन भाषण मौजूदा चुनौतियों का सही खाका खींचता है। पश्चिम

एशिया पर मंडराता युद्ध का खतरा, ऊर्जा संकट, सप्लाई चेन में रुकावट और जलवायु परिवर्तन ने अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को एक नए मोड़ पर ला खड़ा किया है। तमाम देशों की अर्थव्यवस्था को मंदी में फंसने का डर सता रहा है। ऐसे में जैसा कि विदेश मंत्री ने कहा, विकासशील देशों ने ब्रिक्स से यह उम्मीद लगाई है कि यह मंच स्थिरता कायम करने में सकारात्मक भूमिका अदा करेगा। इसके कतिपय निहितार्थ इस प्रकार हैं-

पहला, एकध्रुवीय विश्व व्यवस्था को चुनौती: बैठक का सबसे बड़ा संदेश यह था कि दुनिया अब केवल अमेरिका-केन्द्रित व्यवस्था पर निर्भर नहीं रहना चाहती। ब्रिक्स देशों ने मल्टीपोलर वर्ल्ड के दृष्टिगत बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था की आवश्यकता पर जोर दिया। इसका अर्थ है कि वैश्विक निर्णयों में पश्चिमी देशों के साथ एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका की शक्तियों की भी बराबर भूमिका हो।

दूसरा, अमेरिकी प्रतिबंधों और आर्थिक दबाव का विरोध: भारत, रूस, चीन और ईरान सहित कई देशों ने एकतरफा प्रतिबंधों को अंतरराष्ट्रीय व्यापार और संप्रभुता के खिलाफ बताया। विशेष रूप से एस जयशंकर ने कहा कि प्रतिबंध और दबाव कूटनीति का विकल्प नहीं हो सकते। यह संदेश सीधे तौर पर अमेरिका की प्रतिबंध नीति की आलोचना माना गया।

तीसरा, डॉलर प्रभुत्व कम करने का संकेत: बैठक में स्थानीय मुद्राओं में व्यापार बढ़ाने और वैकल्पिक भुगतान प्रणालियों पर भी चर्चा हुई। यह संदेश था कि ब्रिक्स देश डॉलर पर निर्भरता कम करना चाहते हैं ताकि अमेरिकी आर्थिक दबाव का असर घटाया जा सके।

चतुर्थ, पश्चिम एशिया संकट पर चिंतन : ईरान-इज़राइल तनाव और समुद्री मार्गों की सुरक्षा बड़ा मुद्दा रहा। ब्रिक्स देशों ने रेड सी और होर्मुज़ जलडमरूमध्य जैसे मार्गों की सुरक्षा पर जोर दिया। दुनिया को यह संदेश दिया गया कि क्षेत्रीय युद्ध अब वैश्विक अर्थव्यवस्था और ऊर्जा सुरक्षा को सीधे प्रभावित कर सकते हैं। हालांकि इस मंच के सामने भी चुनौती है। ईरान और यूएई के आपसी रिश्ते ठीक नहीं चल रहे। जबकि चीन ने अपने विदेश मंत्री को नहीं भेजा है।

एक बात और, जब सम्मेलन की शुरुआत हुई, चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग तब ट्रंप की मेजबानी में व्यस्त थे। ब्रिक्स के सबसे बड़े विरोधी ट्रंप है। उन्हें लगता है कि यह मंच अमेरिकी हितों के खिलाफ खड़ा किया गया है। मेजबान होने के नाते यह भारत की जिम्मेदारी है कि यहां से निकला संदेश किसी के विरोध में नहीं, साझा हित में हो। भारत के पास सभी सदस्यों को करीब लाने और मौजूदा संकट का समाधान पेश करने का मौका है।

पांचवां, ग्लोबल साउथ की राजनीतिक आवाज : बैठक में यह स्पष्ट हुआ किब्रिक्स स्वयं को केवल आर्थिक समूह नहीं, बल्कि विकासशील देशों की सामूहिक राजनीतिक आवाज के रूप में स्थापित करना चाहता है। अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका के देशों की समस्याओं—जैसे खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा संकट और कर्ज—को वैश्विक एजेंडा में प्रमुखता देने की बात कही गई।

छठा, संयुक्त राष्ट्र सुधार की मांग : भारत और ब्राजील ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार और विकासशील देशों के अधिक प्रतिनिधित्व की आवश्यकता दोहराई। यह संदेश था कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बनी संस्थाओं में अब नई वैश्विक वास्तविकताओं के अनुसार बदलाव होना चाहिए।

सातवां, ब्रिक्स के भीतर मतभेद भी सामने आए : हालांकि बैठक में एकजुटता दिखाई गई, लेकिन यह भी स्पष्ट हुआ कि सभी सदस्य अमेरिका-विरोधी नीति पर पूरी तरह एकमत नहीं हैं। भारत और ब्राजील जैसे देश पश्चिम के साथ संतुलित संबंध बनाए रखना चाहते हैं, जबकि रूस और ईरान अधिक आक्रामक रुख चाहते हैं। इससे यह संकेत मिला कि ब्रिक्स अभी पूर्ण राजनीतिक गठबंधन नहीं, बल्कि साझा हितों वाला मंच है।

समग्र रूप से कहा जाए तो, इस बैठक का वैश्विक संदेश यह था कि उभरती शक्तियाँ अब विश्व राजनीति और अर्थव्यवस्था में अधिक स्वतंत्र, संतुलित और पश्चिम से अलग भूमिका चाहती हैं। ब्रिक्स ने यह दिखाने की कोशिश की कि ग्लोबल साउथ अब केवल दर्शक नहीं, बल्कि वैश्विक शक्ति-संतुलन का सक्रिय खिलाड़ी बनना चाहता है। चूंकि ब्रिक्स अब केवल उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं का समूह नहीं रहा, इसकी भूमिका आज कहीं ज्यादा व्यापक हो चुकी है।

वास्तव में यह वैश्विक संतुलन स्थापित करने में महत्वपूर्ण हो सकता है। भारत का रोल इसमें सबसे अहम हो जाता है। उसने पश्चिमी देशों के साथ रिश्ते बनाए हुए हैं, जबकि रूस, ईरान और चीन के साथ भी बैलेंस रखा है। उसने हमेशा संवाद से समाधान की बात की है। यह रवैया उसे भरोसेमंद साथी बनाता है।

आज का इतिहास

1862 जीन जोसेफ एटिनी लेनोयर पहला ऑटोमोबाइल तैयार किया।
1869 सिनसिनाटी रेड्स ने अपना पहला बेसबॉल गेम 41-7 से जीता।
1872 मेट्रोपॉलिटन गैस कंपनी का लैंप पहली बार जलाया गया।
1875 वेनेजुएला और कोलंबिया में भूकंप से 16 हजार लोगों की मौत हुई।
1877 1877 फ्रांस में राजनीतिक संकट आरम्भ हुआ।
1916 यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस ने साइक्स-पिकोट समझौते पर हस्ताक्षर किए, एक गुप्त समझौते पर विचार किया गया जो मध्य पूर्व को आकार देता है, इराक और सीरिया की सीमाओं को परिभाषित करता है।
1918 संयुक्त राज्य अमेरिका में सेडिशन एक्ट पारित किया गया, संयुक्त राज्य सरकार, ध्वज, या सशस्त्र बल के बारे में संयुक्त राज्य सरकार, ध्वज, या सशस्त्र बल का उपयोग करने के लिए अव्यवस्थित, अपवित्र, अपमानजनक या अपमानजनक का उपयोग करने से मना किया।
1919 अमेरिकी नौसेना का विमान कर्टिस NC-4, 16 मई, 1919 को ट्रांसअटलांटिक फ़्लाइट अभियान को पूरा करने वाला पहला विमान बन गया।
1920 एक जनमत संग्रह स्विट्जरलैंड के लीग ऑफ नेशंस में शामिल हुआ।
1929 प्रथम अकादमी पुरस्कार (स्टैचू चित्रित) समारोह को लॉस एंजिल्स में हॉलीवुड रूजवेल्ट होटल में आयोजित किया गया था।
1943 द्वितीय वायु युद्ध के दौरान ऑपरेशन चेजिस में जर्मन बांधों पर बमों को तैनात करने के लिए रॉयल एयर फोर्स डैंबर्स ने छापेमारी की।
1948 चेम वीज़ामेन इजरायल के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुने गए।
1960 रूबी लेजर, पहला काम करने वाला ठोस-राज्य लेजर, का आविष्कार 16 मई, 1960 को थियोडोर मैमन द्वारा ह्यूजेस रिसर्च लेबोरेटरीज में कैलिफोर्निया के मालिबू में किया गया था। इस उपकरण को ऑप्टिकल मेसर की अवधारणा पर बनाया गया था।
1960 अमेरिकी भौतिक विज्ञानी थियोडोर मैमन ने कैलिफोर्निया के मालिबू में ह्यूजेस रिसर्च लेबोरेटरीज में पहली वर्कशॉप संचालित की।
1961 पार्क चुंग-ही के नेतृत्व में सैन्य क्रांति समिति ने दक्षिण कोरिया के द्वितीय गणराज्य को समाप्त करने के लिए यूं बो-सियोन की सरकार के खिलाफ रक्तहीन तख्तापलट किया।

राष्ट्रहित पर राजनीति और कांग्रेस की दोहरी मानसिकता

कांतिलाल मांडोत

भारत के राजनीतिक इतिहास में ऐसे कई अवसर आए हैं जब देश ने कठिन परिस्थितियों का सामना किया और जनता ने अपने नेतृत्व पर भरोसा करते हुए त्याग किया। आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक युद्ध संकट, बढ़ती तेल कीमतों और विदेशी मुद्रा पर पड़ रहे दबाव को देखते हुए देशवासियों से पेट्रोल-डीजल की बचत करने, सोने की खरीद कम करने और अनावश्यक विदेश यात्राएं टालने की अपील की, तब कांग्रेस और उसके नेता राहुल गांधी इसे सरकार की विफलता बताने लगे। यह वही कांग्रेस है जो अपने इतिहास के सबसे बड़े उदाहरणों को भी भूल चुकी है।

देश को यह नहीं भूलना चाहिए कि भारत ने संकट के समय हमेशा सामूहिक त्याग और अनुशासन के बल पर विजय प्राप्त की है। वर्ष 1965 में जब देश खाद्यान्न संकट से जूझ रहा था, तब तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने देशवासियों से सप्ताह में एक दिन उपवास रखने की अपील की थी। उस समय अमेरिका भारत को शर्तों के साथ अनाज देने को तैयार था, लेकिन शास्त्री जी ने इसे देश के स्वाभिमान के खिलाफ माना। उन्होंने पहले अपने परिवार पर प्रयोग किया और फिर पूरे देश से कहा कि एक समय भोजन छोड़कर राष्ट्र को आत्मनिर्भर बनाने में सहयोग करें। उस दौर में जनता ने बिना सवाल किए इस अपील को स्वीकार किया। गांवों से लेकर शहरों तक लोगों ने एक वक्त का भोजन त्याग दिया ताकि देश विदेशी दबाव के सामने झुके नहीं।

यह घटना केवल इतिहास नहीं बल्कि भारतीय समाज की राष्ट्रभक्ति और अनुशासन का सबसे बड़ा प्रमाण है। उस समय कांग्रेस के नेताओं और विपक्ष ने इसे 卐विफलता卐 नहीं कहा था। किसी ने यह आरोप नहीं लगाया था कि प्रधानमंत्री जनता पर बोझ डाल रहे हैं। क्योंकि उस समय राजनीति से ऊपर राष्ट्रहित था। लेकिन आज कांग्रेस की राजनीति इतनी संकुचित हो चुकी है कि यदि देशहित में कोई अपील की जाती है तो उसे भी राजनीतिक चश्मे से देखा जाता है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से जो अपीलें की हैं, उनका उद्देश्य किसी पर बोझ डालना नहीं बल्कि वैश्विक संकट से देश को सुरक्षित रखना है। दुनिया इस समय युद्ध और आर्थिक अस्थिरता के दौर से गुजर रही है। पश्चिम एशिया में तनाव के कारण कच्चे तेल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा आयात करता है। ऐसे में यदि प्रधानमंत्री लोगों से ईंधन की बचत करने, कारपूलिंग अपनाने, मेट्रो का उपयोग बढ़ाने और प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ने की बात करते हैं तो यह दूरदर्शिता है, विफलता

नहीं।

कांग्रेस की समस्या यह है कि वह हर राष्ट्रीय मुद्दे में केवल राजनीतिक लाभ खोजती है। जब देश आत्मनिर्भर भारत की दिशा में आगे बढ़ रहा है, तब कांग्रेस उसे रोकने का प्रयास करती दिखाई देती है। मोदी सरकार ने पिछले वर्षों में भारत को जिस ऊंचाई तक पहुंचाया है, वह पूरी दुनिया देख रही है। आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। देश डिजिटल क्रांति में अग्रणी बन चुका है। करोड़ों गरीबों के बैंक खाते खुले, गांवों तक बिजली पहुंची, मुफ्त राशन योजना से गरीबों को सुरक्षा मिली और भारत वैश्विक मंचों पर मजबूत आवाज बनकर उभरा।

कांग्रेस के शासनकाल में भारत को हर छोटे संकट में विदेशी संस्थाओं और देशों के सामने झुकना पड़ता था। कभी अमेरिका के दबाव में निर्णय लिए जाते थे तो कभी अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं की शर्तों पर देश की नीतियां तय होती थीं। लेकिन आज भारत दुनिया को आंखों में आंखें डालकर जवाब देता है। यही कारण है कि प्रधानमंत्री मोदी आत्मनिर्भरता की बात करते हैं। वे चाहते हैं कि भारत विदेशी निर्भरता कम करे और अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाए।

सोने के आयात को कम करने की अपील भी इसी सोच का हिस्सा है। भारत हर वर्ष भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा सोने के आयात पर खर्च करता है। यदि संकट के समय कुछ समय के लिए संयम बरता जाए तो उससे देश की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। इसी तरह पेट्रोल और डीजल की बचत केवल आर्थिक नहीं बल्कि पर्यावरणीय आवश्यकता भी है। दुनिया के विकसित देश भी ऊर्जा बचत के लिए जनता से अपील करते हैं। लेकिन भारत में कांग्रेस हर सकारात्मक प्रयास का मजाक उड़ाने लगती है।

राहुल गांधी का यह कहना कि 卐देश चलाना मोदी के बस की बात नहीं卐 वास्तव में उनकी राजनीतिक हताशा को दर्शाता है। जनता जानती है कि मोदी सरकार ने कठिन परिस्थितियों में भी देश को मजबूत बनाया है। कोरोना महामारी के समय भारत ने न केवल अपने नागरिकों को वैक्सीन दी बल्कि दुनिया के कई देशों की मदद भी की। सीमाओं पर भारत की ताकत बढ़ी है। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता आई है। अंतरिक्ष से लेकर तकनीक तक भारत नई ऊंचाइयों को छू रहा है। यह सब किसी कमजोर नेतृत्व में संभव नहीं होता।

सच्चाई यह है कि कांग्रेस आज भी पुराने राजनीतिक ढर्रे से बाहर नहीं निकल पाई है। उसे लगता है कि केवल आलोचना करके जनता का समर्थन मिल जाएगा। लेकिन देश अब बदल चुका है। जनता समझती है कि राष्ट्रहित में कभी-कभी सामूहिक जिम्मेदारी निभानी पड़ती है। जिस तरह लालबहादुर शास्त्री की अपील को देश ने स्वीकार किया था, उसी तरह आज भी लोग समझते हैं कि संकट के समय देश के साथ खड़ा होना आवश्यक है।

विडंबना यह है कि कांग्रेस अपने ही नेताओं की विरासत भूल चुकी है। यदि शास्त्री जी आज जीवित होते तो शायद कांग्रेस उन्हें भी 卐विफल प्रधानमंत्री卐 कह देती। क्योंकि आज की कांग्रेस का उद्देश्य राष्ट्रहित नहीं बल्कि केवल सत्ता प्राप्ति रह गया है। वह हर उस कदम का विरोध करती है जिससे भारत मजबूत बनता है।

भारत आज जिस दिशा में आगे बढ़ रहा है, वह आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता की दिशा है। दुनिया भारत को नई आशा के रूप में देख रही है। वैश्विक संस्थाएं भारत की आर्थिक क्षमता की सराहना कर रही हैं। विदेशी निवेश लगातार बढ़ रहा है। भारतीय तकनीक, उद्योग और युवाशक्ति दुनिया में अपनी पहचान बना रहे हैं। ऐसे समय में देश को नकारात्मक राजनीति नहीं बल्कि सकारात्मक सोच की आवश्यकता है।

राष्ट्र निर्माण केवल सरकार का काम नहीं होता। उसमें जनता की भी भूमिका होती है। यदि देशहित में कुछ समय के लिए संयम बरतने की अपील की जाती है तो उसे राजनीति का मुद्दा बनाने के बजाय राष्ट्रीय जिम्मेदारी के रूप में देखना चाहिए। भारत ने हमेशा त्याग, अनुशासन और एकता के बल पर चुनौतियों को हराया है और आगे भी हर संकट से मजबूती के साथ बाहर निकलेगा।

ट्रंप का चीन दौरा भू-राजनीतिक बदलाव का संकेत

ज्योति भास्कर

ईरान युद्ध की पृष्ठभूमि में जब विभिन्न अर्थव्यवस्थाएं अनिश्चितताओं से घिरी हैं और महाशक्तियों समेत विभिन्न देश एक किस्म के अविश्वास के दौर से गुजर रहे हैं, तब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बीजिंग यात्रा द्विपक्षीय संबंधों के लिहाज से तो महत्वपूर्ण है ही, वैश्विक भू-राजनीति की दृष्टि से भी इसके संदेश अहम हैं।

इस यात्रा का महत्व इससे भी समझा जा सकता है कि पिछले तकरीबन एक दशक में यह पहली बार है, जब कोई अमेरिकी राष्ट्रपति पद पर रहते हुए चीन पहुंचा हो। कई बार टलने के बाद अब अगर दो बड़े वैश्विक नेता वार्ता के लिए तैयार हुए हैं, तो इसका अर्थ ही है कि वे आश्वस्त हैं कि रणनीतिक प्रतिस्पर्धा को खतरनाक टकराव में बदलने से रोकने के लिए सीधी बातचीत जरूरी है। हालांकि यह मान लेना जल्दबाजी होगी कि ट्रंप की यात्रा से दोनों देशों के बीच गहरे मतभेद आसानी से खत्म हो जाएंगे।

ताइवान का मुद्दा संवेदनशील है, जिसे सैन्य समर्थन देने के मामले में चीन अमेरिका से, वहीं हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीनी सक्रियता के मद्देनजर अमेरिका चीन से अधिक संयम बरतने की मांग कर सकता है। इसके अतिरिक्त, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सेमीकंडक्टर तकनीक और साइबर सुरक्षा के क्षेत्रों में भी दोनों देशों के बीच प्रतिस्पर्धा लगातार तेज हो रही है। अमेरिका की यह आशंका पूरी तरह निराधार भी नहीं है कि चीन तकनीकी और सैन्य रूप से उसकी बराबरी करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है।

गौरतलब है कि अमेरिका और चीन के संबंध ही वर्तमान युग में वैश्विक भू-राजनीति की

दिशा तय कर सकते हैं। शायद इसीलिए दुनिया के विभिन्न देशों की निगाहें इस बैठक पर टिकी हैं और इसके निष्कर्षों में ही उन्हें अपने लिए रणनीतिक जमीन ढूंढनी होगी। जहां तक नई दिल्ली की बात है, तो पिछले कुछ दशकों में अमेरिका ने उसे चीन के खिलाफ एक संतुलनकारी ताकत के रूप में देखा है, जिसका रणनीतिक फायदा भारत को मिला है। लेकिन अब अगर वाशिंगटन और बीजिंग के बीच रिश्तों में गर्माहट बढ़ती है, तो यह समीकरण बदल सकता है।

यही नहीं, अगर चीन पर अमेरिकी दबाव कम होता है, तो वह दक्षिण एशिया में अपनी पैठ को और गहरा करने की कोशिश कर सकता है। हालांकि ये सब अटकलें ही हैं। दरअसल, ट्रंप और शी जिनपिंग की बैठक अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था और इसकी पारंपरिक अवधारणाओं में आ रहे बदलावों को रेखांकित करती है। भारत के लिए जरूरी है कि वह इस बैठक के नतीजों का विश्लेषण करे, खुद को बदलती वैश्विक व्यवस्था के अनुरूप ढाले और अपने हितों को प्राथमिकता देते हुए किसी एक राष्ट्र पर अत्यधिक निर्भरता के बगैर नीतियां बनाए।

घर लौट आयी है पश्चिम बंगाल की मूल आत्मा

प्रभु चावला

नौ मई की तपती दोपहर को कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में इतिहास ने केवल एक पन्ना नहीं पलटा। वह एक गेरुआ उभार के रूप में फूट पड़ा, जिसने सात दशकों से अधिक की वैचारिक जड़ता को झुलसा दिया। पश्चिम बंगाल के इतिहास में पहली बार गेरुआ वस्त्रधारी एक नेता ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। पचपन वर्षीय शुभेंदु अधिकारी ने तृणमूल कांग्रेस से उभरकर अपनी पहचान बनायी। उनका परिधान केवल वस्त्र नहीं था, बल्कि एक ऐसे राज्य में, जो लंबे समय तक कांग्रेस की निष्क्रियता, मार्क्सवादी कुप्रबंधन और ममता बनर्जी की राजनीति से बंधा रहा, सांस्कृतिक पुनरुत्थान की चुनौतीपूर्ण घोषणा के रूप में था।

राज्यपाल आरएन रवि भी, जिन्होंने तमिलनाडु में अपने कार्यकाल के दौरान शायद ही कभी पारंपरिक वस्त्र पहने थे, गेरुआ कुर्ता और पारंपरिक बंगाली धोती में सुसज्जित दिखाई पड़े। उन्होंने अपनी पत्नी के साथ, जो समान रंग की साड़ी पहने थीं, उस दिन रवींद्रनाथ ठाकुर की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस क्षण को संभव बनाने वाला जनादेश एक ऐतिहासिक विभाजन था। भाजपा की 207 सीटों और 45 प्रतिशत मतों के साथ मिली विजय फुसफुसाहट नहीं, बल्कि प्रबल जनाक्रोश की गर्जना थी। मतदाता छोटे-मोटे बदलाव नहीं, बल्कि पूर्ण परिवर्तन चाहते थे। मोदी, अमित शाह और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं के लिए यह केवल चुनावी गणित नहीं था। यह एक सांस्कृतिक विजय थी, जिसने 175 वर्षों की ब्रिटिश औपनिवेशिक स्मृति को एक झटके में समाप्त कर दिया।

कोलकाता औपनिवेशिक शासन का पालना था। यहीं से 1774 में बंगाल के पहले गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स ने उस साम्राज्य का संचालन किया था, जिसकी पकड़ पूरे उपमहाद्वीप तक फैली थी। वह शहर जिसने ब्रिटिश राज की प्रशासनिक रीढ़ को जन्म दिया, अब उसके प्रतीकात्मक पतन का साक्षी बना। भाजपा की रणनीति अत्यंत सूक्ष्म, सुविचारित और दूरदर्शी थी। पश्चिम बंगाल को जानबूझकर अंतिम राज्य के रूप में मतदान समाप्त करने के लिए रखा गया। अंतिम चरण और चार मई की मतगणना के बीच पांच दिनों का अंतर रखा गया। यह तिथि विशेष महत्व रखती थी, क्योंकि यह

जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती थी, जिनकी अखंड भारत की परिकल्पना लंबे समय तक वामपंथी इतिहास लेखन की परतों में दबा दी गयी थी। शपथ ग्रहण समारोह नौ मई को निर्धारित किया गया, जिसे रवींद्रनाथ ठाकुर की विरासत को स्मरण करते हुए गेरुआ प्रतीकवाद से जोड़ा गया। ममता बनर्जी के नबान्न से सरकार चलाने के केंद्र को वापस ऐतिहासिक राइटर्स बिल्डिंग में ले जाने का निर्णय भी पुनर्स्थापन का संकेत था।

इस दृश्य के पीछे भाजपा की 15 वर्षों की धैर्यपूर्ण मेहनत थी। पश्चिम बंगाल की भूमि ऐतिहासिक महत्व रखती है, जहां राजा राम मोहन राय ने नवजागरण का दीप प्रज्वलित किया था, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने 'वंदे मातरम' की रचना की। सुभाष चंद्र बोस ने वहीं ब्रिटिश राज को चुनौती देने वाला आक्रामक स्वतंत्रता आंदोलन खड़ा किया। श्री अरविंद ने हिंदू अध्यात्म को क्रांतिकारी विचारधारा का रूप दिया, तो स्वामी विवेकानंद ने विश्व मंच पर हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व किया और घोषणा की कि भारत की आत्मा शाश्वत है। इन महान विभूतियों ने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के ऐसे बीज बोये कि न तो कांग्रेस की धर्मनिरपेक्ष राजनीति और न ही मार्क्सवाद की भौतिकवादी विचारधारा उन्हें उखाड़ सकी। फिर भी सात दशकों तक इन प्रतीकों को उपेक्षित रखा गया।

कांग्रेस, वाम मोर्चा और बाद में तृणमूल कांग्रेस ने बंगाल को एक बिखरे और आत्महीन राज्य में बदल दिया। वोट बैंक की राजनीति ने समाज को धार्मिक और क्षेत्रीय आधार पर विभाजित किया। बांग्लादेश से घुसपैठ ने सीमावर्ती जिलों को अस्थिर बना दिया। हिंसा ने निवेशकों को दूर भगा दिया। जो बंगाल कभी औद्योगिक शक्ति था, वह पूंजी पलायन, उद्योगहीनता और उगाही का पर्याय बन गया। वर्ष 1960-61 में प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत की 127.5 प्रतिशत थी, जो गिरकर 83.17 फीसदी रह गयी। राष्ट्रीय जीडीपी में राज्य की हिस्सेदारी 10.5 फीसदी से घटकर 5.8 प्रतिशत रह गयी। भाजपा ने इस अवसर को पहचाना। पंद्रह वर्षों तक उसने चुपचाप काम किया। अपमानित समूहों की पहचान की, हिंदुओं को उनके खतरे में पड़े धार्मिक प्रतीकों की याद दिलायी और चेताया कि जनसांख्यिकीय बदलाव उन्हें अपनी ही भूमि में अजनबी बना सकते हैं।

संदेशखाली की घटनाओं, चुनाव के बाद की हिंसा और रोजमर्रा के अपमान से उपजा क्रोध अंततः विस्फोटित हुआ। हिंदुओं ने जाति और वर्ग से ऊपर उठकर अभूतपूर्व एकजुटता के साथ मतदान किया। लेकिन विजय के साथ सबसे कठिन परीक्षा भी आती है। शुभेंदु अधिकारी की सरकार को भाषणों से आगे बढ़कर परिणाम देने होंगे। बंगाल के लोग अब विकास चाहते हैं, जो समाज को जोड़े, तोड़े नहीं। उन्होंने हिंदू एकजुटता के लिए मतदान किया, अब वे व्यवहार में रामराज्य चाहते हैं। ऐसा शासन जो वंचितों की गरिमा लौटाये, निवेश को गुंडागर्दी के भय से मुक्त करे, सीमाओं को सुरक्षित बनाये और बंगाल की बौद्धिक व आर्थिक शक्ति पुनर्जीवित करे।

राइटर्स बिल्डिंग में वापसी इसी गहरे उद्देश्य का प्रतीक है। अब सचिवालय इतिहास से कटे आधुनिक भवन में नहीं बैठेगा। वह उन्हीं कक्षों में लौटेगा, जहां कभी औपनिवेशिक आदेश लिखे जाते थे और बाद में क्रांतिकारियों ने उनका विरोध किया था। इस स्थानांतरण के माध्यम से नयी सरकार ने यह घोषणा की कि बंगाल की पहचान न तो औपनिवेशिक अवशेष है और न ही वामपंथी प्रयोगशाला, बल्कि बंगाल भारत की निरंतर जीवंत धारा का हिस्सा है। आलोचक इस पर आपत्ति करेंगे। कुछ अन्य लोग धर्मनिरपेक्ष गढ़ों के अंत पर शोक जतायेंगे। जनादेश स्पष्ट है। मतदाताओं ने अतीत के टूटे वादों को अस्वीकार कर दिया। भूमि सुधारों ने कृषि को ठहराव दिया, औद्योगिक नीतियों ने विकास के स्थान पर हड़तालों को बढ़ावा दिया और अल्पसंख्यक राजनीति ने बहुसंख्यकों की बढ़ती चिंताओं की उपेक्षा की। फिलहाल एक सत्य निर्विवाद है। बंगाल की मूल आत्मा घर लौट आयी है।

मुश्किलों के बीच मितव्ययिता की अपील

प्रो गौरव वल्लभ

आज दुनिया जिस दौर से गुजर रही है, वह केवल भू-राजनीतिक तनाव का दौर नहीं, बल्कि आर्थिक अस्थिरता का भी दौर है। पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव कच्चे तेल की आपूर्ति और समुद्री व्यापार मार्गों को प्रभावित कर रहा है। रूस-यूक्रेन युद्ध के प्रभाव अब भी यूरोप की अर्थव्यवस्था पर दिखाई दे रहे हैं, जबकि अमेरिका-चीन तनाव वैश्विक सप्लाई चेन और कमोडिटी बाजारों को नये सिरे से आकार दे रहा है। कच्चे तेल की कीमतें अस्थिर हैं, उभरती अर्थव्यवस्थाओं की मुद्राओं पर दबाव बना हुआ है और वैश्विक राजनीति अब सीधे-सीधे आर्थिक परिणामों को प्रभावित कर रही है।

भारत के लिए यह स्थिति विशेष रूप से महत्व रखती है, क्योंकि देश कच्चे तेल की अपनी आवश्यकता का लगभग 87 प्रतिशत विदेशों से आयात के माध्यम से पूरी करता है। इसलिए अंतरराष्ट्रीय बाजार में आने वाला हर झटका महंगाई, पेट्रोल-डीजल की कीमतों और घरेलू बजट पर सीधा-सीधा असर डालता है।

हालांकि, हाल के दौर में भारत ने ऊर्जा आयात के स्रोतों को 40 से अधिक देशों तक विस्तारित कर, पश्चिम एशिया में अपनी कूटनीतिक सक्रियता बढ़ाकर और नये व्यापारिक गलियारों के निर्माण के माध्यम से स्थिति को संभालने की कोशिश की है। लेकिन ऐसी संरचनात्मक रणनीतियों का असर समय के साथ ही दिखाई देता है।

वास्तविकता यह है कि कच्चे तेल का बाजार रातोंरात स्थिर नहीं होता और सप्लाई चेन की स्थिति भी कुछ महीनों में नहीं सुधरती। ऐसे कठिन समय में आर्थिक मजबूती केवल सरकारों और संस्थानों की जिम्मेदारी नहीं रहती, बल्कि करोड़ों नागरिकों के रोजमर्रा के छोटे-छोटे फैसले भी उतने ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इसी संदर्भ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अनावश्यक ईंधन खपत कम करने, गैर-जरूरी सोने की खरीद टालने, देश के भीतर पर्यटन को बढ़ावा देने और जहां संभव हो वहां वर्क फ्रॉम होम अपनाने की अपील को समझना चाहिए। पहली नजर में प्रधानमंत्री के ये

सुझाव प्रतीकात्मक नजर आ सकते हैं, लेकिन इनके पीछे मजबूत आर्थिक तर्क मौजूद हैं। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत में सोने का आयात लगभग 72 अरब डॉलर तक पहुंच गया, जो कच्चे तेल के बाद दूसरी सबसे बड़ी आयातित वस्तु है।

दूसरी ओर, देश के चालू खाते का घाटा बढ़ने की आशंका है, खासकर तब, जब कच्चे तेल की ऊंची कीमतें लंबे समय तक बनी रहें। चालू खाते का घाटा जब बढ़ता है, तब उसका असर केवल आर्थिक आंकड़ों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि इसका रुपये पर दबाव बढ़ता है, पेट्रोल महंगा होता है, विदेश में पढ़ाई का खर्च बढ़ता है और होम लोन की इएमआइ तक इससे प्रभावित हो सकती है। इस तरह वैश्विक अर्थव्यवस्था का दबाव अंततः आम परिवार की रसोई तक पहुंच जाता है। चुनौती भरे इस वैश्विक परिदृश्य में भारत को कठोर मितव्ययिता की आवश्यकता नहीं है। जरूरत केवल समझदारी भरे विकल्पों की है-यानी ऐसे छोटे-छोटे बदलावों पर अमल करना, जो विदेशी मुद्रा पर दबाव कम करें, लेकिन जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित न करें।

उदाहरण के तौर पर, भारतीय शादियों को देखा जा सकता है। मध्यमवर्गीय परिवारों के लिए शादी अक्सर सबसे बड़ा खर्च होता है और इसका बड़ा हिस्सा आयात आधारित होता है, जैसे-सोने के गहने, विदेशी डेस्टिनेशन वेडिंग, विदेश यात्राएं और आयातित सजावट। इसमें संयम का परिचय दिया जा सकता है। संयम का अर्थ उत्सव को त्यागना नहीं है। यदि कुछ हिस्सा सोने की खरीद के बजाय वित्तीय निवेश में लगाया जाये और बाली या दुबई की जगह उदयपुर, जयपुर या केरल जैसे भारतीय पर्यटन स्थलों को चुना जाये, तो आर्थिक लाभ देश के भीतर ही बना रहेगा। विवेकपूर्ण खर्च का उद्देश्य खुशियों को कम करना कतई नहीं है, बल्कि खर्च को अधिक विवेकपूर्ण बनाना है।

यही बात रोजमर्रा की खपत पर भी लागू होती है। ईंधन का अत्यधिक उपयोग, आयातित खाद्य तेल, विदेशी ब्रांडों की खरीद, विदेशी छुट्टियां और अनावश्यक आयात आधारित उपभोग धीरे-धीरे देश की बाहरी आर्थिक स्थिति पर दबाव बढ़ाते हैं। यदि शहरी मध्यमवर्ग का एक हिस्सा भी अपनी विदेशी मुद्रा आधारित वैकल्पिक खपत में 15-20 प्रतिशत की कमी लाये, तो इससे हर वर्ष अरबों डॉलर की विदेशी मुद्रा बचायी जा सकती है। यातायात के तौर-तरीकों पर भी पुनर्विचार करना आवश्यक है। ऊर्जा के महंगे होने के दौर में मेट्रो रेल, सार्वजनिक परिवहन, कार-पूलिंग और हाइब्रिड वर्क मॉडल आर्थिक रूप से व्यावहारिक विकल्प हैं। देश के बड़े कॉरपोरेट संस्थान यदि सप्ताह में दो-तीन दिन वर्क फ्रॉम होम व्यवस्था अपनायें, तो हर महीने सैकड़ों करोड़ रुपये के ईंधन की बचत संभव है। इससे ट्रैफिक और प्रदूषण भी कम होगा। इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर बढ़ना भी इस दिशा में एक स्थायी कदम है। हर इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर पेट्रोल पर निर्भरता को स्थायी रूप से कम करता है। वास्तविकता यह है कि भारत का इवी इकोसिस्टम अब पहले की तुलना में कहीं अधिक परिपक्व हो चुका है और इसकी परिचालन लागत भी तुलनात्मक रूप से कम है।

इस दौर में उद्योग जगत के लिए भी अवसर मौजूद हैं। ज्वेलरी उद्योग हल्के और कम सोने वाले डिजाइनों पर ध्यान दे सकता है। ऐसे ही, पर्यटन उद्योग विश्वस्तरीय भारतीय अनुभव तैयार कर सकता है, ताकि भारतीय पर्यटक विदेश जाने के बजाय देश के भीतर खर्च करें। हालांकि, इस मामले में सरकार को भी संरचनात्मक प्रोत्साहन देने होंगे-जैसे बड़ी शहरी परियोजनाओं में रूफटॉप सोलर को बढ़ावा देना और कम दूरी की सरकारी यात्राओं में रेल एवं इवी आधारित परिवहन को प्राथमिकता देना। देश केवल बड़े भाषणों से आर्थिक चुनौतियों से बाहर नहीं निकलते। वे करोड़ों लोगों द्वारा समय के साथ किये गये छोटे, लेकिन लगातार व्यावहारिक बदलावों से मजबूत बनते हैं।

इंडिया गठबंधन को कमजोर करेगी डीएमके की नाराजगी

रशीद किदवई

चार राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में हुए विधानसभा चुनावों में कांग्रेस को बेशक केरल में सत्ता मिल गयी, लेकिन इंडिया गठबंधन की कमजोरी के संकेत भी दिखने लगे हैं। खासकर तमिलनाडु में कांग्रेस द्वारा विजय को समर्थन देने से डीएमके नाराज है और उसने कांग्रेस के फैसले को पीठ में छुरा घोंपना कहा है। डीएमके ने लोकसभा अध्यक्ष से लोकसभा में अपनी सीटिंग अरेंजमेंट भी कांग्रेस से अलग करने के लिए कहा है। कांग्रेस और डीएमके के राजनीतिक संबंधों का इतिहास उतार-चढ़ाव भरा रहा है। वर्ष 1991 में राजीव गांधी की हत्या के बाद दोनों पार्टियों के रिश्ते बेहद तल्ख हो गये थे। कांग्रेस ने डीएमके पर एलटीटीइ के प्रति नरम रवैया बरतने के आरोप लगाये थे। याद कीजिए, 1998 में कांग्रेस ने राजीव गांधी के हत्यारों को डीएमके द्वारा कथित समर्थन देने का आरोप लगाकर आइके गुजराल सरकार से हाथ खींच लिये थे। पर कुछ वर्षों बाद दोनों दल फिर साथ आये। वर्ष 2004 और 2009 में कांग्रेसनीत यूपीए सरकार में डीएमके अहम सहयोगी बनी। किंतु 2013 में डीएमके ने श्रीलंका के मुद्दे पर यूपीए सरकार का साथ छोड़ दिया था। तो क्या राहुल गांधी ने 2013 का बदला चुकाया है? दरअसल, राजनीति में वर्षों पुराने अतीत की इतनी अहमियत नहीं होती, जितनी वर्तमान या भविष्य की। इसलिए विजय की टीवीके के साथ जाने का फैसला लेते समय राहुल के जेहन में 2013 तो कतई नहीं होगा, बल्कि इसे महीने भर पहले टीवीके के साथ चुनाव पूर्व गठबंधन न करने की भूल को सुधारने की कोशिश माना जा सकता है। उल्लेखनीय है कि हालिया विधानसभा चुनावों से पहले राहुल गांधी ने मल्लिकार्जुन खरगे और पार्टी के अन्य पुराने नेताओं की सलाह पर डीएमके के साथ बने रहने का फैसला किया था, जबकि तमिलनाडु कांग्रेस का एक धड़ा, खासकर युवा नेता इससे सहमत नहीं थे। अपनी इस गलती का अहसास राहुल को मतदान वाले दिन ही हो गया था। तमिलनाडु में त्रिशंकु सदन की स्थिति आते ही राहुल ने कांग्रेस के वर्षों पुराने साझेदार डीएमके से नाता तोड़कर एक्टर 'थलापति' विजय की नयी-नवेली पार्टी व सरकार को समर्थन देने में एक पल की भी देरी नहीं लगायी। राहुल के इस फैसले ने नये सियासी समीकरणों को लेकर नयी बहस छेड़ दी है। कुछ हलकों में उनके इस फैसले को भले ही घोर अवसरवादी बताया जा रहा हो, लेकिन स्वयं उनकी अपनी पार्टी ही नहीं, विपक्षी दलों के बीच भी इस घटनाक्रम को उत्सुकता से देखा जा रहा है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के तौर पर रविवार को विजय के शपथ ग्रहण समारोह में उनकी राहुल गांधी के साथ जिस तरह की केमिस्ट्री देखने को मिली, वह दिलचस्प थी। आम तौर पर शपथ ग्रहण समारोह में आने वाले अति विशिष्ट लोग सामने की तरफ आगे वाली कुर्सियों पर बैठते हैं। मंच पर केवल मुख्यमंत्री या शपथ लेने वाले मंत्री ही बैठते हैं। लेकिन विजय ने राहुल से मंच पर बैठने का विशेष आग्रह किया, जिसे उन्होंने स्वीकार किया। प्रोटोकॉल के हिसाब से यह एक असामान्य बात थी। इस दौरान पूरे तमिलनाडु और देश ने देखा कि कैसे विजय ने राहुल गांधी को सम्मान दिया। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद विजय ने शुरुआती भाषण में ही स्पष्ट कर दिया कि उनका पूरा जोर सामाजिक न्याय पर रहेगा। राहुल गांधी को भी सामाजिक न्याय पर बातें करना अच्छा लगता है। वर्ष 2024 के लोकसभा चुनावों के दौरान यही मसला उनके प्रचार अभियान के केंद्र में था। लेकिन कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति और उत्तर भारत में उन्हें इसमें उतनी कामयाबी नहीं मिल पायी, जितनी उन्हें उम्मीद थी। मगर अब ऐसा लगता है कि उन्हें विजय के रूप में समान विचारधारा वाला एक साथी मिल गया है। गौरतलब है कि देश में केवल तीन ऐसे प्रदेश हैं, जहां राहुल गांधी की लोकप्रियता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ज्यादा है। इनमें तमिलनाडु भी एक है (अन्य दो राज्य केरलम और पंजाब हैं)। ऐसे में कांग्रेस के एक धड़े को लग रहा है कि राहुल और विजय के रूप में यह युवा जोड़ी अगले लोकसभा चुनावों में कमाल कर सकती है। इस नये गठबंधन के साथ 2029 के लोकसभा चुनावों में कांग्रेस तमिलनाडु में कुछ ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने की उम्मीद भी लगा सकती है। यह थोड़ा दिलचस्प लग सकता है कि चार मई के बाद से ही कांग्रेस मुख्यालय इंदिरा गांधी भवन में उत्साह की लहर दिखाई दे रही है। कांग्रेस का एक खेमा, खासकर राहुल गांधी के करीबी लोगों का मानना है कि पार्टी के पास पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, दिल्ली, उत्तराखंड, पंजाब और कई अन्य राज्यों में अपने 'पुराने अच्छे दिन' वापस लाने का मौका है। इसलिए 'एकला चलो रे' अब नया नारा बन गया है।

तारा के जीवन में फिर प्यार का सितारा चमका

तारा और वीर का रिश्ता पिछले दिनों काफी चर्चा में रहा। सूत्रों के अनुसार जनवरी की शुरुआत में दोनों का ब्रेकअप हो गया। इसकी सबसे बड़ी वजह सिंगर ए. पी. ढिल्लों के मुंबई कॉन्सर्ट को माना गया, जहां सिंगर ने स्टेज पर तारा को किस किया था।

'तारा सुतारिया एक बार फिर अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में है। कुछ समय पहले उसका नाम वीर पहाड़िया के साथ जोड़ा जा रहा था, लेकिन खबरें आईं कि दोनों का ब्रेकअप हो गया ।

अब सूत्रों के अनुसार तारा की जिंदगी में एक बार फिर प्यार ने दस्तक दी है। रिपोर्ट्स के अनुसार, तारा इन दिनों आदित्य रॉय कपूर को डेट कर रही है। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच नजदीकियां किसी प्रोजेक्ट के दौरान बढ़ीं और धीरे-धीरे यह रिश्ता खास बनता चला गया। दोनों के करीबी सूत्रों का कहना है कि दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ रही हैं और वे एक-दूसरे की कंपनी काफी पसंद कर रहे हैं।

हालांकि, दोनों सितारों ने अभी तक अपने रिश्ते को लेकर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है, लेकिन साथ में दिखने और इंडस्ट्री में चल रही चर्चाओं ने इन अफवाहों को और तेज कर दिया है ।

वीर से ब्रेकअप का खुलासा !

तारा और वीर पहाड़िया का रिश्ता पिछले दिनों काफी चर्चा में रहा। सूत्रों के अनुसार जनवरी की शुरुआत दोनों का ब्रेकअप हो गया। इसकी सबसे बड़ी वजह ए. पी. ढिल्लों के मुंबई कॉन्सर्ट को माना गया, जहां सिंगर ने स्टेज पर तारा को किस किया था। इसके बाद ही रिश्ते में तनाव की खबरें सामने आने लगी थीं ।

वहीं अब कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि दोनों का रिश्ता टूटने की वजह कुछ और भी थी। दरअसल, बताया जा रहा है कि कथित तौर पर तारा रिश्ते में काफी कंट्रोलिंग थी और वह वीर की लाइफस्टाइल, दोस्तों व निजी चीजों में बदलाव चाहती थी।

एक रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि वीर के कई अच्छे दोस्त हैं- ऐसे दोस्त जो सच में उसकी परवाह करते हैं तो दूसरी तरफ, तारा को एक 'डॉमिनेटिंग' शख्स कहा जाता है। सूत्रों ने बताया कि ये दोनों अपने रिश्ते के छोटे से समय में साथ में अच्छे थे लेकिन यह बिना शर्तों वाला रिश्ता नहीं था ।

बताया जा रहा है कि तारा शुरुआत से वीर में और आस-पास सब कुछ बदलना चाहती थी । वह चाहती थी कि उसकी चीजें बदल दी जाएं। यहां तक कि वीर की 'कॉल-लिस्ट' से लोगों को एडिट करके निकाल दिया जाए । यह भी कहा जा रहा है कि तारा चाहती थी कि वीर अपना घर एक खास तरीके से सजाए। साथ ही खुद को वैसा ढाले जैसा उसने सोचा था ।

सूत्र के अनुसार वीर बदलाव के लिए तैयार भी था। भले ही उसके दोस्तों ने उसे ऐसा करने से बार-बार मना किया हो और उसे समझाया था कि जैसे हो तुम वैसे ही रहो। हालांकि, ए. पी. ढिल्लों के कॉन्सर्ट के बाद चीजें बहुत खराब हो गईं। वैसे अपने ब्रेकअप को दोनों में से किसी ने कंफर्म नहीं किया। अब भी दोनों के सोशल मीडिया पर एक-दूसरे के साथ तस्वीरें हैं। अब सच क्या है यह तो आने वाले वक्त में ही पता चल सकता है।

वैसे तारा वीर से पहले अभिनेता आदर जैन के साथ भी रिलेशनशिप में थी लेकिन दोनों का ब्रेकअप हो गया था। उसके बाद आदर ने अलेखा आडवाणी के साथ शादी कर ली थी ।

तारा का करियर

तारा सुतारिया ने 'बिग बड़ा बूम' तथा 'द सूइट लाइफ ऑफ करण एंड कबीर' जैसे टी. वी. शोज से 15 साल की उम्र में ही अभिनय करियर शुरू कर दिया था। जवान होने पर उसने फिल्म 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2' के साथ बड़े पर्दे पर डेब्यू किया। इसके बाद से अब तक वह 'मरजावां', 'एक विलेन रिटर्न्स', 'हीरोपंती 2', 'अपूर्वा', 'तड़प' जैसी कई फिल्में कर चुकी है। अब जल्द ही वह पैन इंडिया फिल्म 'टॉक्सिक' में नजर आएगी।

शाहरुख खान की 'किंग' से लीक हुआ अभिषेक बच्चन का धांसू लुक, फिल्म में निभाएंगे दमदार भूमिका

बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान की मच अवेटेड फिल्म 'किंग' अपनी घोषणा के बाद से ही लगातार चर्चाओं में बनी हुई हैं। फिल्म से शाहरुख खान का लुक पिछले साल मेकर्स ने जारी किया था। इसके बाद बीते दिनों शूटिंग के दौरान के फोटो-वीडियो सामने आए थे, जहां शाहरुख के साथ दीपिका नजर आई थीं। अब फिल्म से अभिषेक बच्चन का लुक ऑनलाइन लीक हो गया है। अब ये लुक सोशल मीडिया पर वायरल है।

'किंग' में ऐसा होगा अभिषेक बच्चन का लुक

फिल्म को लेकर सामने आई रहीं चर्चाओं के मुताबिक, अभिषेक 'किंग' में विलेन के रूप में नजर आएंगे। ऑनलाइन लीक हुए लुक में भी उनका खतरनाक अंदाज देखने को मिल रहा है। वायरल हो रही फोटो में अभिषेक बच्चन एक गाड़ी के ऊपर खड़े नजर आ रहे हैं। उनके हाथों में शॉटगन है। छोटे बाल वाले लुक में अभिषेक काला चश्मा लगाए नजर आ रहे हैं। वायरल फोटो में अभिषेक ब्लैक आउटफिट पर ग्रे कलर का ओवरकोट पहने हुए हैं। फोटो में उनके बैकग्राउंड में पहाड़ी चोटी नजर आ रही है।

फिल्म से शाहरुख और दीपिका के फोटो-वीडियो भी हो चुके हैं लीक

इससे पहले 'किंग' से शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की भी साउथ अफ्रीका में शूटिंग सेट से तस्वीरें वायरल हुई थीं। ये तस्वीरें किसी गाने की शूटिंग की मालूम पड़ती हैं। इसके बाद निर्देशक सिद्धार्थ आनंद ने लोगों से अपील की थी कि तस्वीरों को शेयर न करें।

वहीं वायरल हुए शूटिंग के एक वीडियो में शाहरुख और दीपिका दक्षिण अफ्रीका में सनसेट के समय बीच पर शूटिंग करते नजर आए थे। क्लिप में दीपिका सफेद ड्रेस में थीं, जबकि शाहरुख धारीदार शर्ट और काले ट्राउजर में नजर आए थे।

उसी शेड्यूल के कुछ और सीन में उन्हें एक गाने की शूटिंग के दौरान हाथ में हाथ डाले चलते हुए देखा गया।

उन तस्वीरों में दीपिका फ्लोरल प्रिंट गाउन में थीं, जबकि शाहरुख बिना बटन वाली प्रिंटेड शर्ट में सफेद-काले बालों के साथ दिखाई दिए। एक अन्य बिहाइंड-द-सीन क्लिप में शाहरुख सीढ़ियों पर रुकते हुए, पीछे मुड़कर दीपिका को हाथ बढ़ाते हुए दिखाई दिए।

24 दिसंबर को रिलीज होगी 'किंग'

सिद्धार्थ आनंद द्वारा निर्देशित 'किंग' में शाहरुख खान प्रमुख भूमिका में नजर आएंगे। इसके अलावा फिल्म में एक बड़ी स्टारकास्ट नजर आएगी, जिसमें शाहरुख की बेटी सुहाना खान, दीपिका पादुकोण, अभिषेक बच्चन, रानी मुखर्जी, अनिल कपूर, अरशद वारसी, जयदीप अहलावत, जैकी श्रॉफ, राघव जुयाल और अभय वर्मा भी अहम भूमिकाओं में दिखाई देंगे। यह एक्शन फिल्म इसी साल 24 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

मैंने कभी खुद को खास नहीं समझा: चित्रांगदा सिंह

जोधपुर में जन्मी और बरेली व मेरठ में पली-बढ़ी चित्रांगदा सिंह इन दिनों चुनिंदा फिल्में करना ही पसंद कर रही है। फिल्म 'हजारों ख्वाहिशें ऐसी', 'ये साली जिंदगी', 'देसी ब्वॉयज' जैसी फिल्मों से पहचान बनाने वाली चित्रांगदा ने बतौर प्रोड्यूसर फिल्म 'सूरमा ' बनाई जो हॉकी खिलाड़ी संदीप सिंह की बायोपिक थी। वह लेखिका भी बन चुकी है। चित्रांगदा एक शॉर्ट फिल्म की पटकथा लिखी है। उसने वैब सीरीज 'खाकी : द बंगाल चैप्टर' से ओ.टी. टी. पर डेब्यू किया और गत वर्ष वह कॉमेडी फिल्म 'हाऊसफुल 5' में नजर आई थी।

हाल ही में अपने शुरुआती दिनों को याद करते हुए उसने बताया कि स्कूल और कॉलेज में उसने कभी खुद को ' स्पैशल ' महसूस नहीं किया, लेकिन मॉडलिंग में आने के बाद लोगों की तारीफों ने उसका नजरिया बदल दिया। वहीं उसने राजनीति में आने के सवाल पर कहा कि यह बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन भविष्य में कुछ भी संभव हो सकता है।

'बड़े सितारों के लिए चीजें अलग'

दीपिका पादुकोण के 8 घंटे वर्क शिफ्ट वाले मुद्दे ने फिल्म इंडस्ट्री में काफी चर्चा बटोरी थी । रिपोर्ट्स के अनुसार दीपिका ने अपने काम के लिए तय 8 घंटे की शिफ्ट की मांग रखी थी, ता कि लंबे और अनिश्चित शूटिंग घंटों से बचा जा सके।

फि ल्म इंडस्ट्री में अक्सर 10-12 घंटे या उससे भी ज्यादा काम होता है, ऐसे में यह मांग एक बड़े बदलाव की तरह देखी गई। वहीं, चित्रांगदा ने अब इस मुद्दे पर अपनी राय रखी है। उसने अपनी प्रोफैशनल और पर्सनल लाइफ को लेकर भी ढेरों खुलासे किए।

उसने कहा कि फिल्ममेकिंग एक क्रिएटिव प्रोसैस है, जहां कई बार लाइट, लोकेशन या टैक्निकल वजहों से शॉट समय पर नहीं हो पाता। ऐसे में सख्ती से 8 घंटे की सीमा लागू करना हर प्रोजैक्ट में संभव नहीं होता ।

हालांकि, उसने यह भी माना कि बड़े सितारों के लिए चीजें अलग होती हैं। अगर किसी फिल्म की शूटिंग किसी बड़े एक्टर पर निर्भर है, तो प्रोड्यूसर्स उनके हिसाब से शैड्यूल एडजस्ट कर लेते हैं लेकिन हर कलाकार के लिए यह सुविधा मिलना आसान नहीं है।

सबका ध्यान रखता है सलमान

चित्रांगदा जल्द ही सलमान खान के साथ फिल्म ' मातृभूमि' में नजर आने वाली है। सलमान के साथ काम को लेकर उसने कहा कि इंडस्ट्री में उसके बारे में कई तरह की बातें सुनने को मिलती हैं, लेकिन उसका अनुभव बिल्कुल अलग रहा। चित्रांगदा के अनुसार, सलमान बेहद सहज, प्रोफैशनल और सैट पर सभी का ख्याल रखने वाला इंसान है ।

चित्रांगदा ने सलमान खान को लेकर कुछ बड़े खुलासे करते हुए उसके साथ काम करने को लेकर कहा, "फिल्म बहुत मेहनत से बनाई है, दिल से बनाई है। सलमान के बारे में बहुत बातें करते हैं कि वह ऐसे हैं, वैसे हैं। मुझे भी इस बारे में काफी अफवाहें मिली थीं। जैसे मुझे उन सब चीजों के लिए तैयार रहना होगा अगर सलमान समय पर न आएं या शूटिंग का शैड्यूल बढ़ जाए ।'

उसने आगे कहा, लेकिन असल में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैंने पहले से ही खुद को तैयार कर लिया था क्योंकि इतने लोगों से यह अफवाह सुनी थी कि वह अनप्रोफैशनल हैं... लेकिन इसमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है । वह तो बहुत ही सहज और मिलनसार इंसान उनकी एक खास बात है कि वह सैट पर सबसे कम नजर आने वाले इंसान का भी ख्याल रखते हैं, चाहे वह लाइटमैन हो या चौथा एडी । वह पूछते हैं कि उन्होंने ब्रेक लिया या नहीं, समय पर खाना खाया या नहीं, उनके साथ कैसा व्यवहार हो रहा है । इतने साल इंडस्ट्री में काम करने के बाद भी उनमें यह चिंता होना वाकई कमाल की बात है ।

गौरतलब है कि सलमान खान की अगली फिल्म 'मातृभूमि' की रिलीज फिलहाल टल गई है । इसी वजह से फिल्म कई दिनों से चर्चाओं में बनी हुई है लेकिन फिल्म के विषय को देखते हुए इसे स्वतंत्रता दिवस पर रिलीज करने की खबरें सामने आ रही हैं।

वही करो जो मन को भाए : रिद्धिमा कपूर

बॉलीवुड के कपूर परिवार में वैसे एक से सुनने के बाद मुझे महसूस हुआ कि मुझे इसे एक दिग्गज कलाकार रह चुके हैं। इनमें पृथ्वीराज कपूर से लेकर करीना कपूर और रणबीर कपूर के नाम शामिल हैं और कपूर परिवार ने बॉलीवुड को एक से एक बड़ी फिल्में दी हैं ।कपूर परिवार अपने संस्कारों और फिल्मों में किए गए शानदार अभिनय को लेकर जाना जाता है।

अब फिल्म 'दादी की शादी' से नीतू कपूर की बेटी रिद्धिमा कपूर ने भी बॉलीवुड में डेब्यू कर लिया है। इस फिल्म में उसकी मां नीतू ने ही लीड रोल किया है।

अपनी पहली फिल्म को लेकर रिद्धिमा ने कहा, "मैं दर्शकों को धन्यवाद देना चाहती हूं । फिल्म की कहानी बहुत ही सुंदर है। यह दिल से बनाई है। मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है।

फिल्म 'दादी की शादी' की कहानी

करना ही चाहिए। जब मुझसे पूछा गया कि आप फिल्म में मम्मी की बेटी बनना चाहोगी तो पहले मैं थोड़ा-सा हिचकिचाई, फिर मुझे मम्मी ने कॉल किया कि पहले अपने पति और ससुराल में पूछ लो । फिर मुझे लगा कि इस फिल्म कर लेना चाहिए।

'मुझ पर भी फिल्मों में आने का कभी दबाव नहीं था। मुझे हमेशा से बोला गया है कि आपके मन आ वही करो। मैं 16- 17 साल की उम्र में पढ़ने के लिए लंदन चली गई थी। वापस आने के बाद मेरी शादी हो गई, फिर मेरी बच्ची हो गई और मैं घर- परिवार में व्यस्त हो गई। मुझे कभी ध्यान में ही नहीं आया कि मैं फिल्में भी कर सकती हूं। 'अब जब मौका मिला तो फिल्म कर ली । मुझे लगता है कि आप जो भी करना चाहती हो, किसी भी उम्र में करना चाहती हो तो करना चाहिए। मुझे किसी सीन में दिक्कत होती थी तो मम्मी मदद करती थीं।

राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय
प्रमुख समाचार

पीएम मोदी की अपील का असर बिहार सीएम पैदल पहुंचे दफ्तर

पटना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पेट्रोल-डीजल की खपत कम करने और पर्यावरण संरक्षण की अपील का असर अब बिहार की राजनीति पर दिखने लगा है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी शुक्रवार को वाहन निषेध दिवस मना रहे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री आवास से सचिवालय तक 50 मीटर की दूरी पैदल चलकर तय की। बिहार सरकार में मंत्री उपेंद्र कुशवाहा के पुत्र दीपक प्रकाश भी अपने आधिकारिक आवास से सचिवालय तक पैदल चलकर गए। उन्होंने लगभग 1 किलोमीटर की दूरी तय की। मुख्यमंत्री की पहल के बाद, शुक्रवार को सचिवालय के अधिकारियों और कर्मचारियों ने भी वाहनों का इस्तेमाल नहीं किया। सचिवालय के कर्मचारी साइकिल और सार्वजनिक परिवहन से कार्यालय आए। सामान्य दिनों की तुलना में सचिवालय परिसर के आसपास सरकारी वाहनों की संख्या कम दिखाई दी, जबकि कई अधिकारी अपने निजी वाहनों से या पैदल चलकर कार्यालय पहुंचते हुए देखे गए।

बंगाल विधानसभा के नए अध्यक्ष बने भाजपा के रथिंद्र

कोलकाता। शुक्रवार को कूचबिहार दक्षिण निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक रथिंद्र बोस को पश्चिम बंगाल विधानसभा का नया अध्यक्ष चुना गया। चुनाव जीतने के बाद, मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने विधानसभा परंपरा के अनुसार बोस को अध्यक्ष की कुर्सी तक पहुंचाया। मुख्यमंत्री अधिकारी ने गुरुवार को अध्यक्ष पद के लिए बोस के नामांकन की घोषणा करते हुए कहा कि कूच बिहार दक्षिण निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के विधायक रथेंद्र बोस को 18वीं पश्चिम बंगाल विधानसभा के अध्यक्ष पद के लिए हमारे उम्मीदवार के रूप में नामित किया गया है। मुझे आशा है कि उनकी उम्मीदवारी का सभी का समर्थन होगा और वे सर्वसम्मति से निर्वाचित होंगे। अधिकारी ने बोस की पेशेवर पृष्ठभूमि और समर्पण पर प्रकाश डालते हुए कहा कि वे एक समर्पित पार्टी कार्यकर्ता और पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। वे इस भूमिका में प्रशासनिक समझ और संगठनात्मक अनुभव दोनों लेकर आएंगे।

ब्राह्मण अपमान पर मायावती का सपा पर बड़ा हमला

लखनऊ। बहुजन समाज पार्टी (बीएसपी) की प्रमुख और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने शुक्रवार को समाजवादी पार्टी (एसपी) के प्रवक्ता राजकुमार भाटी द्वारा ब्राह्मण समुदाय के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणियों की आलोचना की। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे ने व्यापक आक्रोश पैदा किया है और एसपी नेतृत्व से इसे गंभीरता से लेने का आग्रह किया। ङ्क पर एक पोस्ट में मायावती ने इन टिप्पणियों को अशोभनीय, और आपत्तिजनक बताते हुए कहा कि इनसे ब्राह्मण समुदाय की गरिमा और आत्मसम्मान को ठेस पहुंची है। मायावती ने कहा कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता द्वारा ब्राह्मण समुदाय के बारे में हाल ही में की गई अशोभनीय और आपत्तिजनक टिप्पणियों और बयानों ने स्वाभाविक रूप से व्यापक आक्रोश और कड़ी निंदा को जन्म दिया है। इस विवाद के परिणामस्वरूप पुलिस मामला दर्ज होने के बावजूद, मामला शांत होने के कोई संकेत नहीं दिखा रहा है।

असम चुनाव के घोषणापत्र का हर वादा पूरा करेंगे : हिमंत

गुवाहाटी। असम विधानसभा चुनाव में भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए की जीत के बाद, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने सरकार द्वारा किए गए सभी वादों को पूरा करने का विश्वास व्यक्त किया। एनडीए को 102 सीटें मिलने के बाद, सरमा ने सरकार पर बढ़ी हुई जिम्मेदारी को स्वीकार किया। 15 मई को नागांव जिले के बटाद्रवा थान में श्रीमंत शंकरदेव के जन्मस्थान पर प्रार्थना करने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए शर्मा ने कहा कि सरकार आने वाले वर्षों में विकास को और तेज करेगी। उन्होंने कहा कि 102 सीटें जीतने के बाद जिम्मेदारी बढ़ेगी। इस बार हम पिछले पांच वर्षों की तुलना में अधिक मेहनत करेंगे ताकि असम का विकास हो सके। सरमा ने बताया कि 2026 के चुनाव घोषणापत्र में पिछले घोषणापत्र की तुलना में व्यापक वादे शामिल हैं। इस बार हमने अपने चुनाव घोषणापत्र में अधिक काम करने का वादा किया है और मुझे विश्वास है कि हम अपने चुनाव घोषणापत्र में किए गए वादों को पूरा करने में सक्षम होंगे।

व्यापार समझौता नहीं, अदाणी की रिहाई का सौदा किया : राहुल

नईदिल्ली। अमेरिका में उद्योगपति गौतम अदाणी के खिलाफ चल रहे कानूनी मामले और भारत-अमेरिका व्यापार समझौते को लेकर देश की राजनीति में नया तूफान खड़ा हो गया है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। राहुल गांधी का दावा है कि हालिया भारत-अमेरिका व्यापार समझौता वास्तव में देश का हित साधने के लिए नहीं, बल्कि गौतम अदाणी को अमेरिकी कानूनी कार्रवाई से बचाने के लिए किया गया है। खबरों में दावा किया गया है कि अमेरिकी अधिकारी भारतीय अरबपति अदाणी के खिलाफ धोखाधड़ी के आरोपों को सुलझाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अदाणी समूह ने अतीत में लगे सभी आरोपों को खारिज किया था। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने 'एक्स' पर पोस्ट किया, '''कंप्रोमाइज्ड, पीएम' ने व्यापार समझौता नहीं, अदाणी की रिहाई का सौदा किया।''

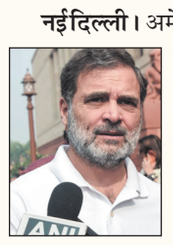

भारत-यूएई रक्षा साझेदारी से दुनियाभर में हड़कंप

अमीरात को निशाना बनाया जाना स्वीकार्य नहीं : मोदी

अबू धाबी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात की संक्षिप्त लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को नई दिशा देने पर जोर दिया। अबू धाबी में संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता में प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच रणनीतिक सहयोग का महत्व और अधिक बढ़ गया है। उन्होंने जनवरी में राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद की भारत यात्रा का उल्लेख करते हुए कहा कि दोनों देशों ने संबंधों को गुणात्मक रूप से नई ऊंचाई पर ले जाने का निर्णय लिया था और कम समय में ही उल्लेखनीय प्रगति हासिल की गई है।

प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम एशिया में जारी तनाव और संघर्ष पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि संवाद और कूटनीति ही किसी भी विवाद का सर्वोत्तम समाधान है। इस दौरान उन्होंने होर्मुज जलडमरूमध्य को मुक्त, खुला और सुरक्षित बनाए रखने की आवश्यकता पर बल दिया तथा अंतरराष्ट्रीय कानूनों के सम्मान की बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत हर परिस्थिति में संयुक्त अरब अमीरात के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और क्षेत्र में शांति तथा स्थिरता बहाल करने के लिए हर संभव सहयोग देगा।

वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने हाल के दिनों में संयुक्त अरब अमीरात पर हुए हमलों की कड़ी निंदा भी की। उन्होंने कहा कि किसी भी रूप में अमीरात को निशाना बनाया जाना स्वीकार्य नहीं है। प्रधानमंत्री ने संयुक्त अरब अमीरात के नेतृत्व द्वारा राष्ट्रीय एकता, सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता बनाए रखने के लिए उठाए गए कदमों की सराहना की। साथ ही उन्होंने वहां रह रहे भारतीय समुदाय को कठिन समय में सहयोग देने के लिए अमीरात सरकार और शाही परिवार का आभार जताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि संयुक्त अरब अमीरात में भारतीयों को परिवार के सदस्य की तरह सम्मान और सुरक्षा मिलती है।

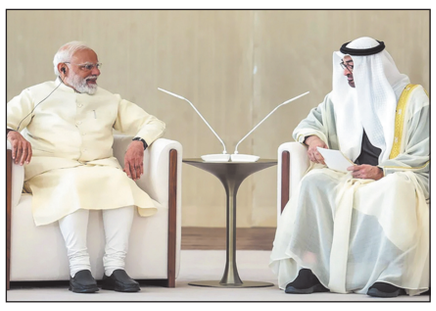

हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा के दौरान भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच रक्षा, ऊर्जा और निवेश से जुड़े कई महत्वपूर्ण समझौते भी हुए। दोनों देशों ने रणनीतिक रक्षा साझेदारी के ढांचे पर सहमति जताई। इसके अलावा रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार, द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस आपूर्ति तथा वाडीनार में जहाज मरम्मत केंद्र स्थापित करने से संबंधित समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इस यात्रा के दौरान भारतीय आधारभूत ढांचा परियोजनाओं, आरबीएल बैंक और सम्मान कैपिटल में लगभग पांच अरब अमेरिकी डॉलर के निवेश की घोषणाएं भी की गईं।

ऊर्जा सुरक्षा इस यात्रा का प्रमुख विषय रही। अधिकारियों के अनुसार संयुक्त अरब अमीरात भारत की ऊर्जा जरूरतों का एक महत्वपूर्ण भाग पूरा करता है। पिछले वर्ष भारत के कच्चे तेल आयात का लगभग ग्यारह प्रतिशत हिस्सा संयुक्त अरब अमीरात से आया था। इसके साथ ही यह भारत के लिए द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता है और भारत की लगभग चालीस प्रतिशत आवश्यकता पूरी करता है। दोनों देशों के बीच रणनीतिक पेट्रोलियम भंडारण को लेकर पहले भी सहयोग रहा है। वर्ष 2018 में भारतीय सामरिक पेट्रोलियम भंडार लिमिटेड और अबू धाबी राष्ट्रीय तेल कंपनी के बीच समझौते के तहत मैंगलोर स्थित भंडारण केंद्र में पांच मिलियन बैरल से अधिक कच्चे तेल का भंडारण किया गया था।

देखा जाये तो पश्चिम एशिया में जारी युद्ध और अस्थिरता के बीच प्रधानमंत्री मोदी की यह यात्रा विशेष महत्व रखती है। ईरान और अमेरिका-इजराइल के बीच बढ़ते तनाव तथा होर्मुज जलडमरूमध्य में संकट के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति प्रभावित हुई है। ऐसे समय में संयुक्त अरब अमीरात भारत के सबसे भरोसेमंद ऊर्जा साझेदार के रूप में उभरा है। बताया जा रहा है कि दोनों देश होर्मुज जलडमरूमध्य पर निर्भरता कम करने के विकल्पों पर भी विचार कर रहे हैं, जिनमें फुजैरा बंदरगाह के माध्यम से तेल आपूर्ति का मार्ग शामिल है।

हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी शुक्रवार सुबह दिल्ली से रवाना हुए और अबू धाबी पहुंचने पर उन्हें औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। संयुक्त अरब अमीरात के हवाई क्षेत्र में भारतीय प्रधानमंत्री के विमान को एफ-16 लड़ाकू विमानों ने एस्कॉर्ट किया। यह यात्रा प्रधानमंत्री के पांच देशों के दौरे का पहला चरण है। संयुक्त अरब अमीरात के बाद प्रधानमंत्री नीदरलैंड, स्वीडन, नार्वे और इटली की यात्रा करेंगे। नार्वे की यात्रा विशेष रूप से महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली नार्वे यात्रा होगी। ओस्लो में प्रधानमंत्री तीसरे भारत-नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे, जिसमें डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड और स्वीडन के नेता शामिल होंगे।

प्रधानमंत्री मोदी की गलती, जनता चुकाएगी कीमत

पेट्रोल-डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी पर भड़के राहुल

नईदिल्ली। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को पश्चिम एशिया संघर्ष के बीच ईंधन की कीमतों में हुई बढ़ोतरी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिम्मेदार ठहराया और जनता के कल्याण के लिए दृढ़ रुख अपनाया। एक्स पर एक पोस्ट में राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व वाली सरकार की गलतियों का खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है और दावा किया कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में हुई बढ़ोतरी, जिसे उन्होंने वसूली करार दिया, किश्तों में की जाएगी।

राहुल गांधी ने कहा कि मोदी सरकार की गलती, जनता को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। 3 रुपए का झटका पहले ही लग चुका है। बाकी की वसूली किश्तों में की जाएगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने आरोप लगाया कि ईंधन संकट के साथ-साथ भारत में आर्थिक संकट की बड़ी वजह मोदी सरकार में नेतृत्व का संकट तथा दूरदर्शी सोच का अभाव है। खरगे ने कहा, जनता को यह समझना होगा कि इस समय अंतरराष्ट्रीय ईंधन संकट के साथ-साथ भारत में आर्थिक संकट की बड़ी वजह मोदी सरकार में नेतृत्व का संकट तथा दूरदर्शी सोच का अभाव है और अक्षमता कूट-कूट कर भरी है।

उन्होंने दावा किया कि यह संकट मोदी सरकार द्वारा पैदा किया गया है, जिसका ख़ामियाज़ा देश की जनता को पेट्रोल, डीज़ल और एलपीजी पर अपनी जेब से भरना पड़ रहा है। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत कम थी तो मोदी सरकार ने उपभोक्ताओं को राहत देने के बजाय उन्हें लूटा। सरकारी तेल कंपनियों ने चार वर्षों के लंबे अंतराल के बाद शुक्रवार को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में संशोधन करते हुए दोनों ईंधनों के दाम में तीन रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की। रमेश ने 'एक्स' पर पोस्ट किया, वर्षों तक जब अंतरराष्ट्रीय तेल कीमतें कम थीं या गिर रही थीं, तब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लगातार यह मांग करती रही कि उसका लाभ भारतीय उपभोक्ताओं तक पहुंचाया जाए और गैस, पेट्रोल तथा डीजल की घरेलू कीमतों में कमी की जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और उपभोक्ताओं को लूटा गया।

दुनिया के मुकाबले भारत में सबसे कम बढ़े तेल के दाम : किरेन रिजिजू

नईदिल्ली। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने शुक्रवार को ईंधन की कीमतों में केंद्र सरकार के बढ़ोतरी के फैसले का बचाव करते हुए कहा कि पश्चिम एशिया संघर्ष के बाद कई देशों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 20% से लेकर लगभग 100% तक की बढ़ोतरी देखी गई, जबकि भारत में यह बढ़ोतरी मामूली रही। आर्थिक स्थिरता और जन कल्याण के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा करते हुए रिजिजू ने कहा कि सरकार ने नागरिकों को महंगाई के दबाव से बचाने के लिए जिम्मेदारी से काम किया।

रिजिजू ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि पश्चिम एशिया संघर्ष के बाद जब पूरी दुनिया ईंधन की बढ़ती कीमतों से जूझ रही थी, तब भारत ने एक अलग रुख अपनाया। जहां कई देशों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 20% से लेकर लगभग 100% तक की बढ़ोतरी देखी गई, वहीं भारत ने बढ़ोतरी को केवल +3.2% और डीजल में +3.4% तक सीमित रखा। उन्होंने आगे कहा कि भले ही ब्रेंट क्रूड की कीमत 100 डॉलर प्रति बैरल के पार पहुंच गई और वैश्विक बाजार अस्थिर हो गए, भारत की सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों ने नागरिकों को मुद्रास्फीति और आर्थिक दबाव से बचाने के लिए हफ्तों तक भारी नुकसान उठाया। यही जिम्मेदारी से भरा शासन है। यही वह नेतृत्व है जो जनता को सर्वोपरि रखता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, भारत आर्थिक स्थिरता और जन कल्याण के बीच संतुलन बनाए हुए है।

रिजिजू ने पश्चिम एशिया संघर्ष के बीच विभिन्न देशों में ईंधन की कीमतों में हुई वृद्धि की तुलना करते हुए आंकड़े भी साझा किए। आंकड़ों के अनुसार, मलेशिया में पेट्रोल की कीमतों में 89.7% और डीजल की कीमतों में 112.7% की वृद्धि दर्ज की गई, जबकि अमेरिका में पेट्रोल की कीमतों में 44% और डीजल की कीमतों में 48.1% की वृद्धि हुई। चीन में पेट्रोल की कीमतों में 21.7% और डीजल की कीमतों में 23.7% की वृद्धि हुई। केंद्र सरकार द्वारा शुक्रवार को देशभर में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी के बाद ये टिप्पणियां सामने आईं। नई दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 94.77 रुपये से बढ़कर 97.77 रुपये प्रति लीटर हो गई, जबकि डीजल की कीमत 87.67 रुपये से बढ़कर 90.67 रुपये प्रति लीटर हो गई। पश्चिमी एशिया में बढ़ते तनाव के कारण वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में आई भारी वृद्धि के बाद ईंधन की कीमतों में यह संशोधन किया गया है।

खेल
प्रमुख समाचार

केकेआर और गुजरात टाइटंस के बीच मुकाबला आज

कोलकाता। लगभग एक महीने के बाद अपने घरेलू मैदान पर वापसी करने वाली कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) की टीम अपनी उम्मीद जीवंत रखने के लिए शनिवार को यहां इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के मैच में शीर्ष दो में जगह बनाने की कवायद में लगी गुजरात टाइटंस का सामना करेगी। अनुभवी अजिंक्य रहाणे की कप्तानी में केकेआर ने पिछले साल की तरह इस वर्ष भी अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है जिससे उन्हें फिर से कप्तान नियुक्त करने के फैसले पर सवाल उठने लग गए हैं। केकेआर को मौजूदा सत्र में अपनी पहली जीत के लिए सातवें मैच (आधे चरण) तक इंतजार करना पड़ा था। वह इस दौरान एक संतुलित टीम संयोजन तैयार करने में नाकाम रहा।

केकेआर ने इसके बाद लगातार चार मैच जीते लेकिन पिछले मैच में विराट कोहली के शानदार शतक के कारण उसे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) से हार का सामना करना पड़ा था। केकेआर के अब तीन मैच बचे हैं और अगर वह सभी मैच जीत जाता है तो अधिकतम 15 अंक तक पहुंच पाएगा। इसके बावजूद उसकी प्लेऑफ में जगह पक्की नहीं हो पाएगी और इसके लिए उसे अगर मगर के समीकरणों से गुजरना होगा। एक और हार से उसकी आगे बढ़ने की संभावना खत्म हो जाएगी। केकेआर की लगातार चार मैचों में जीत का श्रेय काफी हद तक सुनील नारायण और वरुण चक्रवर्ती की स्पिन जोड़ी को जाता है जबकि उपकप्तान रिंकू सिंह ने भी निरंतर योगदान दिया है। चक्रवर्ती बाएं पैर में चोट लगने के कारण आरसीबी के खिलाफ नहीं खेल पाए थे जो टीम को महंगा पड़ा। केकेआर के मुख्य कोच अभिषेक नायर ने उनकी वापसी के संकेत दिए हैं जो टीम के लिए अच्छी खबर है। केकेआर की बल्लेबाजी में पूरे सत्र में निरंतरता का अभाव रहा है। उसके बल्लेबाजी क्रम को लेकर भी सवाल उठते रहे हैं।

आर्थिक/वाणिज्य/विज्ञान/
प्रमुख समाचार

सेंसेक्स 161 अंक टूटा निफ्टी 23,644 पर बंद

नईदिल्ली। घरेलू शेयर बाजार गुरुवार को गिरावट के साथ बंद हुआ। दिन के अंत में हुई बिकवाली और रुपये की कमजोरी का असर बाजार पर साफ दिखाई दिया। इसके साथ ही कच्चे तेल की कीमतों में तेजी ने भी निवेशकों की चिंता बढ़ा दी। कारोबार के अंत में निफ्टी-50 46.10 अंक यानी 0.19 प्रतिशत गिरकर 23,643.50 पर बंद हुआ। वहीं, बीएसई सेंसेक्स 160.73 अंक यानी 0.21 प्रतिशत की गिरावट के साथ 75,237.99 के स्तर पर बंद हुआ। बाजार पर दबाव का मुख्य कारण रुपये का अमेरिकी डॉलर के मुकाबले नए निचले स्तर पर पहुंचना रहा। इसके साथ ही अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेजी ने भी निवेशकों की धारणा को प्रभावित किया। ब्रेंट क्रूड का मई वायदा 2.9 प्रतिशत बढ़कर 108.8 डॉलर प्रति बैरल के करीब पहुंच गया, जिससे ऊर्जा लागत को लेकर चिंता और बढ़ गई।

पश्चिम एशिया संकट के बीच महंगा हुआ पेट्रोल-डीजल

नईदिल्ली। देश में लंबे समय से स्थिर चल रहे पेट्रोल और डीजल के दामों में आखिरकार बढ़ोतरी कर दी गई है। सरकारी तेल कंपनियों ने शुक्रवार को पेट्रोल की कीमतों में 3.14 रुपये और डीजल में 3.11 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की घोषणा की है। यह बढ़ी हुई कीमतें शुक्रवार सुबह से ही लागू हो गई हैं। यह फैसला ऐसे समय में आया है जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में लगातार उतार-चढ़ाव देखा जा रहा है। तेल कंपनियों के अनुसार अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। खासकर पश्चिम एशिया में चल रहे तनाव के बाद कच्चे तेल के दाम तेजी से ऊपर गए हैं। कंपनियों का कहना है कि वैश्विक स्तर पर बढ़े हुए दामों के मुकाबले घरेलू बाजार में पूरी बढ़ोतरी नहीं की गई है।

मुथूट फाइनेंस का चौथी तिमाही में मुनाफा दोगुने से भी अधिक

नई दिल्ली। मुथूट फाइनेंस का वित्त वर्ष 2025-26 की जनवरी-मार्च तिमाही में एकीकृत शुद्ध लाभ दोगुना से अधिक होकर 3,397 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। वित्त वर्ष 2024-25 की समान तिमाही में कंपनी ने 1,444 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ कमाया था। समीक्षाधीन तिमाही में कंपनी की कुल आय बढ़कर 9,291 करोड़ रुपए हो गई, जो 2024-25 की समान तिमाही में 5,627 करोड़ रुपए थी। चौथी तिमाही में कंपनी की ब्याज आय भी बढ़कर 9,008 करोड़ रुपए रही, जो वित्त वर्ष 2024-25 की समान तिमाही में 5,465 करोड़ रुपए थी। पूरे वित्त वर्ष 2025-26 में मुथूट फाइनेंस का शुद्ध लाभ 10,606 करोड़ रुपए रहा, जो वित्त वर्ष 2024-25 में 5,352 करोड़ रुपए था यानी इसमें 98 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। वित्त वर्ष 2024-25 में कंपनी की कुल आय भी बढ़कर 31,263 करोड़ रुपए रही, जो 2024-25 में 20,265 करोड़ रुपए थी।

48 घंटे में कई चीजें महंगी घर का बिगड़ा बजट

नईदिल्ली। देशभर में महंगाई ने आम लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। बीते 48 घंटों में सोना-चांदी, दूध, पेट्रोल-डीजल और सीएनजी जैसी जरूरी चीजों की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हुई है, जिससे जनता पर महंगाई का चौतरफा अटैक देखने को मिल रहा है। सबसे पहले सरकार द्वारा सोने-चांदी पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाए जाने के बाद इनके दामों में तेज उछाल आया। बाजार में सोना करीब 11,000 रुपए और चांदी 22,000 रुपए तक महंगी हो गई। इससे ज्वेलरी खरीदने वालों को बड़ा झटका लगा। इसके बाद दूध कंपनियों ने भी कीमतों में इजाफा कर दिया। अमूल और मदर डेयरी ने पैकेज्ड दूध के दाम 2 रुपए प्रति लीटर तक बढ़ा दिए हैं। महंगाई का असर सीएनजी पर भी पड़ा है। दिल्ली और मुंबई में सीएनजी की कीमतें 2 रुपए प्रति किलो तक बढ़ा दी गई हैं।

पश्चिम एशिया संघर्ष से भारत की अर्थव्यवस्था पर बढ़ता दबाव

अजय छिब्बर

होर्मुज स्ट्रेट से आवागमन लगातार बाधित होने के कारण अप्रैल के अपने स्तंभ में मैंने जिस मुद्रास्फीति जनित सुस्ती (स्टैगफ्लेशन) की आशंका जताई थी वह अब भारत और विश्व के लिए स्पष्ट वास्तविकता बनती जा रही है। विश्व बैंक के नवीनतम वस्तु पूर्वानुमान के मुताबिक युद्ध के चलते 2026 में तेल की कीमतें पहले की अपेक्षा 20 डॉलर प्रति बैरल अधिक रहने की संभावना है। इसका अर्थ यह है कि अंतरराष्ट्रीय मुद्र कोष यानी आईएमएफ का 2026 के लिए विश्व सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) वृद्धि का 3.4 फीसदी का अनुमान घटकर करीब 3 फीसदी रह जाएगा। वैश्विक मुद्रास्फीति भी बुनियादी पूर्वानुमान की तुलना में लगभग 1 फीसदी अंक बढ़ जाएगी।

भारत को और अधिक मुश्किल हालात का सामना करना होगा। आईआईएम के कारोबारी पूर्वानुमान सर्वेक्षण के अनुसार जीडीपी वृद्धि 7 फीसदी से अधिक के स्तर से घटकर 6 से 6.5 फीसदी रह जाएगी और मुद्रास्फीति बढ़कर 5 फीसदी से ऊपर निकल जाएगी। यह 4 फीसदी मुद्रास्फीति के तय लक्ष्य से अधिक होगा। 2025 के अंत में भारत को 'गोल्डीलॉक्स अर्थव्यवस्था' (अच्छी वृद्धि, कम मुद्रास्फीति और उच्च रोजगार वाली) कहा गया था, लेकिन अब इसे रिवर्स गोल्डीलॉक्स कहा जा रहा है। पेट्रोल पंप पर कीमतों में वृद्धि को रोकना बहुत लंबे समय तक संभव नहीं है, क्योंकि इससे तेल सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की वित्तीय स्थिति और राजकोषीय घाटे के लक्ष्यों को नुकसान पहुंचेगा। एलपीजी की कीमतें पहले ही बढ़ा दी गई हैं और डीजल तथा जेट ईंधन पर निर्यात शुल्क लगाया गया

है। रुपया डॉलर के मुकाबले 95 पार चला गया है और एशिया की सबसे कमजोर मुद्राओं में शामिल हो गया है। रिजर्व बैंक ने थोड़े समय के लिए हस्तक्षेप किया लेकिन जल्द ही समझ लिया कि यह हार जाने वाली लड़ाई है क्योंकि ईरान युद्ध से उत्पन्न संकट के चलते विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने भारतीय बाजारों से 21 अरब डॉलर से अधिक की राशि निकाल ली है।

हालांकि ईरान युद्ध से पहले ही रुपया कमजोर हो गया था और 2025 में यह एशिया की सबसे कमजोर मुद्रा था, क्योंकि विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने भारतीय बाजारों से 19 अरब डॉलर से अधिक की राशि निकाल ली थी। यह शुल्क संबंधी झटके के कारण हुआ। दरअसल, अमेरिका ने भारत पर 50 फीसदी शुल्क लगा दिए जिससे सभी चकित रह गए। लेकिन इसके साथ ही कम चर्चा में रहने वाला 'आर्टिफिशल इंटेलिजेंस का झटका' भी इसमें योगदान करने वाला रहा क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि भारत का सूचना प्रौद्योगिकी सोर्सिंग मॉडल पराजित होने वाला है। सरकार ने इस धारणा का मुकाबला एक बहुचर्चित एआई शिखर सम्मेलन के माध्यम से किया और 2030 तक एक मजबूत एआई पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए एक व्यापक एआई मिशन की घोषणा की है। इसमें स्वदेशी छोटे एआई मॉडल तैयार करना और स्टार्टअप्स तथा सार्वजनिक-निजी एआई परियोजनाओं को बढ़ावा देना शामिल है। परंतु यह सवाल बरकरार है कि एआई वरदान साबित होगा या अभिशाप क्योंकि भारत की बड़ी आईटी कंपनियों ने एआई अनुसंधान में निवेश करना उचित नहीं समझा है और उनका आउटसोर्सिंग मॉडल प्रभावित हो रहा है। वे कितनी जल्दी एआई का उपयोग करके अपने व्यापार मॉडल को नया रूप दे सकते हैं, यह देखना होगा।

फिर भी भारत 2025 से अपेक्षाकृत अच्छी स्थिति में उभरा। लेकिन अब तेल संकट और युद्ध से संबंधित आपूर्ति व्यवधानों ने पुनः धन को भारत से बाहर निकालना शुरू कर दिया है। रुपया भी कमजोर हुआ है। शुल्क का झटका कम हो गया है क्योंकि अब भारत संयुक्त राज्य अमेरिका में केवल 10 फीसदी आयात शुल्क देता है, जो अन्य देशों के समान है। लेकिन डॉनल्ड ट्रंप व्यापार समीक्षाएं करवा रहे हैं और चुनिंदा देशों पर फिर से शुल्क लगाने का इरादा रखते हैं। इस पर नजर रखनी होगी।

सुदूर वनांचल के सुशासन तिहार शिविर में पहुंचे उप मुख्यमंत्री शर्मा

वनांचल क्षेत्र का विकास हमारी प्राथमिकता

रायपुर। कबीरधाम जिले के सुदूर वनांचल एवं बैगा बाहुल्य क्षेत्र तरेगांव जंगल में आयोजित सुशासन तिहार के समाधान शिविर में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा शामिल हुए। उन्होंने शिविर में ग्रामीणों के साथ अपने सहज और चिर-परिचित अंदाज में सीधे संवाद किया, उनकी समस्याएं सुनीं और कई मामलों में मौके पर ही अधिकारियों को त्वरित निराकरण के निर्देश दिए।

उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि सुशासन तिहार शासन और जनता के बीच विश्वास एवं संवाद का माध्यम है। राज्य सरकार गांव-गांव पहुंचकर लोगों की समस्याओं को समझने और उनका समाधान करने का प्रयास कर रही है। उन्होंने अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से निर्माण कार्यों की गुणवत्ता की नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष श्री ईश्वरी साहू, जनपद अध्यक्ष श्रीमती बालका राम किंकर वर्मा, उपाध्यक्ष जिला पंचायत श्री कैलाश चंद्रवंशी, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष श्री विदेशी राम धुर्वे, उपाध्यक्ष जनपद पंचायत श्री नंद श्रीवास, जिला पंचायत सदस्य श्रीमती रूपा राजकुमार धुर्वे, श्री लोकचंद साहू, श्री मनीराम साहू, कलेक्टर श्री गोपाल वर्मा, जिला पंचायत सीईओ श्री अभिषेक अग्रवाल सहित जनप्रतिनिधि और विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि वनांचल क्षेत्रों का समुचित विकास और मूलभूत सुविधाओं की सहज पहुंच सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि 100 करोड़ रुपए की लागत वाली कुसुमघटा - बैजलपुर - राजानवांगांव समूह जल प्रदाय योजना से 66 गांवों तक पेयजल पहुंचाया जाएगा, जिससे क्षेत्र के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। इससे बड़ौदाखुर्द, बड़ौदाकला, भलपहारी, अचानकपुर, गंडईकला, गंडईखुर्द, कुसुमघटा, बोइरकछारा, खरहट्टा, भरेली, खड़ोदाकला, कारेसरा, सारंगपुर कला, राम्हेपुर, लोहझरी, सुकवापारा, जैताटोला, खैरबनाखुर्द, घोंघा, दियाबार, छपरी, खुर्सीपार, मंडलाटोला, मुड़ियापारा, मरियाटोला, बैहरसरी, सिल्हाटी, प्रभाटोला, बुधवारा, रहंगी, चंडालपुर, हरिनछपरा, मिनमिनिया मैदान, मोतिमपुर, रघुपारा, बद्दो, खिरसाली, लाटा, बाघुटोला, राजानवागांव, तिलाईभाट, बिसनपुरा, भलुचुवा, भीरा, खरिया, मुड़घुसरी मैदान, खड़ोदाखुर्द, कांदापारा, कामाडबरी, सिंघारी, बैजलपुर, अंधरीकछार, सिल्ली, बोदा 03, लबदा, अमेरा, सोंनतरा, मगरवाड़ा, बोरिया, कनपा, सिरमी, खंडसरा, छांटा, मड़मड़ा, कबराटोला, महली ग्राम शामिल है।

उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय द्वारा क्षीरपानी मध्यम परियोजना के नहर विस्तार के लिए 50 करोड़ रुपए की घोषणा की गई है। इस परियोजना से 19 गांवों के हजारों किसानों को सिंचाई सुविधा मिलेगी। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार गठन के बाद सबसे पहले गरीब परिवारों के पक्के मकान के सपने को पूरा करने की दिशा में कार्य किया गया।

सुशासन शिविरों में गूंजा संकल्प न बाल विवाह करेंगे, न होने देंगे

रायपुर। छत्तीसगढ राज्य के बीजापुर जिले को बाल विवाह मुक्त बनाने के लिए जिला प्रशासन, महिला एवं बाल विकास विभाग और पुलिस विभाग मिलकर व्यापक अभियान चला रहे हैं, जिसके तहत अब तक 25 ग्राम पंचायतें बाल विवाह मुक्त घोषित की जा चुकी हैं। कलेक्टर के नेतृत्व में बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के तहत जागरूकता, शपथ और कड़ी निगरानी के माध्यम से 2028-29 तक पूरी तरह से बाल विवाह मुक्त होने का लक्ष्य है।

कलेक्टर विश्वदीप के निर्देशन में बीजापुर जिले के सुशासन शिविरों में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा बाल विवाह मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान के तहत एक व्यापक जन-जागरूकता कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। इस पहल का उद्देश्य समाज के हर वर्ग को बाल विवाह के दुष्परिणामों और इससे जुड़े कड़े कानूनी प्रावधानों से अवगत कराना है।

शिविरों के दौरान ग्रामीणों, महिलाओं, युवाओं और अभिभावकों ने बाल विवाह जैसी कुप्रथा के विरुद्ध एकजुटता प्रदर्शित की। प्रतिभागियों ने सामूहिक रूप से यह संकल्प लिया कि वे न केवल अपने परिवारों को इस कुरीति से बचाएंगे, बल्कि समाज में भी इसे नहीं होने देंगे। ग्रामीणों ने यह भी वादा किया कि बाल विवाह की किसी भी संभावित घटना की सूचना वे तत्काल प्रशासन को प्रदान करेंगे। समाज में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए बड़े पैमाने पर हस्ताक्षर अभियान भी चलाया जा रहा है।विभागीय अधिकारियों ने शिविरों में उपस्थित लोगों को समझाया कि कम उम्र में विवाह बालिकाओं के विकास में सबसे बड़ी बाधा है। विवाह के कारण बेटियाँ शिक्षा से वंचित हो जाती हैं, जिससे उनके भविष्य के अवसर सीमित हो जाते हैं। कम उम्र में गर्भधारण मातृ एवं शिशु मृत्यु दर के जोखिम को बढ़ाता है।

महंगाई और ईंधन संकट, कांग्रेस का मोदी सरकार पर हमला

पेट्रोल और डीजल की कमी: प्रमोद दुबे

रायपुर। छत्तीसगढ़ में पेट्रोल और डीजल की पैनिक बाइंग की वजह से अफरा तफरी का माहौल है. इससे पहले पीएम मोदी ने देश वासियों से कम ईंधन खपत और सोने की खरीदी नहीं करने की अपील की थी. पीएम मोदी के इस बयान पर कांग्रेस हमलावर है. दुर्ग में कांग्रेस नेता प्रमोद दुबे ने मोदी सरकार पर हमला बोला. उन्होंने बीजेपी सरकार पर आम जनता को राहत देने में विफल रहने का आरोप लगाया.

कांग्रेस नेता प्रमोद दुबे ने आरोप लगाया कि पिछले दो महीनों से देश और प्रदेश की जनता पेट्रोल, डीजल और गैस संकट से जूझ रही है, लेकिन केंद्र सरकार समाधान निकालने के बजाय लोगों को कम उपयोग की सलाह दे रही है. प्रधानमंत्री किसानों को उर्वरक कम उपयोग करने, कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम अपनाने, महिलाओं को गैस और खाद्य तेल की खपत घटाने तथा लोगों को सोना और विदेश यात्रा से बचने की सलाह दे रहे हैं. यह आम जनता के जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा है.

छत्तीसगढ़ में लगभग 15 लाख मीट्रिक टन उर्वरक की जरूरत है, लेकिन समितियों तक पर्याप्त खाद नहीं पहुंच पा रही है. इससे खेती प्रभावित हो रही है और किसानों की लागत लगातार बढ़ रही है. मजदूर, छोटे व्यापारी और फेरी लगाने वाले लोग घर बैठकर रोजगार नहीं चला सकते. पेट्रोल-डीजल पर भारी टैक्स लगाकर जनता पर आर्थिक बोझ डाला गया है- प्रमोद दुबे, कांग्रेस नेता

प्रमोद दुबे ने आगे कहा कि सरगुजा सहित कई इलाकों में पेट्रोल-डीजल की कमी से लोग लंबी कतारों में खड़े होने को मजबूर हैं, जबकि कमर्शियल गैस की कमी से उद्योग प्रभावित हो रहे हैं. राहुल गांधी पहले ही सरकार से पेट्रोल, डीजल और खाद के भंडारण को बढ़ाने की चेतावनी दे चुके थे, लेकिन सरकार ने समय रहते कदम नहीं उठाए.

वाहन चालकों के हड़ताल के चलते कचरा कलेक्शन ठप

रायपुर ।छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में कचरा कलेक्शन व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। शहर के कई इलाकों में शुक्रवार को भी कचरा उठाने वाली गाड़ियां नहीं पहुंचीं, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल, कचरा कलेक्शन में लगे वाहन चालक और हेल्पर अपनी 18 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। ये सभी कर्मचारी रामेका ग्रुप के तहत काम करते हैं। हड़ताल के चलते राजधानी की सड़कों, कॉलोनियों और मोहल्लों में कचरे के ढेर लगने शुरू हो गए हैं, जिससे बदबू और गंदगी की समस्या बढ़ती जा रही है।

मामले को गंभीरता से लेते हुए समबिट मिश्रा ने रामकी कंपनी के रीजनल डायरेक्टर के साथ बैठक की। निगम कमिश्नर ने कहा कि विवाद कंपनी और कर्मचारियों के बीच का है, लेकिन नगर निगम लगातार समाधान निकालने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने उम्मीद जताई कि अगले एक-दो दिनों में स्थिति सामान्य हो सकती है। साथ ही शहरवासियों को हो रही परेशानियों के लिए खेद भी जताया। इधर, आकाश तिवारी ने पूरे मामले के लिए नगर निगम प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया है। उनका कहना है कि एक तरफ स्वच्छता सर्वेक्षण और सफाई व्यवस्था के बड़े-बड़े दावे किए जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ राजधानी में कचरा उठाव पूरी तरह ठप पड़ा है। उन्होंने आरोप लगाया कि निगम की लापरवाही का खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है और शहर में गंदगी तेजी से फैल रही है।

आशा-आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए स्वास्थ्य प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित

रायपुर । शकुंतला फाउंडेशन छत्तीसगढ़ और इटसा हॉस्पिटल के संयुक्त तत्वावधान में रायपुर में आशा कार्यकर्ताओं, मितानिन दीदियों और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का उद्देश्य ग्रामीण स्तर पर कार्यरत स्वास्थ्य कर्मियों को प्रशिक्षित और सशक्त बनाना था, ताकि गांवों में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर बनाया जा सके।

कार्यशाला के दौरान मितानिन दीदियों को बीपी, शुगर और हीमोग्लोबिन जांच जैसे आवश्यक स्वास्थ्य परीक्षणों की प्रायोगिक जानकारी दी गई। इसके साथ ही विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम ने मातृ स्वास्थ्य, नवजात शिशु देखभाल, क्षय रोग, कैंसर के शुरुआती लक्षण और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां साझा कीं।

विशेषज्ञों की टीम में डॉ. जयेश शर्मा, तुषार जैन, डॉ. अर्चना राय, डॉ. जील सेठ अग्रवाल, डॉ. गार्गी पांडे और डॉ. ईशिका जायसवाल शामिल रहे। कार्यशाला में प्रतिभागियों को आपात स्थिति से निपटने के लिए ष्टक्क्र (कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन) का लाइव डेमो भी दिया गया, ताकि हार्ट अटैक या बेहोशी जैसी परिस्थितियों में वे तुरंत सहायता प्रदान कर सकें।

इस अवसर पर सीईओ त्रिपाठी, शकुंतला फाउंडेशन की अध्यक्ष श्रीमती स्मिता सिंह, सीएसआर मैनेजर मुस्कान खंडेलवाल, पदमा घोष, नीता विश्वकर्मा, सौहदरा पठारी, उर्वशी कौशिक सहित अस्पताल के चिकित्सकगण उपस्थित रहे।

छत्तीसगढ़/राजधानी प्रमुख समाचार

मोदी राज में हर आदमी परेशान: त्रिवेदी

रायपुर। ईरान-इजरायल और अमेरिका के बीच जारी तनाव के मद्देनजर विश्व में पेट्रोल डीजल को लेकर संकट जैसे हालात हैं. भारत पर भी इसका असर पड़ रहा है. छत्तीसगढ़ में गुरुवार से पेट्रोल डीजल को लेकर पैनिक बाइंग की स्थिति है. ईंधन संकट के अलावा महंगाई और खाद की कमी भी पैदा हो रही है. इसे लेकर कांग्रेस ने धमतरी में मोदी सरकार पर हमला किया है. पेट्रोल डीजल को लेकर पीएम मोदी के अपील पर शैलेश नितिन त्रिवेदी ने करारा प्रहार किया है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा देशवासियों से डीजल-पेट्रोल, गैस और अन्य संसाधनों का कम उपयोग करने की अपील करना जनता के जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा है. उन्होंने कहा कि किसानों को उर्वरक कम उपयोग करने की सलाह दी जा रही है, जबकि पहले से ही खाद की कमी के कारण किसानों की उत्पादकता प्रभावित हो रही है और किसान आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं. शैलेश नितिन त्रिवेदी ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार रोजगार और महंगाई को नियंत्रित करने में विफल रही है. वर्क फ्रॉम होम की सलाह उन लोगों के लिए परेशानी खड़ी करेगी जो फील्ड में काम करते हैं, फेरी लगाकर सामान बेचते हैं या रोज कमाकर परिवार चलाते हैं. बढ़ती महंगाई ने आम आदमी की रसोई का बजट बिगाड़ दिया है।

मात्र 3 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी किसानो पर अत्याचार: शुक्ला

रायपुर। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि धान के समर्थन मूल्य में मात्र 3 प्रतिशत की वृद्धि ऊंट के मुंह में जीरा के समान है। केंद्र सरकार के द्वारा तय समर्थन मूल्य में मात्र 72 रू. की बढ़ोत्तरी किया है। कृषि की लागत दिनों दिन बढ़ रही है मजदूरी, खाद, बीज और कीटनाशकों की कीमत आसमान छू रही है। 2022 तक किसानों की आय दुगुना करने का वायदा जुमला साबित हुआ, किसानों को उम्मीद थी कि मोदी जी किसानों से 2014 में किए गए अपने सी-2 फार्मूले पर लागत से 50 प्रतिशत लाभ के साथ एमएसपी देने के वादे पर अमल करेंगे, लेकिन मोदी जी के तीसरे कार्यकाल में भी किसानों को निराशा ही हाथ लगी है। कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार के 10 साल में 147 प्रतिशत वृद्धि किया था। 14.7 प्रतिशत प्रतिवर्ष। मोदी सरकार (2014-2026) % 2014-15 में धान का एमएसपी 1,360-1,400 (सामान्य) था, जिसे बढ़ाकर 2026-27 के खरीफ मार्केटिंग सीजन के लिए 2,441 प्रति क्विंटल किया गया है। अर्थात मोदी के 12 साल में कुल वृद्धि 1081/- अर्थात 44.28 प्रतिशत, औसत मात्र 3.69 प्रतिशत प्रतिवर्ष। 2022 तक किसानों की आय दुगुनी करने और सी 2 फार्मूले से लागत पर 50 प्रतिशत लाभ देने का वादा करके सत्ता में आई मोदी सरकार ने एक बार फिर किसानों को धोखा दिया है।

डीजल संकट के चलते ट्रांसपोर्ट व्यवसाय चरमराई: ठाकुर

रायपुर। पेट्रोल डीजल संकट को लेकर सरकार के दावों को हवाहवाई बताते हुए प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि राजधानी से लेकर सरगुजा से लेकर बस्तर तक लगभग सभी जिलों में पेट्रोल डीजल को लेकर अफरा तफरी मची है। प्रदेश के 50 प्रतिशत पेट्रोल डीजल पंप ड्राई हो चुके है। डीजल नही मिलने के कारण हजारों ट्रक, छोटे, मंझोले मालवाहक वाहन,ट्रैक्टर खड़ी हो गई है खेती किसानी पर असर पड़ा है कंस्ट्रक्शन काम बंद हो चुके है। उद्योगों में भी प्रभाव दिख रहा है। होटल रेस्टोरेंट ढाबा बंद होने के कगार पर है। आने वाले दिनों में स्थिति और बिगड़ सकती है। बेरोजगारी बढ़ेगी,ड्राइवर कंडक्टर, हमला,मजदूर सब पर आर्थिक संकट पड़ेगा।सरकार पेट्रोल डीजल स्टॉक होने की आंकड़े जारी कर सब कुछ बेहतर होने का दावा कर रही है फिर पेट्रोल डीजल पम्प बंद क्यो हो रहे है? पेट्रोल डीजल के लिए पम्पों में लाईन क्यो लग रही है? जनता सरकार के दावों पर जनता भरोसा क्यो नही कर रही है? सरकार सभी पम्पो पर पेट्रोल डीजल की आपूर्ति सुनिश्चित क्यो नही कर रही है। प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि पेट्रोल डीजल की लाईन के लिए सरकार जिम्मेदार मुख्यमंत्री से लेकर सरकार के नुमाइंदे लगातार सोशल मीडिया में पेट्रोल डीजल बचाने की अपील कर रहे है।

गौधाम में सरकारी दावों की खुली पोल: वर्मा

रायपुर। गौधाम योजना को लेकर जनहित मामले में सुनवाई के दौरान उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा सरकार को लगाई गई फटकार पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा कि भाजपा सरकार की गौधाम, गौ-अभ्यारण बनाने की योजना सिर्फ हवा हवाई है, सरकार के दावे केवल कागजी है, जमीनी हकीकत अलग है। बिलासपुर जिले के लाखासार गौधाम की अव्यवस्था इस सरकार के गौ माता के खिलाफ किए जा रहे अत्याचार और महापाप का प्रमाण है। हाईकोर्ट के डिवीजन बैंच का यह सवाल की यदि व्यवस्था पूरी तरह दुरुस्त है तो फिर सड़कों पर आवारा पशुओं का जमावड़ा कम क्यों नहीं हो रहा है? भाजपा की सरकार ने पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार के द्वारा संचालित हजारों गोठानो को बिना वैकल्पिक व्यवस्था के बंद कर दिया, किसान खुली चराई से परेशान है, गाएं सड़कों पर बेमौत मारी जा रही है, राहगीर भी दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं। भाजपा सरकार एक तरफ यह मान रही है कि प्रदेश में 1 लाख 84 हजार 993 से अधिक छुट्टा घुमन्तु गौवंश पशुधन है, जिसका कोई मालिक नही है, दूसरी ओर ढाई साल में दिखावे के लिए गिनती के गौधाम बनाकर पशुधन के संरक्षण का दावा फर्जी है।

कार्यवाहक अध्यक्ष संगीता सिन्हा ने पदभार ग्रहण किया

रायपुर। महिला कांग्रेस की नवनियुक्त कार्यवाहक अध्यक्ष संगीता सिन्हा ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज, नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पूर्व मंत्री ताम्रध्वज साहू, राज्यसभा सांसद फूलोदेवी नेताम, सांसद ज्योत्सना महंत, महिला कांग्रेस की प्रभारी गुंजन सिंह, पूर्व मंत्री डा. शिवकुमार कुमार डहरिया, प्रभारी महामंत्री मलकीत सिंह गैदू, सहप्रभारी सुमिता मिश्रा की उपस्थिति में राजीव भवन में पदभार ग्रहण किया। इस अवसर पर प्रदेश भर में आई महिला कांग्रेस की पदाधिकारी बड़ी संख्या में बैठक में शामिल हुई। वरिष्ठ नेताओं की उपस्थिति में महिला कांग्रेस की कार्यवाहक अध्यक्ष संगीता सिन्हा ने फूलोदवी नेताम से पदभार ग्रहण किया। इस अवसर हुई बैठक को संबोधित करते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि संगठन को मजबूत करना, महिला आरक्षण बिल के मुद्दे पर लड़ना एवं सरकार के खिलाफ अन्य मुद्दे लड़ने में महिला कांग्रेस की महत्वपूर्ण भूमिका होनी चाहिए। आज गैस महंगी हो गई है, पेट्रोल, डीजल की कील्लत हो गयी है, घर का बजट बिगड़ चुका है। सिलेंडर नहीं मिल रहा है, हाहाकार मचा हुआ है। प्रदेश कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन भी किया।

सहकारिता विकास का आधुनिक ढांचा

सहकार से समृद्धि छत्तीसगढ़ में खुशहाली का नया मार्ग

छत्तीसगढ़ में सहकारिता आंदोलन राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, जो अब श्सहकार से समृद्धिश् के विजन के साथ विकास के एक नए और आधुनिक ढांचे में बदल रहा है। विष्णुदेव साय सरकार के नेतृत्व में सहकारी समितियों को मजबूत कर ग्रामीण विकास और किसान सशक्तिकरण को नई गति दी जा रही है। एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। सहकारिता के इस शाश्वत मंत्र को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के सहकार से समृद्धि विजन ने आज भारत के ग्रामीण और शहरी परिदृश्य में एक नई क्रांति का आधार बना दिया है। धान का कटोरा कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ में यह संकल्प आज एक आर्थिक संबल बनकर उभर रहा है। यह मात्र एक व्यवस्था नहीं, बल्कि अंत्योदय की वह भावना है जहाँ समाज का अंतिम व्यक्ति विकास की मुख्यधारा से जुड़कर आत्मनिर्भर बन रहा है।

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व और सहकारिता मंत्री श्री केदार कश्यप के कुशल मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ ने सहकारिता के दायरे को केवल कृषि तक सीमित न रखकर इसे व्यापार और सेवा क्षेत्र का प्रमुख स्तंभ बना दिया है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह की संकल्पनाओं को धरातल पर उतारते हुए राज्य के सहकारी ढांचे का अभूतपूर्व विस्तार किया गया है।

सहकारिता के माध्यम से खुशहाली सुनिश्चित करने हेतु निम्नलिखित प्रयास किए जा रहे हैं। 515 नवीन पैक्स (चॅॅ) का गठन सहकारी तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए राज्य में 515 नई प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों का गठन किया गया है। अब राज्य में कुल पैक्स समितियों की संख्या 2 हजार 573 हो गई है। ये समितियाँ अब केवल ऋण वितरण नहीं, बल्कि बहुउद्देश्यीय केंद्रों के रूप में कार्य कर रही हैं। इन केंद्रों के माध्यम से किसानों को खाद-बीज के साथ-साथ जन औषधि केंद्र, उर्वरक वितरण और कॉमन सर्विस सेंटर (ब्ब) जैसी सुविधाएं सीधे उनके गांव में मिल रही हैं। विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना के तहत किसान अब अपनी उपज का स्थानीय स्तर पर सुरक्षित भंडारण कर सकेंगे। इससे उन्हें फसल को कम दामों पर बेचने की मजबूरी से मुक्ति मिलेगी। महिला और युवा सशक्तिकरण को बढावा देने दुग्ध उत्पादन और मत्स्य पालन के क्षेत्र में सहकारी समितियों के माध्यम से युवाओं और महिलाओं को उद्यमिता से जोड़कर उनकी आय में वृद्धि की जा रही है। सहकारिता में स्व से ऊपर सर्व के कल्याण की भावना निहित है। छत्तीसगढ़ सरकार ने इस क्षेत्र में डिजिटलीकरण पर विशेष जोर दिया है। समितियों के कंप्यूटरीकरण से बिचौलियों की भूमिका समाप्त हुई है और हर लेनदेन पारदर्शी हुआ है। ई-मार्केटप्लेस के माध्यम से स्थानीय सहकारी उत्पादों को अब राष्ट्रीय और वैश्विक मंच प्राप्त हो रहा है।

157 साल पुराने बांके बिहारी मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव

रायपुर। राजधानी रायपुर के नयापारा स्थित ऐतिहासिक बांके बिहारी मंदिर में गुरुवार को भव्य प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव आयोजित हुआ। सुबह पुराने मंदिर से भगवान की शोभायात्रा निकाली गई, जिसमें सैकड़ों श्रद्धालु भजन-कीर्तन करते हुए झूमते और नाचते नजर आए। बता दें करीब 157 वर्ष पुराने इस मंदिर की स्थापना वर्ष 1870 में बैजू अग्रवाल ने की थी।

शोभा यात्रा एडवर्ड रोड, चिकनी मंदिर, कोतवाली चौक और सदर बाजार होते हुए पेठा लाइन स्थित नवनिर्मित मंदिर पहुंची। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच भगवान बांके बिहारी सहित 7 विग्रहों की विधिवत स्थापना की गई।

ट्रस्ट के अध्यक्ष अशोक अग्रवाल ने बताया कि मंदिर का जीर्णोद्वार एवं पुनर्निर्माण राजस्थानी वास्तुकला की शानदार कृति के रुप में किया गया है। भगवान बांकेबिहारी जी की पांच फीट ऊंची आदमकद प्रतिमा व अन्य देवी देवताओं की 3 फीट ऊंची प्रतिमाएं मकराना के सफेद मार्बल से जयपुर से बनाकर लाई गई है। पिछले दो वर्षों से सैकड़ों मजदूरों ने रात दिन परिश्रम कर इस भव्य मंदिर के निर्माण कार्य को पूरा किया है।

प्रतिष्ठित यज्ञाचार्य ओम प्रकाश जोशी के सानिध्य में भगवान बांके बिहारी, शिव पंचायतन, भवानी शंकर, दुर्गा मैया, बजरंगबली, लक्ष्मी माता, अग्रसेन माधवी देवता की प्रतिमाओं का जलाभिषेक और 56 प्रकार के द्रव्यों से अभिषेक किया गया।नेत्रोन्मीलन और श्रृंगार के बाद भगवान के दर्शन के लिए हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। मंदिर ट्रस्ट की ओर से भंडारे का आयोजन भी किया गया, जिसमें एक हजार से अधिक लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया।

आर.एन.आई.रजि. क्र. CHHHIN/2021/80529, स्वत्वाधिकारी, मुद्रक एवं प्रकाशक- शशांक शर्मा द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि., प्रेस कॉम्प्लेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) 492001 से मुद्रित एवं 29/1110, सेवती स्मृति, आजाद चौक, रायपुर (छ.ग.) 492001 से प्रकाशित। संपादक-शशांक शर्मा, मो. 94255-20531.